

C O N T E N T S

**Fifteenth Series, Vol.X, Fifth Session, 2010/1932 (Saka)
No.9, Thursday, August 05, 2010/Sravana 14, 1932(Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.161 to 163	2-39
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.164 to 180	40-88
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	89-419

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	420-421
MESSAGE FROM RAJYA SABHA	422
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES	423
Statements	
COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION	423
Reports	
STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS	423-424
Statements	
STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES	424
4th Report	
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE	424
18th Report	
STATEMENT BY MINISTER	425-426
Status of implementation	
of the recommendations contained in the 2nd Report of	
Standing Committee on Chemicals and	
Fertilizers pertaining to the Department of Fertilizers,	
Ministry of Chemicals and Fertilizers.	
Shri Srikant Jena	
CALLING ATTENTION TO MATTER OF	427-445
URGENT PUBLIC IMPORTANCE	
Situation arising out of recent Spurt in the	
Incidents of “Honour Killings” in the country and	
steps taken by the Government in this regard.	
Shri Gurudas Dasgupta	427
	429-434
Shri P. Chidambaram	427
	441-445

Shri Shailendra Kumar	435-436
Shri Gopinath Munde	437-438
Dr. Girija Vyas	438-440
INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010	446
STATEMENT RE: INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) ORDINANCE, 2010	446
Shri Ghulam Nabi Azad	
SUBMISSIONS BY MEMBERS	
(i) Re : Situation being faced by Urdu newspaper due to the negligent attitude of Government Institutions in the country	446-460
(ii) Re: Need to review the decision to accord environmental clearance to nuclear power plants to be set up in Chandrapur and Nagpur regions of Maharashtra	447-460
MATTER UNDER RULE 377	463-464
(i) Need to bring a Central legislation to regulate the service conditions of Nurses working in various parts of the country	
Shri K.C. Venugopal	463-464
(ii) Need to set up Centrally Sponsored Surveillance Committees with local MPs as members to monitor the programme of Centrally Sponsored Schemes	
Dr. Sanjay Singh	465
(iii) Need to introduce the Bill for categorization of Scheduled Castes into A,B,C and D groups in Andhra Pradesh	
Dr. Manda Jagannath	466
(iv) Need to take steps for revival of Damodar Valley Corporation in West Bengal	
Shri Adhir Chowdhury	467

- (v) Need to ensure the safety of Railway passengers in the country
Sh. P.T. Thomas 469
- (vi) Need to review the decision of Divisional Railway Manager, Dhanbad and re-open the various closed railway crossings and VIP parking at Dhanbad in Jharkhand
Shri Ravindra Kumar Pandey 470
- (vii) Need to accord permission for opium farming in Himachal Pradesh
Shri Virender Kashyap 471
- (viii) Need to provide special financial package to Bihar for the over all development of the State
Smt. Rama Devi 472
- (ix) Need to display banners & signages in Hindi language during Commonwealth Games
Shri Hukamdeo Narayan Yadav 473
- (x) Need to complete the construction of various roads in Madhya Pradesh which are pending with Ministry of Road Transport and Highways
Shri Ganesh Singh 474
- (xi) Need to direct the banks of the country to follow the guidelines issued by Reserve Bank of India in order to allow the students from minorities to open scholarship accounts in various banks
Shri Abdul Rahman 475
- (xii) Need to keep alive Subarnrekha Sanskar Project in the pendency list of the Central Water Commission
Shri Arjun Charan Sethi 476

- (xiii) Need to expedite approval of proposed transfer of State Government land of Nizam Bunglow premises to Defence (Army) in exchange of defence land for four laning of State Highway No. 60 in Maharashtra

Shri Chandrakant Khaire

477

**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY
GRANTS (GENERAL)-2010-2011**

478-568

Shri Yashwant Sinha	479-491
Dr. K.S. Rao	413-506
Shri Mangani Lal Mandal	507-509
Shri Bhishma Shankar Alias Kushal Tiwari	510-512
Shri T.K.S. Elangovan	513-514
Shri P. Karunakaran	515-519
Shri B. Mahtab	520-527
Shrimati Harsimrat Kaur Badal	528-534
Shri Anandrao Adsul	535
Shri S. Semmalai	536-538
Shri Shailendra Kumar	539-540
Shri Prabodh Panda	541-542
Shri S. Sivasami	543-545
Shri Virendra Kumar	546
Shri Naranbhai Kachhadia	547-548
Shri Prasanta Kumar Majumdar	549-551
Shri Ramashankar Rajbhar	552-553
Shri Ganesh Singh	554
Shri P.T. Thomas	555-556
Shri Ganeshrao Nagorao Dudhgaonkar	557
Shri P. Kumar	558-559
Shri Hansraj G. Ahir	560

Shri Pranab Mukherjee	562-568
APPROPRIATION (No. 4) BILL, 2010	570
Motion to Consider	570
Clauses 2 and 3	571
Motion to Pass	571
<u>ANNEXURE – I</u>	
Member-wise Index to Starred Questions	597
Member-wise Index to Unstarred Questions	598-602
<u>ANNEXURE – II</u>	
Ministry-wise Index to Starred Questions	603
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	604

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Shri Beni Prasad Verma

Dr. Girija Vyas

SECRETARY GENERAL

Shri P.D.T. Achary

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, August 05, 2010/Sravana 14, 1932(Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

... (*Interruptions*)

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): अध्यक्ष महोदया, दो दिनों से ज़ीरो आवर नहीं चल रहा है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए, प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे दो मिनट अपनी बात रखने के लिए चाहता हूँ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपको शून्य प्रहर में बोलने का समय देंगे। अभी प्रश्न काल चलने दीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। हम आपको शून्य प्रहर में बोलने का समय देंगे।

... (व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what I am saying.

(*Interruptions*) ... *

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

(*Interruptions*) ... *

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदया, सरकार ने ऊर्दू के अखबारों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अपनी बात शून्य प्रहर में उठाइए।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, on the Urdu paper issue, which the
senior Member of the House Hon. Mulayam Singh Yadavji has brought to the

* Not recorded.

notice of the House, the Government is very sensitive about it and is taking all possible steps for the promotion of Urdu newspapers.

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने उत्तर दे दिया है, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। आप लोग शून्य प्रहर में बोलिएगा, वह रिकार्ड में भी जाएगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शून्य प्रहर होगा। आप लोग बैठ जाइए। प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम आपकी बात को शून्य प्रहर में सुनेंगे। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न काल चलने दीजिए। आज शून्य प्रहर होगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, कहा गया था कि शून्य प्रहर लेंगे, लेकिन नहीं लिया गया

था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हुक्म देव नारायण यादव जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 161, डॉ. चरण दास महन्त।

* Not recorded.

(Q. No.161)

डॉ. चरण दास महन्त : अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा प्रश्न पहली बार प्रथम स्थान पर आया है और ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी पहली बार इसका जवाब देंगे। इसके लिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

महोदया, मैं मंत्री जी को मेरे प्रश्न का विस्तृत जवाब देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस विभाग की स्थापना वर्ष 2008 में होने के बाद भी, नाइपर, मोहाली के साथ ही साथ उसके 6 केन्द्रों के माध्यम से हमारे देश में दवाइयों के संवर्द्धन और विकास के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, रायबरेली और गुवाहटी केन्द्रों में काम हो रहे हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी हमारे देश की कम्पनियां पर्याप्त मात्रा में पेटेन्ट नहीं करवा पा रही हैं। इसके कारण हमारे देश की कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों द्वारा खरीद लिया जाता है, हस्तगत कर लिया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी सीधा और सरल प्रश्न है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, इतने केन्द्र स्थापित करने के बाद भी कि हम देश में दवाइयों के पेटेन्ट को तैयार नहीं कर पा रहे हैं और हमारी कम्पनियों को विदेशी कम्पनियां खाई जा रही हैं।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीकांत जेना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूँ, माननीय सदस्य ने जो दो बेसिक प्रश्न उठाए हैं कि इस देश में फार्मास्युटिकल सेक्टर में जितना रिसर्च होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है। जो विदेशी कम्पनियां हैं, उनके पेटेंटेड मेडीसन को हमें ज्यादा पैसे में खरीदना पड़ता है। उसी का इस्तेमाल देश में हो रहा है, जिसके कारण मेडीसन का प्राइस ज्यादा हो रहा है। मैं एक-दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ, जैसे कि नाइपर, मोहाली एक सेंट्रल एक्ट के तहत सन् 1998 में शुरू हुआ, उसके बाद मोहाली के अंदर सन् 2007-08 में और छः नाइपर खोले गए हैं, लेकिन बेसिकली उस पर ज्यादातर बच्चों को पढ़ाने के लिए मास्टर्स डिग्री, पीएचडी और पीएचडी के बाद इसमें ध्यान दिया जाता है, उसमें रिसर्च भी इन्वाल्व है। जहां तक मोहाली का सवाल है, मोहाली में जो मलेरिया और कालाजार के ऊपर रिसर्च हुआ है, उसमें हमें कुछ फायदा मिला है। Discovery of two new structural doses is patented as anti-Tuberculosis agents. It will take some time for application. Then, there is discovery of two promising molecules, each for therapeutic intervention in Tuberculosis and Malaria. It will take another seven to nine years for practical use. इसकी जो फोरमेलिटीस हैं, उन पर अभी टाइम लगेगा। मुझे आपको

यह बताने में खुशी है कि कम से कम मोहाली के अंदर जो रिसर्च हो रहा है और जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और उसके साथ जो रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता मिली है।

डॉ. चरण दास महन्त : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी मलेरिया का जिक्र किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश और विदेश में इतनी सारी कम्पनियां हैं, जो रिसर्च एवं डेवलपमेंट कर रही हैं। हमारे भारत और अफ्रीका जैसे अनेक देशों में हजारों मौतें सिर्फ मलेरिया से होती हैं। हम लोगों ने इतनी सारी दवाइयां बना लीं, मगर मच्छर को मारने की दवाई अभी तक नहीं बन पाई, न भारत में बन पाई और न ही विदेशों में बन पाई।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियां जो दवाइयां बनाती हैं, जानवरों पर उसका प्रयोग करने के बाद हमारे देश में यहां के मरीजों पर उसका प्रयोग किया जाता है। इस देश में लगभग दो सौ ऐसे सेंटर हैं, छत्तीसगढ़, भोपाल और इन्दौर में भी हैं। हरेक प्रदेश में इसके सेंटर हैं, जहां पर विदेशी कम्पनियों की दवाई का ट्रायल मरीजों पर किया जाता है और इस ट्रायल में अनेकों मरीजों की मौत भी हो जाती है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने ऐसी कौन सी व्यवस्था की है कि विदेशी कम्पनियों की दवाई के ट्रायल के दौरान होने वाली मौतों पर उसके परिवार को पर्याप्त मुआवजा मिल सके? क्या दवाइयों के ट्रायल करने से पहले मरीजों से पूछा जाता है कि यह नई विदेशी दवाई है, इसका हम आप पर ट्रायल करना चाहते हैं? आप जिन्दा रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा उससे पहले कुछ लिखावाया जाता है। इस पर आने वाले दिनों में केन्द्र सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं?

SHRI SRIKANT JENA: There are two stages – one is laboratory test trials and the other stage is clinical trials at the field. Once the laboratory trial is over, industry takes over and takes it to clinical trial. Clinical trial is being done by hospitals and different companies. This is being monitored by the Ministry of Health.

DR. M. THAMBIDURAI : Thank you, Madam.

As the hon. Minister said, we are manufacturing more medicines, based on the formulae of foreign countries. At the same time, we are also importing various diseases from foreign countries like swine flu and others. Keeping this in view, we have to concentrate more on research and development, to produce or manufacture more medicines in India according to the conditions suitable to India. For that, as

the hon. Minister said, research and development is very essential to maintain the standard of drugs to treat the patients.

Apart from that, we have come across many instances in India, especially in Tamil Nadu where the pharmaceutical companies selling even the expired medicines. Due to the circulation of the expired medicines in Tamil Nadu, many people got affected. I want to know from the Minister through you, Madam, whether the Central Government knows what is happening in Tamil Nadu about the expired medicines. What are the steps taken by the Government to stop them from selling this kind of medicine and also will the Government take severe action against the culprits who are selling this kind of medicine?

SHRI SRIKANT JENA: Though this is not concerning the main Question, I would say that the 'expired medicines' are the subject of drug inspectors at the State level. They are supposed to get them checked. ... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI: They have to maintain the standards of medicines. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Let him reply.

... (*Interruptions*)

DR. M. THAMBIDURAI : They are circulating sub-standard medicines. ... (*Interruptions*)

SHRI SRIKANT JENA: There are two questions – one is the standard medicine and the other is expired medicine. The standard medicine can expire, if the date got expired. If any shopkeeper is selling such medicines, they are liable for punishment. So, if he has any complaint, he could write to the Controller of Drugs, who will immediately take action. ... (*Interruptions*)

SHRI T.R. BAALU: He is wasting the time of the House unnecessarily. ... (*Interruptions*)

SHRI T.K.S. ELANGO VAN: The State Government has already taken action. He is unnecessarily asking this question. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Okay, sit down. He has put the question and the Minister answered. It is over now. Please sit down. Nothing is going on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछ लिया। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया। आप लोग बीच में क्यों बोल रहे हैं। श्री टी.आर. बालू जी, आप कृपया बैठ जाइए। आगे चलने दीजिए। हो गया।

...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने वे रिपोर्ट्स देखी हैं, जिनमें क्लीनिकल ट्रायल्स के लिए मरीजों को लाने के वास्ते डॉक्टरों को कुछ पैसा दिया जाता है? ऐसी पुस्तकें क्लीनिकल ट्रायल्स के बारे में छपी हैं। इसे कहते हैं - 'under the belly of multinationals clinical trials'. क्योंकि ये किसी भी आदमी को ले जाते हैं। उस पर ट्रायल करते हैं और उसे पता नहीं होता कि उसके ऊपर क्या किया जा रहा है। उसे ज्ञान नहीं है कि उसके ऊपर किसी दवाई का ट्रायल किया जा रहा है। वह ऐसे काम के लिए क्यों जाएगा, लेकिन उसे लालच देकर ले जाया जाता है। क्या आपने इसकी रिपोर्ट्स देखी हैं ? दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि यह भारत में ही क्यों किया जाता है?

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्य, कृपया एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : महोदया, यहां ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि यहां यह सस्ता है और वहां यह बहुत महंगा है। क्या भारत के मरीजों की जान सस्ती है, क्या वे गिनी-पिग बनने के लिए हैं? क्या भारत सरकार ने इस मामले में कोई विधिक व्यवस्था की है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हैं और यदि नहीं, तो क्या वे अब करेंगे और इस पर ध्यान देंगे कि भारत में ये ट्रायल्स लोगों को गिनी-पिग बनाने के लिए न हों और डॉक्टरों इसके अन्दर भ्रष्टाचार न कर सकें ?

SHRI SRIKANT JENA: The hon. Member, Dr. Joshi is well experienced in the episode of clinical trials. I do not know why he is asking; but Dr. Joshi knows it; there is a procedure.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : No clinical trial has been done on me!

SHRI SRIKANT JENA: There is a procedure. Any company which wants to go for a clinical trial, has to follow the procedure. The permission of the Government

* Not recorded.

of India has to be obtained; though my Department is not monitoring that and it is concerning the Health Ministry. But there is a procedure which has to be followed, about which he is well aware of.

DR. MURLI MANOHAR JOSHI : But are you sure that the procedure is well-maintained and well-observed?

डॉ. ज्योति मिर्धा : महोदया, अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही थी। मोलीक्यूल्स ऐसे नहीं होते कि एक लैबोरेट्री खोल दी और वहां चार साइंटिस्ट बैठा दिए। वे नौ से पांच बजे तक के लिए वहां आते हैं और वे कोई मोलीक्यूल्स ढूंढने निकले हुए हैं। ये जनरली इंसीडेन्टल फाइन्डिंग्स होती हैं। मैं मिनिस्टर साहब की बात से एग्री करती हूं, जैसा वह कह रहे हैं कि इस फील्ड में पैसा तो देना ही पड़ता है, पर क्या वह पैसा सही जगह पर टार्गेट हो रहा है? जैसे किसी फार्मास्युटिकल कंपनी ने अपना प्रॉफिट एक साल के लिए सौ करोड़ रुपए दिखाया। अगले साल उन्होंने आर एंड डी के ऊपर दस करोड़ रुपए खर्च किए, तो उनको कायदे से नब्बे करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स देना चाहिए, लेकिन इनके डिपार्टमेंट ने एक अनुशंसा कर रखी है कि आर एंड डी डिपार्टमेंट को पैसे की ज्यादा जरूरत है, इसलिए इनको इंसेटिवाइज करो और किसी तरह से कन्सैशन दो। इसलिए ये लोग बजाय नब्बे करोड़ रुपए के सिर्फ पच्चासी करोड़ रुपए के ऊपर टैक्स देते हैं। नतीजा आज हम सब के सामने हैं। आप मोलीक्यूल के बारे कह रहे थे। हिंदुस्तान में आज तक एक भी ऐसा मोलीक्यूल नहीं बना, जिसको हम मार्केट कर पाए हों और जिसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मान्यता दी जाती हो या हमारा पेटेंट कोई मानने के लिए तैयार हो, ऐसा एक भी मोलीक्यूल नहीं है। जो कन्सैशन्स दिए गए, उनका असली नतीजा यह हुआ कि जो हमारी फार्मास्युटिकल कंपनीज थी, जिन्होंने टैक्स में पैसा बचाया, उन्होंने बेहतर रिटर्न्स और डिविडेन्ड्स दिए। शेयर मार्केट के अंदर उनकी झूठी-सच्ची वैल्यू ऊपर आयी और तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब अच्छा माहौल है और हमारी कीमत बढ़ गयी है। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ता कह रहे थे कि उन्होंने खरीद ली। उन्होंने खरीदी नहीं है, जब तक कोई बिकने के लिए तैयार नहीं है, उसे कोई खरीद नहीं सकता है।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

डॉ. ज्योति मिर्धा : उन कंपनीज ने चूज किया कि अब बाजार में हमारी कीमत अच्छी है और हम बिकने के लिए तैयार हैं, तब उनको बाहर की कंपनीज ने खरीद लिया। रिजल्ट यह हुआ कि मोलीक्यूल एक भी नहीं बना और हम बिकने के लिए तैयार हैं, इसलिए बाहर की कंपनीज हमें खरीदने के लिए तैयार हो गयीं। यह टार्गेटेड एप्रोच रखकर मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप इस पर इंसेटिवाइज करेंगे कि अगर

आप कुछ ढूँढते हैं तो हम आपको इन्सॅटिवाइज करेंगे, वरना सिर्फ इस बात के लिए नहीं इन्सॅटिक्स नहीं देंगे कि आप फार्मास्युटिकल कंपनीज के अंदर रिसर्च एंड डिवलपमेंट करें?

SHRI SRIKANT JENA: I fully agree with the hon. Member. In the name of research the pharmaceutical companies in India are yet to come up with any new molecule. They do take the benefits and the Government of India is also encouraging them to go for research and development. But the big companies are yet to find out any new molecule. We are dependent on patented medicines of foreign companies which are spending a lot of money on research. Fortunately, many of the patented medicines are now off-patented. India is having a huge market of pharmaceuticals. Just because there is a branding there is a market. It is a different question and since the hon. Member has asked it, I would say that this needs to be very deeply analysed. The Department of Pharmaceuticals is also coordinating with other departments in the field of research. The real benefit should go to the scientists who are really engaged in the research and development work. I fully share the hon. Member's views.

श्री लालू प्रसाद : मैडम, जितनी दवा बन रही हैं और पेटेंट हो रही हैं, उतना ही रोग भी अपना स्वरूप बदल रहे हैं और यह सब बेकार होता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ जिससे देश को स्पष्ट रूप से मालूम हो जाए कि क्या स्व-मूत्रपान और गौ-मूत्रपान के लिए आपने कोई अनुसंधान कराया है या इस संबंध में पेटेंट करायेंगे, इसका क्या स्टेटस है, क्योंकि बहुत से लोग स्व-मूत्रपान करते हैं? इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताइए कि इस संदर्भ में क्या हो रहा है?

SHRI SRIKANT JENA: Lalu ji has raised a very pertinent question. There is a debate not only in India but throughout the world as to whether any alternative medicine or alternative action can be fruitful. This is being debated even in the USA and there are many takers of this view. In India we will certainly look into it.

(Q. No. 162)

श्री भूपेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि फर्टिलाइजर की कुल मिलाकर आठ यूनिट्स पिछले वर्षों में बंद हो गईं। आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर की बहुत कमी है और हमें बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। आपने यह भी स्वीकार किया है कि आठ यूनिट्स बंद होने से लगभग 23 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन प्रभावित हुआ है। हमारे देश में यूरिया की कुल डिमांड 280 लाख मीट्रिक टन है। हमारे देश का अपना उत्पादन लगभग 211 लाख मीट्रिक टन है। करीब 20 लाख मीट्रिक टन आप आयात कर रहे हैं। हमारे देश में फर्टिलाइजर की काफी कमी है। हम एक तरफ आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश की फर्टिलाइजर यूनिट्स बंद होती जा रही हैं। हमारे देश के अंदर फर्टिलाइजर की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो, हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। आपने कहा है कि नैचुरल गैस से जो फर्टिलाइजर बनता है, वह काफी सस्ता होता है। हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में नैचुरल गैस है। फिर क्या कारण है कि हमें पूरी तरह से आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है। हमारी यूनिट्स लगातार बंद हो रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में किसानों को पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर मिले, ठीक कीमत पर मिले, मिलावटी न मिले और जो इकाइयां बंद हो गई हैं, वे प्रारंभ हों या जहां नैचुरल गैस उपलब्ध है, वहां फर्टिलाइजर के कारखाने लगाकर देश में उत्पादन किया जाए, इस संबंध में सरकार की क्या योजना और नीति है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): Madam, it is true that we are dependent on import basically for phosphatic fertiliser and potashic fertiliser. But so far as urea is concerned, the total requirement of urea is about 280 lakh metric tonnes in the country annually and our production is about 211 lakh metric tonnes. From Oman-India Fertiliser Company, we are getting at proper rate about 20 lakh metric tonnes. So, we are short of nearly 50 lakh metric tonnes of urea. We have closed down eight units. Practically, we had closed down six units in 2002 because those units were not functioning properly and the loss was huge. The gas is the real issue and if the gas linkage is there, these units can be revived. In 2007, the UPA Government decided that these closed units need to be revived and the mandate was given. Ultimately, the Cabinet took a decision in 2008 and accordingly, the Empowered Committee of Secretaries finalised a road map. I am

sure in another eight to nine months, these closed units will be revived and the situation on the urea front will be comfortable in a maximum of two-three years time.

श्री भूपेन्द्र सिंह : मंत्री जी, मेरा सागर लोक सभा क्षेत्र बुंदेलखंड के हिस्से में आता है। बुंदेलखंड के अंदर रॉक फास्फेट, पोटेशियम, रॉक स्टोन आदि ऐसे अनेक मिनरल पाए जाते हैं। बुंदेलखंड में पर्टीकुलरली सायगढ़ का रॉक फास्फेट साउथ की कम्पनियों में जाता है और वहां उससे यूरिया का निर्माण किया जाता है। बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब हमारे यहां से कच्चा माल साउथ में जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी काफी महंगा है, तो क्या भारत सरकार बुंदेलखंड के पिछड़े हुए क्षेत्र सायगढ़ और बाकी हिस्सों में जो मिनरल हैं, उनका सर्वे कराने का काम करेगी जिससे फर्टीलाइजर बन सकता है? वर्तमान में रॉक फास्फेट की सप्लाई साउथ में हो रही है। क्या भारत सरकार वहां फर्टीलाइजर का कारखाना लगाने पर विचार करेगी?

SHRI SRIKANT JENA: The first priority of the Government is to revive those sick units which have been closed. Secondly, a new investment policy is being worked out. I am sure, in a month's time the new investment policy will come up. It is dependent upon the availability of gas and Bundelkhand is one of the priority areas of the Government and I had a discussion with my colleague Shri Jain and he is also equally keen that this unit should come up there. It is because the gas line passes through Bundelkhand and therefore Bundelkhand is a priority area. But the question here is the availability of land. Unless the State Government gives us land it is very difficult to come up with this kind of a thing. So, firstly, there should be availability of gas and secondly, the land has to be provided by the State Government. If these two things are available, then certainly Bundelkhand will get certain priority once the new investment policy comes up.

अध्यक्ष महोदया : भूपेन्द्र सिंह जी, आपके प्रश्न का जवाब आ गया है, इसलिए अब आप उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : भूपेन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइये और पूर्णमासी राम जी को प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पूर्णमासी राम : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकारी खाद कारखानों को कितनी गैस आवंटित की जाती है और प्राइवेट उद्योगों को कितनी गैस आवंटित की जाती है? माननीय मंत्री जी यह भी बतायें कि अभी वर्तमान में हैदराबाद से कितनी गैस मिली है? मुझे ऐसा पता चला है कि 86 एमएमयू केजी गैस बेसिन मिला है। सभी फर्टिलाइजर फैक्टरियों को चलाने के लिए 17 एमएमयू गैस की जरूरत है। सरकारी खाद कारखानों को 0.17 एमएमयू ही गैस दी जाती है और शेष गैस प्राइवेट उद्योगों, प्राइवेट लोगों को दी जाती है। इस तरह सरकारी खाद फैक्टरियों को बंद करके रखा गया है और जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा की गयी है जिससे किसान महंगे दाम पर रद्दी खाद खरीदें।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यदि गैस मिली है, तो कितने दिनों में आप इन आठ खाद फैक्टरियों को चालू कराकर कैसे उनको गैस उपबल्ल करायेंगे?

SHRI SRIKANT JENA: The hon. Member is actually advocating the cause of the Ministry of Fertilizer before the Ministry of Petroleum. Gas is available and the priority has to be given to the fertilizer plants that have been prioritized by the Cabinet itself. Availability of Gas is a major component for revival of the fertilizer plants. Therefore, we have been approaching them and there is a decision. Once the new investment policy is on track, then we will be able to do it...

(Interruptions) अध्यक्ष महोदया, मैंने बताया है कि इस बारे में फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का प्रपोजल पड़ा हुआ है। ...*(व्यवधान)*

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

श्री श्रीकांत जेना: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है कि क्या फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री ने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से गैस मांगी है, तो हमने उनसे गैस मांगी है। उसे कैबिनेट ने प्राइवटाइज किया है। उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट पालिसी तय हो जायेगी, कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि जब फर्टिलाइजर प्लांट आ जायेगा तब गैस जरूर दी जायेगी। लेकिन कितने प्राइज में दी जायेगी, यह अभी तक डिटरमिन नहीं हुआ है। इस बारे में अभी बातचीत चल रही है। मुझे लगता है कि इस बारे में तुरंत फैसला हो जायेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : पूर्णमासी राम जी, आपके प्रश्न का जवाब आ गया है।

* Not recorded.

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह विवरण दिया है कि कौन-कौन सी यूनिट्स, खाद कारखाने बंद हैं। फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पांच यूनिट्स को बंद होना बताया गया है जिसमें से कोरबा यूनिट कभी कमिशन ही नहीं हुई। इसी तरह सिंदरी, तलचर और रामागुंडम के बारे में बताया कि इनके रिवाइवल के प्रपोजल्स आ चुके हैं। गोरखपुर अकेला पूर्वांचल का सबसे पुराना खाद कारखाना है, जो पूर्वांचल और बिहार के लिए खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करता था, के रिवाइवल के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मेरा कहना है कि पूर्वांचल में खाद की कमी को देखते हुए उसे पूरा करने के लिए, इस कारखाने के बंद होने से वहां रोजगार के जो साधन समाप्त हो गए हैं, उनको दुबारा रिवाइव करने के लिए एचबीजे पाइपलाइन, जगदीशपुर में खाद कारखाना है, वहां एचबीजे पाइपलाइन से गैस आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। गोरखपुर कारखाने का रिवाइवल किया जाना चाहिए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार शीघ्र निर्णय लेकर गोरखपुर में कारखाना पुनः प्रारंभ कराएगी? अगर हाँ, तो इसे जल्दी से जल्दी कब तक प्रारंभ कराएंगे?

श्री श्रीकांत जेना: महोदया, जहां तक गोरखपुर का सवाल है, वह भी रिवाइवल के पैकेज में रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में लिया गया है। जिन छः यूनिट्स के रिवाइवल का प्रपोजल है, उनमें से पांच यूनिट्स जहां पर हैं, वहां की राज्य सरकारों द्वारा जो लैण्ड क्लियरेंस देनी थी, वह मिल चुकी है। केवल गोरखपुर के बारे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी तक यह क्लियरेंस नहीं दिया है, जिसके कारण इसमें आगे बढ़ने में प्रॉब्लम है।...(व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA: Madam, eight urea manufacturing units of the Fertiliser Corporation of India and Hindustan Fertilizers Corporation were closed down in 2002. We are told that the production at that point of time was more than the demand. But after eight years, we have come to a situation that there is a deficit of more than 50 lakh tones of urea today. In 2007, the Government of India decided to revive these closed fertilizer units and a Consortium has been formed with GAIL, Coal India Limited, SAIL and Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited. The three urea manufacturing units were coal based units. The Sindri Fertilisers was the first public sector undertaking in our country which was inaugurated in 1952 and then came Talcher and Ramagundam units.

Will the Government consider reviving these three units as coal based units as we have abundant reserves of coal which can be utilized? As regards revival of Durgapur unit of Hindustan Fertilizers Limited, coal-bed methane is available in that area. That can be utilized to revive the Durgapur unit of the Hindustan Fertilisers Limited. Will the Government consider these two proposals?

SHRI SRIKANT JENA: Madam, to revive these closed units, there are two routes. The Empowered Committee of Secretaries and the Government are considering the two routes. One route is, wherever coal is available like the Talcher unit, the coal gasification route is the best route and that has been recommended by the Consortium of GAIL, Coal India Limited and Rashtriya Chemicals and Fertilisers. They have agreed that coal gasification will be the best route. Wherever coal is available, this is cheaper, the technology is better, and therefore, they are considering the coal gasification route.

The other route is the gas route where the pipeline goes along the side the closed units. The gas can be tapped and it can be made viable. Therefore, both options are being considered. There are two options. One is nomination basis and it has to be seen whether the public sector undertakings consortium can take over one or two units. The other option is to go in for the revenue sharing model like how three or four airports have gone in for this model. This model is also being worked out. The revenue sharing model is also being considered and I am sure within another six to seven months, these two models will become optional and the Cabinet will take a final view on this matter.

श्री आर.के.सिंह पटेल : अध्यक्ष जी, वर्तमान समय में पूरे देश में जब यूरिया की आवश्यकता होती है तब डीएपी खाद किसानों को दी जाती है। इसी तरह जब किसानों को डीएपी की आवश्यकता होती है, तो उस समय यूरिया से गोदाम भरे होते हैं। मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, उनमें बताया गया है कि हमारे देश में इतना उत्पादन होता है और इतना हम आयात करते हैं। किसान जब बुवाई करता है, उस समय उसे डीएपी की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, रबी का मौसम है और किसान दिन भर अपने खेतों में बुवाई कर रहा है। लेकिन जब वह डीएपी लेने दुकान पर जाता है तो उसे घंटों लाइन में खड़ा

होकर केवल एक बोरी डीएपी मिलती है, जबकि उसकी आवश्यकता पांच बोरी की होती है। इससे वह अपने खेत के एक कोने में ही बुवाई कर पाता है, क्योंकि उसे एक बोरी ही डीएपी खाद मिलती है और बाकी खेत सूख जाता है। मेरा मंत्री जी से यह कहना है कि किसान को समय पर खाद पर्याप्त मात्रा में दी जाए और जिस खाद की जरूरत है, वह दी जाए, दूसरी खाद से गोदामों को न भरा जाए। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह ऐसा कदम उठाएंगे, जिससे किसानों को समय पर, सही मात्रा में और सही खाद मिल सके?

श्री श्रीकांत जेना : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि किसानों को फर्टिलाइजर समय पर मिलना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा जिस खाद की और जितनी मांग हमें बताई जाती है, हम उन्हें देते हैं। हमने इस महीने में डीएपी पहुंचा दी है और वह वितरित भी हो गई है, लेकिन राज्य सरकार अगर किसानों को समय पर न वितरित कर पाए तो उसमें फिर भला हम क्या कर पाएंगे...(व्यवधान)

श्री रेवती रमन सिंह : उत्तर प्रदेश सरकार ने कितनी मांग की थी और कितनी खाद उसे मिली है?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, उन्हें उत्तर देने दें। इस तरह से बीच में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना: आप लोग पहले मेरी बात सुन लें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाएं, आप क्यों खड़े हो रहे हैं। मंत्री जी को उत्तर देने दें।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

*(Interruptions) ... **

SHRI SRIKANT JENA: Let me emphasise one thing. I have written to all hon. Members of Parliament explaining the availability of DAP, MOP, urea and fertilizer in their respective districts and States. I have sent this across to every hon. Member. If you require it, I will send it again explaining as to what was the

* Not recorded.

requirement and how much has been sent to you. Let me also assure the House that there is absolutely no problem as far as the availability of fertilizer is concerned. ... (*Interruptions*) Let me explain. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, I can see that most of the Members – in fact the entire House – are very worried about this issue. I have a very long list of those Members who want to ask supplementary questions on this issue. It may not be possible to accommodate all of them in the Question Hour. So, if you think proper and if you send a notice, we will have an Half-an-Hour discussion on this issue.

MADAM SPEAKER: Q. 163 - Shri P.T. Thomas

(Q.No. 163)

SHRI P.T. THOMAS: Madam, thank you very much for giving me an opportunity.

I would like to point out here that the answer is a repetition. Long ago on 25th February, 2010 the same question was there and the answer was also the same.

Regarding the upgradation of Calicut and Trivandrum Airports and based on the part (d) of the question, I would like to say that tens and thousands of Keralities are traveling from Calicut, Trivandrum and Cochin. In Calicut, Haj pilgrims are also traveling in large numbers, but the facilities provided are very poor.

Madam in the answer given on 25th February, 2010, it was mentioned that the Engineered Material Arresting System will be commissioned soon in Calicut.

Regarding Trivandrum it was mentioned in the answer that the part parallel taxi track work would be completed. So, the same answer is repeated. My humble request to the hon. Minister is that when it will be completed and when it will be open to public. That is my question.

SHRI PRAFUL PATEL: The hon. Member is agitated as to why the reply is the same. Probably, the question was very similar and, therefore, the reply tends to be very similar. ... (*Interruptions*) I do not think that it would be fair for my friends from Kerala to say that there is no change at the airports in Kerala. If they just flash back for a few years, three-four years ago, and what they see today, I am sure, they will in all honesty appreciate that there has been a large construction activity taking place in most of the airports.

As far as Thiruvananthapuram Airport is concerned, just for the information of all the hon. Members, I would like to say that the international terminal is now almost complete and is to be inaugurated very shortly. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL : Please let us know the time. ... (*Interruptions*)

SHRI PRAFUL PATEL: Please do not ask questions which are not relevant to the main question. I think Rs. 290 crore approximately has been spent on the Trivandrum Airport Terminal and much more expenditure also has been incurred on various other facilities out there and so is the case with Calicut. Also, the Government of India has approved the construction of a new Greenfield Airport in Kunnur. But, unfortunately, after the Government of India has given in-principle approval, not much progress has been made, as I have been told at the local level. So, at the end of the day, if you look at the kind of expenditure and the kind of facilities which have been upgraded, I think it is an on-going process. If there is anything more specific which the hon. Member wants like the Haj terminal or the Haj facilities which he has mentioned, I think if there is any issue which you feel needs attention or improvement, we are most certainly ready to consider it and do the needful.

SHRI P.T. THOMAS : Madam in Kerala the cancellation of the flights of Air India is the order of the day. So, there the things are like that. Even though the Trivandrum International Terminal is completed long back and two or three dates are fixed for its inauguration, but, unfortunately, it is getting delayed and there is a postponement. So, the uncertainty is there. So, what is the reason for this delay and postponement? Will the hon. Minister answer my simple question?

SHRI PRAFUL PATEL: Madam Speaker, I would, in fact, like to say that the Terminal has just been completed. I would, in fact, say that the finishing stages are still going on. I would further say that the inauguration will take place in the coming few weeks.

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने पूरे देश में एयरपोर्ट आधुनिकीकरण का काम शुरू करवाया है। दिल्ली एयरपोर्ट में टी-3 में अभी भी बहुत पैसंजरों को दिक्कत हो रही है। इस दिक्कत के बारे में अखबारों में छपता है। हवाई जहाज आधे घंटे या बीस मिनट तक आसमान में उड़ता रहता है क्योंकि लैंडिंग में दिक्कत होती है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये दिक्कतें कब दूर की जाएंगी? इसके साथ यह भी जानना चाहता हूँ कि मुंबई में पुराना एयरपोर्ट शिवाजी टर्मिनल कब तक तैयार किया जाएगा? आप जानते

हैं कि इलाहाबाद में मंगरौली एयरपोर्ट इतना पुराना है और आपने इसे आधुनिकीकरण में लिया नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में कारगो हब भी नहीं बनाया, इसके बनने से व्यापार बढ़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि आज आप घोषणा कर दें की ये दिक्कतें कब दूर होंगी? इलाहाबाद को आधुनिकीकरण में कब लेंगे और इलाहाबाद में जेट कब से चलाएंगे?

श्री प्रफुल पटेल: महोदया, मैं अपने जवाब की शुरुआत इलाहाबाद से ही करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी रुचि इलाहाबाद में ही है। आपको स्मरण होगा कि आपके ही आग्रह पर इलाहाबाद में हवाई सेवाएं, जो बहुत वर्षों तक निलंबित थी, उन्हें शुरू करने का कार्य किया गया था। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि वहां और हवाई जहाज या बड़े हवाई जहाज चलाने के लिए सरकार की ओर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आपको इस संबंध में बहुत जल्द कोई खुशखबरी दे पाएंगे।

जहां तक हवाई अड्डे की बात है, एयरफोर्स की वजह से अपग्रेडेशन की बात है और टर्मिनल का जहां तक संबंध है, हमारी जहां तक सीमा है, हम जरूर पर्याप्त उपाय और सुधार करने के लिए आश्वस्त करते हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाओं के बारे में एयरफोर्स से भी बातचीत करेंगे। जहां तक दिल्ली और अन्य जगह के बारे में कन्जेशन की बात की है। सभी माननीय सदस्य हवाई अड्डों से गुजरते हैं और आप जानते हैं और कि यात्रियों की संख्या पहले से ज्यादा हो चुकी है, हवाई सेवाएं बढ़ चुकी हैं इसलिए पीक समय पर दिल्ली जैसे हवाई अड्डे पर थोड़ा बहुत ट्रेफिक कन्जेशन होता है। कम्युनिकेशन, एटीसी और बहुत सी सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि पहले से इसमें सुधार जरूर हुआ है और आगे भी हमारे प्रयास सुधार करने के लिए जारी हैं।

श्रीमती दर्शना जरदोश : महोदया, मैं सूरत को रिप्रेजेंट करती हूँ। अर्बन डेवलपमेंट बोर्ड के अनुसार सूरत महानगर एशिया की फास्टेस्ट सिटी में आता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि क्या सूरत को आधुनिकीकरण के साथ देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ने की कोई योजना बनाई गई है? प्रधानमंत्री के सूरत के आगमन से आधुनिकीकरण का प्रश्न नहीं है लेकिन मुंबई के सबसे पास शहर होने के कारण मुंबई का भार कम करने हेतु आयोजन में कोई प्लानिंग की है?



श्री प्रफुल पटेल : माननीय सदस्या बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि सूरत का हवाई अड्डा पुराना था, बंद था, उसके पश्चात हम ही ने इस हवाई अड्डे में विशेष रुचि लेकर उसे आधुनिक और बड़े हवाई जहाजों के अनुरूप बनाया, वहां अच्छा टर्मिनल बना, रनवे अपग्रेड हुआ। वहां पर 24x7 नाइट लैंडिंग से लेकर एटीसी सहित सारी सुविधाएं प्रदान की गईं और सूरत को दिल्ली से जोड़ा भी गया है। जहां तक अन्य शहरों से जुड़ने की बात है, मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं, लेकिन आप भी जानती हैं कि सारी एयरलाइंस के अपने-अपने कमर्शियल कंसिडरेशंस हैं, उन्हें जहां ट्रैफिक मिलेगा, वहां हवाई सेवाएं जरूर बढ़ेंगी। मुझे मालूम है कि सूरत एक बड़ा शहर है और मुम्बई के थोड़ा नजदीक होने के बावजूद वहां हवाई सेवाओं में पर्याप्त मात्रा में वृद्धि नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं और मैं अपनी ओर से भी व्यक्तिगत रूप से सभी एयरलाइंस से बात करके इसके लिए प्रयत्न करूंगा।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : मैडम, हवाई अड्डों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। सरकार की तरफ से बड़े-बड़े दावे किये जा रहे हैं। दिल्ली का टर्मिनल-3 बनकर तैयार हुआ, हम लोगों ने माननीय मंत्री जी का फोटो देखा, वह बैटरी वाली गाड़ी चलाकर वहां पूरे टर्मिनल पर घूमे। लेकिन जिस दिन से वह यात्रियों के लिए खोला गया है, प्रतिदिन समाचार पत्र में एक समाचार टर्मिनल-3 के बारे में देखने को मिल रहा है। जो न्यूनतम यात्री सुविधा पीने का पानी है, उस तक की व्यवस्था वहां नहीं है और इन्होंने इतने लम्बे-चौड़े दावे किए। आपने कहा कि हमारा टर्मिनल-3 पूरे विश्व में एक नम्बर होगा। परंतु आज वहां जो विदेशों से यात्री आ रहे हैं, उन्हें पांच मील चलने पर भी पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं हो रहा है और वहां बैठने के लिए जगह भी नहीं है।

हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपने उसका उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उसमें जो न्यूनतम यात्री सुविधाएं हैं, वे आप कब तक उपलब्ध कराना चाहते हैं और क्या आपने कोई इस तरह का निर्देश दिया है या कोई फैसला किया है?

श्री प्रफुल पटेल : जहां तक आपने कुछ कमियों की बात की, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब एक नया टर्मिनल शुरू होता है तो उसमें शुरूआत की कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन वे इतनी मात्रा में भी नहीं हैं कि हम उसके इतने बड़े आलोचक बन जाएं। अखबारों और मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें जरूर आती हैं, जिनके हमें और आप सबको जानकारी मिलती है। लेकिन मोटे तौर पर आज उस टर्मिनल में यात्रियों के लिए कोई असुविधा है या कमी है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी भावनाओं से सहमत हूं, आखिर दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और जब हमने एक विश्वस्तरीय टर्मिनल

का निर्माण किया है तो उसकी सुविधाएं भी उसके अनुरूप होनी चाहिए। मैं इस बात की तरफ स्वयं भी ध्यान दूंगा।

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY: Madam Speaker, Indian Airlines and Air India have been merged together to form a single organization and as a result of that, expectations of the people grew to a certain level. It was a long-pending demand and some proposals for modernization of few airports are in the process. Mumbai and Delhi airports have been taken up on joint venture basis for expansion and modernization. They are more or less going to be completed now.

My point is, simple modernization of airports and infrastructure development will not serve the purpose, but the allegations of the employees are also need to be taken into consideration. In Kolkata Airport, I am aware that allegations are growing day-by-day against the top management of Air India that they are not taking care of the employees and it may cause damage to the security and safety of the employees. So, I would like to know from the hon. Minister whether any Master Plan has been drawn to construct a well-organised and more modern new airport at Kolkata and whether the allegations of the employees about their day-to-day problems will also be taken care of. I would like to know whether the hon. Minister is prepared to directly intervene at his level. I want the Minister to enlighten us about the latest position regarding Kolkata Airport.

SHRI PRAFUL PATEL: Madam Speaker, the Kolkata Airport is also taken up for major upgradation, though it is being done by the Airports Authority of India itself rather than a joint venture as has happened in Delhi and Mumbai. But that apart, I can assure you that the work at Kolkata is being carried out very efficiently, in a time bound manner and a world-class engineering design or architectural design has been put in place. I am sure as and when the airport terminal and the other facilities at the airport are ready, all people will equally be proud of having a great airport in their city.

As far as employees are concerned, if there are any issues, the hon. Member can bring it to my notice and I will certainly look into the matter.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री साहब को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हिन्दुस्तान के तमाम प्रान्तों में जितने विमानपत्तन हैं, उनके उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का काम किया है। आप लोग तो हवाई जहाज के बाद सुपर जहाज बनाकर आसमान तक भी जाने के लिये तैयार हो रहे हैं लेकिन आप लोग हमारे बोडोलैंड अंचल के 30 लाख लोगों को हवाई जहाज का इस्तेमाल करने के लिये एअरपोर्ट नहीं देते हैं। Why has this kind of discriminatory policy been adopted by the Government of India against the three million people of Bodoland. So, I would like to appeal to the hon. Minister, my friend, Shri Praful Patel to set up an Airport at Kokrajhar with immediate effect. हमारे बोडोलैंड अंचल के 30 लाख लोगों की सुविधा के लिए हम लोगों को एक एअरपोर्ट कब देंगे? मेरा बहुत जबरदस्त दावा है कि अति जल्दी ही हमें एक विमानपत्तन देना ही होगा। मैं आप लोगों को अपनी बात बताता हूँ।

MADAM SPEAKER: All right. Thank you so much. You have put your question.

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : हम लोगों को दिल्ली से गुवाहाटी जाने में हवाई जहाज से चार घंटे 20 मिनट टाईम लगता है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने प्रश्न पूछ लिया।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : गुवाहाटी से फिर मुझे अपनी कांस्टीट्वेंसी तक जाने के लिये पांच घंटा समय लगता है।...(व्यवधान) Why is there this kind of great injustice to the people of Bodoland?

अध्यक्ष महोदया : माननीय मंत्री जी को उत्तर देने दीजिये। उन्हें उत्तर देने का समय दीजिये।

... *(Interruptions)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये।

... *(Interruptions)*

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

SHRI PRAFUL PATEL: Madam Speaker, my friend's anxiety, his keenness and his sentiments are all well respected and appreciated.

* Not recorded.

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य प्रश्न हिन्दी में पूछ रहे हैं और मंत्री जी हिन्दी बढ़िया जानते हैं, फिर क्या बात है?

श्री प्रफुल पटेल : मैं हिन्दी बोल देता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं हिन्दी में जवाब दे देता हूँ।

अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की है, उनसे हमारी भावना अलग नहीं है, उनको यह भी मालूम होना चाहिये। मुझे मालूम है कि परसों ही उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगले बुधवार को हमने बैठने का तय भी किया है। इसलिये, माननीय सदस्य ने बोडोलैंड कौंसिल की जो बात कही है, वहां एअरपोर्ट के लिये एक साईट सजैस्ट की गई थी जिसका सर्वे भी किया गया था लेकिन टैक्नीकली वह साईट सूटेबल नहीं थी। उसके पश्चात् इस संबंध में और कोई प्रगति नहीं हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं सरकार के मामले में इतना जरूर कहूंगा कि डिपार्टमेंट ऑफ नार्थ ईस्ट रीजन के साथ बैठकर हम इस पर जरूर विचार करेंगे। अगर हमें पर्याप्त साईट मिलेगी तो उस पर माननीय सदस्य के सुझाव पर शीघ्र काम हो सकेगा।

MADAM SPEAKER: Thank you so much.

12.00 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now, Papers to be laid.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARUN YADAV): Madam, on behalf of my colleague, Shri Vilasrao Deshmukh, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

- (1) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 2 of 2009-10)-Financial Reporting by Central Public Sector Undertakings (Compliance Audit) for the year ended March, 2009.
- (2) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 9 of 2009-10)-Compliance Audit Observations for the year ended March, 2009.
- (3) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Commercial) (No. 10 of 2010-11)-Performance Audit of Activities of selected Public Sector Undertakings for the year ended March, 2009.

(Placed in Library, See No. LT 2750/15/10)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED): I beg to lay on the Table a copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002:-

- (1) The Competition Commission of India (Salary, allowances, other terms and conditions of service of the Secretary and officers and other employees of the Commission and the number of such officers and other employees)

Amendment Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 344(E) in Gazette of India dated the 22nd April, 2010.

- (2) The Competition Commission of India (Return on Measures for the promotion of Competition Advocacy, Awareness and Training on Competition Issues) (Amendment) Rules, 2010 published in Notification No. G.S.R. 445(E) in Gazette of India dated the 24th May, 2010.

(Placed in Library, See No. LT 2751/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Manufactures Development Council, Kolkata, for the year 2008-2009, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Manufactures Development Council, Kolkata, for the year 2008-2009.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 2752/15/10)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES (SHRI ARUN YADAV): I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

- (1) Memorandum of Understanding between the Triveni Structurals Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2753/15/10)

(2) Memorandum of Understanding between the Bharat Heavy Electricals Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2754/15/10)

(3) Memorandum of Understanding between the Cement Corporation of India Limited and the Department of Heavy Industry, Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises for the year 2010-2011.

(Placed in Library, See No. LT 2755/15/10)

12.01 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report a message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

“In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 2010 agreed without any amendment to the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Bill, 2010 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 3rd May, 2010.”

12.01 ¼ hrs.**COMMITTEE ON THE WELFARE OF
SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
Statements**

SHRI GOBINDA CHANDRA NASKAR (BANGAON): I beg to lay on the Table Statements (Hindi and English versions) showing Final Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in Chapter – I of the Thirty-first Report (14th Lok Sabha) on the subject “Provision for financial assistance and protection of traditional Scheduled Castes and Scheduled Tribes artisans”.

12.01 ½ hrs.**COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION
Reports**

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): I beg to present the Sixth, Seventh, Eighth & Ninth Action Taken Reports (Hindi and English versions) of the Committee on Subordinate Legislation.

12.02 hrs.**STANDING COMMITTEE ON RAILWAYS
Statements**

SHRI T.R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): I beg to lay the following Statements (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Railways:-

(1) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I of the 1st Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 36th Report of Standing Committee on Railways (14th Lok Sabha) on ‘Demands for Grants - 2008-09 of the Ministry of Railways’.

(2) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I of the 2nd Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 40th Report of Standing Committee on Railways (14th Lok Sabha) on 'Review of Plan Performance and 11th Five Year Plan Projection'.

(3) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I of the 3rd Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 41st Report of Standing Committee on Railways (14th Lok Sabha) on 'Review of Special Railway Safety Fund'.

(4) Action Taken by Government on the recommendations contained in Chapter-I and final replies in respect of recommendations contained in Chapter V of the 6th Report of the Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on Action Taken by Government on the recommendations contained in the 4th Report of Standing Committee on Railways (15th Lok Sabha) on „Demands for Grants -2009-10 of the Ministry of Railways’.

12.02 ¼ hrs.

STANDING COMMITTEE ON WATER RESOURCES

4th Report

श्रीमती अन्नू टण्डन (उन्नाव): महोदया, मैं 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकरण' के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2009-10) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूँ।

12.02 ½ hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

18th Report

SHRI GOPINATH MUNDE (BEED): I beg to present the Eighteenth Report of the Business Advisory Committee.

12.03 hrs.

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 2nd Report of Standing Committee on Chemicals and Fertilizers pertaining to the Department of Fertilizers, Ministry of Chemicals and Fertilizers*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SRIKANT JENA): I beg to lay the statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 2nd report of the Standing Committee on Chemicals & Fertilizers in terms of Direction 73-A of the hon. Speaker, Lok Sabha, issued vide Lok Sabha Bulletin Pt.II dated 1st September, 2004

The Department of Fertilizers (DOF) comes under the Ministry of Chemicals and Fertilizers. The main objective of the Department is to ensure adequate and timely availability of fertilizers for maximizing agricultural production in the country and for this purpose to promote and assist industries in the fertilizer sector and to plan and arrange import and distribution of fertilizers.

The main activities of DOF include planning, promotion and development of the fertilizer industry, programming and monitoring of production, pricing, import and supply of fertilizers and management of financial resources by way of subsidy, concession for indigenous and imported fertilizers. The Department also disburses payments to manufacturers/importers of decontrolled fertilizers under the Nutrient Based Subsidy Scheme.

In addition, the activities of DOF also include the administrative control of the following public sector undertakings and cooperatives in the fertilizer sector:-

- (i) National Fertilizers Ltd.(NFL)
- (ii) Madras Fertilizers Ltd. (MFL)
- (iii) Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.(FACT)

* Laid on the Table and also placed in Library See No. LT 2756/15/10)

- (iv) Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd. (RCF)
- (v) Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd. (BVFCL)
- (vi) Projects & Development India Ltd. (PDIL)
- (vii) FCI Arawali Gypsum and Minerals India Ltd. (FAGMIL)
- (viii) Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCIL) (Closed)
- (ix) Hindustan Fertilizer Corporation Ltd. (HFCL) (Closed)
- (x) Krishak Bharati Cooperative Ltd. (KRIBHCO)

The office of the Executive Director, Fertilizers Industry Coordination Committee (FICC) also works under the Department of Fertilizers. This office provides the secretariat- support to FICC constituted to administer the Retention Price Scheme for Nitrogenous Fertilizers and various incentive schemes to augment indigenous production of fertilizers.

In the 2nd Report, the Standing Committee's analysis of implementation of recommendations by Government has revealed that out of the total 18 recommendations contained in the 26th Report of the Committee on Demands for Grants 2008-09, the Department of Fertilizers have implemented twelve (12) recommendations SI. No. 1,2,3,5,7,8,9,10,12,13,17 &18 so far which have also been accepted by the Committee. Further, in respect of three recommendations (sl. No. 4,6, and 11) the replies of the Department have not been accepted by the Committee. In respect of the remaining three recommendations ie 14,15 &16 the replies of the Government were interim in nature.

The Action Taken Replies on the 27 recommendations contained in the 2nd Report have been submitted to the Committee on 8th March 2010.

12.03 ¼ hrs.

**CALLING ATTENTION TO MATTER OF
URGENT PUBLIC IMPORTANCE**

Situation arising out of recent Spurt in the Incidents of “Honour Killings” in the country and steps taken by the Government in this regard.

SHRI GURUDAS DASGUPTA (GHATAL): Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

“The situation arising out of recent spurt in the incidents of “Honour Killings” in the country and steps taken by the Government in this regard.”

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Honour crimes are acts of violence, usually murder, mostly committed by family members predominantly against female relatives, who are perceived to have brought dishonour upon the family. Honour killings are rooted in antiquated traditions and social values.

Recently, instances of honour killings have been reported in the media. Since 'honour killing' is not a crime classified separately under the Indian laws, no data is collected separately regarding this crime by the National Crime Records Bureau, and the same is covered under 'murder'. Moreover, it is difficult to identify or classify an 'honour killing/crime' as such in any given community, since the reasons for such killings often remain a closely guarded private family matter. At present, there is no separate law to deal with the 'honour killing/crime', and such crimes are dealt with under the provisions of the Indian Penal Code and are investigated and prosecuted as offences under the IPC/Cr.P.C.

The Union Government attaches high importance to crimes of violence against women-including the crime of 'honour killing'. As per Seventh Schedule to the Constitution , 'Police' and 'Public Order' are State subjects and,

therefore, the State Governments/UT Administrations are primarily responsible for the prevention, detection, registration, investigation and prosecution of crimes including that of 'honour killing'. Ministry of Home Affairs has sent a detailed advisory dated 4th September, 2009 to all States/UT Governments wherein States/UTs have been advised, *inter alia*, to make comprehensive review of the effectiveness of the machinery in tackling the problem of violence against women, and to take appropriate measures to curb the violation of women's rights by so called 'Honour Killings'. Government is also actively considering a proposal to amend the existing law or to enact a separate law in order to tackle the crime of 'honour killing'.

In pursuance of the Cabinet decision, a Group of Ministers has been constituted to consider a draft Bill on the subject.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, frankly speaking, the Statement just now made by the hon. Home Minister of the country is very innocent, very naive, and does not reflect the gravity of the situation that is prevailing in the country at the moment.

It is not a crime against women alone. Young men are being hanged. It is not only women but it is mostly *dalit* women who are being victimized. The poor downtrodden are the real victims. Let us not, therefore, generalize it as a gender problem; also not generalize it that the State Governments have to do the needful. Let us not outsource the responsibility because the Central Government has the responsibility and because it is the crime against *dalits*, it is the crime against women and it is the crime against human civilization.


Madam, coming to the subject, when the ghost of caste honour strikes, when the religious fanaticism overtakes, webs of medieval and fundamentalist terror are automatically unleashed within the society, the senile human beings are transformed into ghastly ghosts, monsters, criminality is at its worst; mother kills her own baby; father colludes with the murder; and brother turns into a wild conspirator. The crime is committed with the sacred conviction and approval of the conscience because the creatures of social dogmatism having virulent caste bias, pronounce the judgment and in most of the cases it is capital punishment. The penalty has to be imposed because purity of the caste has to be maintained and a social aberration has to be stopped.

Madam, cupid may be blind. Cupid is blind but the guardians of caste and honour cannot be blind to the dilution of caste morality when it takes place. Therefore, Madam, freedom of life and freedom of love cannot be tolerated in a civilized society and, therefore, young people are to be punished mercilessly. We are very hopeful of young India. It is the young India which is being victimized.

Madam, with a desperate indignation and tearful eyes, I would like to raise this discussion. I had raised a similar discussion in the other House maybe 23 years back, Shri Advani may be aware, when Roop Kaanwar, an elegant lady was

burnt to death in Rajasthan in the name of performing *sati*. The right to live and the right to life are the fundamental rights. Therefore, I would like to ask the question in this national forum – without apportioning the responsibility between the Centre and the States; the State is an undivided whole, according to the Indian Constitution – will the State protect the human right? Will the largest democracy in the world rise against the emergence of social fascism? Will the Parliament exert all its authority to protect innocent couples and loving partners?

Madam, the State has failed to discharge the responsibility. Not even the death penalty that was issued in the Karnal Court, awarding capital punishment to five and life imprisonment to one, has deterred the surge of incidents in India because family honour is being trembled down; because community honour is being violated; because religious sentiment is being hurt.

Madam, let me quote – the hon. Minister said that they  had sent an Advisory – the judgments of three Courts including the Supreme Court. Two years back, Punjab and Haryana Court had observed:

“In the last five years, thousands of cases have been filed. Out of 26 petitions”

श्री लालू प्रसाद (सारण): आप नेचर ऑफ केसेस बताइए?...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त : लालू जी, हम सब बोलेंगे। आप मेहरबानी करके हमें बोलने दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : हम जानना चाहते हैं।

श्री गुरुदास दासगुप्त : हम सब बोलेंगे।...(व्यवधान) Please, I beg your patience. ...

(Interruptions)

MADAM SPEAKER: Shri Lalu ji, do not interrupt.

Shri Dasgupta ji, you please continue. It is something very important.

... *(Interruptions)*

SHRI GURUDAS DASGUPTA : I will come to that, gentlemen. ... *(Interruptions)*

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): What your Government has done? *(Not recorded)*

MADAM SPEAKER: Please take your seat. Let him speak.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Gurudas Dasgupta says.

(*Interruptions*) ... *

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, आपका कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): ये एलिगेशन लगा रहे हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: इनका कुछ रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, two years back, Punjab and Haryana High Court had observed:

“In the last five years, thousands of cases have been filed. Out of 26 petitions filed today, ten petitions pertain to marriages of young people. In four days, the cases have swelled to 27. Couples are hiding themselves in the corridors of the court, chased by the relatives, accompanied by musclemen armed with weapons. The State is a mute spectator. When shall the State awake from this slumber? ”

This was the observation of the Punjab and Haryana High Court.

Recently, the Vacation Judge, Mr. Dhingra of the Delhi High Court has said:

“It is unfortunate that elopement cases are converted into rape cases. Police is a party to all honour killings; you connive with parents and turn your faces otherwise; you send the boy behind the bar on rape charges and allow the parents to kill their daughter. ”

The Supreme Court has recently served notice to the Central Government and also to the seven State Governments.

* Not recorded.



They have asked the response as to what they are going to do with regard to the functioning of *Khap* Panchayats, which are some sorts of Panchayats. It has been found that the FIR has been filed after the murder was done. This is the role of the police! ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Banerjee, please sit down.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, the point is. ... (*Interruptions*)

SHRI KALYAN BANERJEE: Madam, please ask him to read the judgment of the Kolkata High Court... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Banerjee, please sit down.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what Mr. Gurudas Gupta is saying.

(*Interruptions*) ...*

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, what is this Panchayat? This Panchayat is a caste council constituted by the senior members of the caste or the village of the region, who proclaim judgment on punishment for having marriage in the same *gotra*, marriage with a prohibited caste. Of late, these panchayats have been very active and assertive. It is there in several States of the North India. According to the Supreme Court, what are the States? They are Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan. This Panchayat is there, may be, in some other States also.

There is a political bias in the whole thing. People are pandering to their vote bank. They do not take action against the panchayats because panchayats control a large number of votes. Therefore, there is growing demand that marriage within the same *gotra* should be banned

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्य ने अभी मध्य प्रदेश का नाम लिया, मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है।

* Not recorded.

श्री गुरुदास दासगुप्त : ठीक है, आपकी जो राय है, वह आप बता दीजिए। मैंने तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो लिखा है, वह बताया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे छोड़ दीजिए। The Supreme Court has written it. I am not saying it. Now, the point is the same *gotra* marriage has to be banned. The support is gaining momentum across the caste. Even political leaders are supporting it. A policeman having an all India fame, who is said to be having love for hockey, has given his support that this type of marriage should be banned. I am sorry; I would like to be given the truth, whether a Chief Minister of a neighbouring State of Delhi is lukewarm to the position to be taken by the Government to take action against these virulent panchayats.

The hon. Home Minister should tell us the truth and only the truth, because there has been a statement; there has been a press report in this regard.

Madam, the point is that this, in my opinion, is a colossal human problem.
MADAM SPEAKER: Please conclude, now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : There is no need to politicise it. Any person, who is trying to politicise the same caste marriage; any Member of the Parliament, who wishes to pull the brake on the discussion that we are having, will not be doing the right, will not be doing the duty... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं। कृपया आप बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

MADAM SPEAKER: Please take your seat, Mr. Banerjee.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Mr. Dasgupta, please conclude, now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Therefore, my question to the hon. Home Minister is this... (*Interruptions*)

I accept hon. Speaker that the incident involving Rizwanur death is a blot on the dignity of West Bengal; I do not approve it; and I do not approve the role the Police Commissioner played, who had been subsequently removed.

Let it be known clear that Rizwanur's death took place because he was provoked by the relatives of the girl. The Police Commissioner at that time played foul and the Government removed him. I do not approve of it. I condemn it. I join you in condemning them. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please conclude now.

SHRI GURUDAS DASGUPTA: My questions are like this. Will the State protect the young girls and young boys and compel the police to take action? It is not a question of whether it is Haryana Government or Mr. Chidambaram's Government. Second question is, will you make new laws? If you want to make new laws, what is going to be there in the new laws? Can you share with us? Third question is, have you mooted any proposal? Fourth question is, is it true, according to the Press, that your proposals had not been approved in a recent meeting of the Cabinet? It came in the Press.

Here are my last two questions. Is it true that a Mahapanchayat had taken place in Kurukshetra in April and the Government of Haryana did not take any action? Is it true that the Government is vacillating there?

The last question is, will you call a meeting of the Chief Ministers of the States? Will you call a meeting of the political parties and try to build up a consensus on this issue?

Let the Government act, act decisively and put the people behind the bar; and do not create a situation where the face of India is put to shame before the comity of the nations.

अध्यक्ष महोदया : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप मात्र एक प्रश्न स्पष्टीकरण के लिए पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदया, बिना भूमिका बनाए प्रश्न कैसे आ आएगा?

अध्यक्ष महोदया : बहुत संक्षिप्त में भूमिका बनाइए और बहुत जल्दी से अपना प्रश्न पूछिए।

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदया, आपने ऑनर किर्लिंग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी सम्मानित सदस्य गुरुदास दासगुप्त जी ने इस संबंध में अपनी बात कही। पूरे देश के अंदर मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बड़े पैमाने पर इसको

दिखाया गया और सुबह से शाम तक चैनल में यही चलता रहा। हमारे उत्तर प्रदेश में एक कहावत है - प्रेम न जाने जात-कुजात और नींद न जाने टुटही खाट। आज देखा गया है कि पारिवारिक और सामाजिक ऑनर के लिए, मूछ के लिए इस प्रकार की हत्याएँ हो रही हैं। इस पर सदन और सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

मैडम, आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि कट्टरवादी, धार्मिक और जातिगत आधार पर जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी मानसिकता आज के समय में भी वैसी है, इसमें ज्यादातर अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनकी हत्याएँ हुयी हैं। मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि विशेष कानून को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल करेंगे। चूंकि हत्या राज्य का मामला है, लेकिन इसे समवर्ती सूची में शामिल करके, केंद्र इसके लिए कानून बनाने का प्रावधान कर रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में उनके द्वारा एक समूह का गठन किया गया है। इस विषय में सम्मान के रूप में देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फर्रुखाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और कुछ जगह राजस्थान में भी है, वैसे तो अगर पता लग गया, तब तो वह मामला ऑनर किलिंग में आ गया, लेकिन कुछ हत्याएँ तो ऐसी हैं, जिनका पता ही नहीं है। ऐसा देश के कोने-कोने में हो रहा है। यह बड़ा गंभीर मामला है। मैं तो यही कहूंगा कि झूठी शान के लिए जो हत्याएँ हो रही हैं, खासकर पंचायत आज भी वही पुरानी परंपरा, रीति-रीढ़ को लेकर फैसला देती है, उससे समाज पर बहुत कुठाराघात हो रहा है, दूसरी तरफ पुरानी परंपरा की ओर हम देख रहे हैं।

जबकि पब्लिक ग्रिवांस लॉ एंड जस्टिस कमेटी में ग्राम पंचायत अदालतों के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए। आपकी भूमिका हो गई है।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। माननीय मंत्री जी प्रधान मंत्री जी के निमित्त में जो कमेटी बन रही है, उसमें जो कानून बन रहा है, वह बन रहा है, लेकिन मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि इसमें आपका स्पष्ट जवाब आना चाहिए। दादा ने जो प्रश्न किया है, मैं भी उस प्रश्न से सम्बद्ध करते हुए कहना चाहूंगा कि यह एक सामाजिक कुरीति है। हम 21वीं सदी का सपना देख रहे हैं। इस प्रकार की जो ऑनर किलिंग हो रही है, उस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आप इस बारे में कड़ा कानून बनाइए, ताकि यह रुके। समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन - उपस्थित नहीं।

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 21वीं सदी में प्यार करके शादी करना गुनाह माना जाता है और उस गुनाह के लिए साधारण नहीं बल्कि मौत की सजा दी जाती है। खाप पंचायतें फरमान निकालती हैं और ऐसी शादी करने वालों का मर्डर किया जाता है। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण बात नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है। पैरलल नई संस्थाओं को चलाया जा रहा है। पैरलल कानून, उसके लिए आर्डर और उसका ऐगज़ीक्यूशन हो रहा है। केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके लिए एक चैलेंज है। किसी भी लोकतंत्र में पैरलल संस्था चलाना, गैर-कानूनी फैसले करना और उन पर अमल करना अपने आपमें बहुत बड़ा गुनाह है। समस्या जितनी गंभीर है, माफ कीजिए, उतनी गंभीरता से आपका स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि सगोत्र शादी करना गलत है। जहां इंटर कास्ट मैरिज हुई हैं, उनकी भी हत्याएं हुई हैं। ये हत्याएं लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके परिवार के लोग ही उसमें हिस्सा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि यह गलत परम्परा और रूढ़ियां हैं। गलत परम्परा और रूढ़ियों की वजह से जो मर्डर हो रहे हैं, उन्हें चलने देना या नहीं चलने देना बड़ा चैलेंज है और उन्हें रोकना चाहिए।...(व्यवधान) पिटाई हो रही है, गांव से हटाया जा रहा है, बहिष्कार किया जा रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया शान्त हो जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : गलत परम्परा का समर्थन उससे ज्यादा गलत है कि हमें अधिकार है, हम न्याय करेंगे और कोई व्यवस्था न्याय नहीं करेगी। खाप पंचायतें मीटिंग कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं और लोगों को संगठित कर रही हैं कि हम जो कर रहे हैं, वह न्याय है, सरकार जो कर रही है, वह न्याय नहीं है। वोट बैंक के कारण सरकार भी डरी हुई है। ऐसी परिस्थिति आठ राज्यों में है, लेकिन मैं उन राज्यों के नाम नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि हर राज्य में गलत परम्परा हो सकती है। लेकिन तीन-चार राज्यों में सैंकड़ों घटनाएं हुई हैं जिनके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और जवाब-तलब किया है कि राज्य और केन्द्र इसके लिए कड़े कानून बनाएं, कड़े कदम उठाएं। ऐसे फैसले के बाद भी सरकार सोई हुई है। मैं इस परिस्थिति का ज्यादा वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन 21वीं सदी में भारत को यह शोभा नहीं देता। कभी-

कभी मुझे डर लगता है, मैंने तीस साल पहले इंटर कास्ट मैरिज की। अगर मैं ऐसे प्रदेश में होता तो शायद यहां बोलने के लिए भी उपस्थित नहीं होता और कई सांसद भी उपस्थित नहीं होते।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

... (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे : आपने कहा है कि यह राज्य का विषय है। रजिस्ट्रेशन ऑफ दी केस, इन्वैस्टीगेशन और उसके सब फैसले करना राज्य का विषय है। मेरा सवाल है कि क्या केन्द्र इसके लिए स्पेशल कानून नहीं बना सकती? ऑनर किलिंग, प्रतिष्ठा के लिए हत्या के खिलाफ आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अलग कानून लाना पड़ेगा।

मिनिस्टर का ग्रुप बनाया गया, लेकिन कोई कानून नहीं है। आपको इसी सेशन में कानून लाना पड़ेगा। इसमें देरी करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि इसे राज्यों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके लिए अलग कोर्ट बनाना चाहिए। यदि केसेज होते हैं, तो वे दस-दस साल तक चलते हैं। उस समय तक काफी विटनेसेज नहीं रहते। ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने चाहिए। क्या सरकार इसके लिए अलग कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनायेगी? इसके साथ-साथ उन पंचायतों को, जो इस प्रकार के फैसले दे रही हैं, उनके प्रति भी सरकार क्या कदम उठाना चाहती है? हत्या होने के बाद कानून लागू करना, हत्या होने के बाद एक्शन लेना ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे फरमान जारी करना इल्लिगल है। ... (व्यवधान) ऐसी मीटिंग करना इल्लिगल है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुंडे जी, आप प्रश्न पूछकर अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गोपीनाथ मुंडे : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठायेगी?

MADAM SPEAKER : Because one Member is absent, as a special case, I am giving permission to Dr. Girija Vyas.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam, please give us half-a-minute. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : Let Dr. Girija Vyas speak.

... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER : The hon. Lady Member has got up. I think you should sit down.

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): आदरणीय महोदया, सबसे पहले मैं आपको और आपके साथ-साथ सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपने आप ही होम मिनिस्टर साहब ने कहा और हम लोगों के

पत्रों का जवाब भी आपकी तरफ से आ रहा है कि केन्द्र सरकार इसके लिए निश्चित तौर पर चिन्तित है। लेकिन चिन्ता के इस विषय के साथ मैं चाहती हूँ कि सम्पूर्ण सदन और देश जो आज इस बात के लिए चिन्तित है, उस पर और भी काफी कुछ विचार करना आवश्यक है।

महोदया, मुझे तीन दिन पहले लॉस एंजलिस से एक बच्ची का पत्र मिला जिसने कहा कि जब मैं निकलती थी, तब सिर ऊपर करके निकलती थी कि मैं भारत की उन बच्चियों में से हूँ जो स्पेस में काम कर रही हूँ। लेकिन आज मुझे लाइब्रेरी से निकलते हुए लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम उसी देश की हो, जहां पर ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में कम से कम हजार इस तरह की हत्याएं होती हैं। हम लोगों ने एक स्टडी करवाई है जिसके अनुसार 500 केसेज लिये गये। अभी तक वह स्टडी जारी है। इंटर कास्ट में 465 अर्थात् 83.3 परसेंट इंटर कास्ट के कारण ऑनर किलिंग बतायी गयी है। इंटर रिलिजन में 14 अर्थात् 2.5 परसेंट, सेम कास्ट का 55 अर्थात् 9.82 परसेंट, सेम गोत्र में 18 अर्थात् 3.21 परसेंट और अदर रीजन से 8 अर्थात् 3.21 परसेंट मामले सामने आये। जिन कारणों से केस स्टडी निकल कर आयी है, वह भयावह स्थिति है कि एफआईआर रजिस्टर ही नहीं होती। दूसरा, यदि रजिस्टर हो गयी, तो बहुत अधिक मामलों में, जिन पर हमारे पूर्ववक्ताओं ने आपका ध्यान आकर्षित किया, वह क्लोज कर दी जाती है। तीसरी बात है कि उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता और चौथी बात यह है कि उनकी एफआईआर के बावजूद उनका मर्डर हो जाता है। तब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कनविकशन रेट बहुत लो है। ...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): सरकार किसकी है और आप शिकायत किससे कर रही हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं सभी से शिकायत कर रही हूँ। समाज से कर रही हूँ, देश से कर रही हूँ, आपसे कर रही हूँ और अपने आप से कर रही हूँ। इसीलिए मैंने उन शब्दों का प्रयोग किया कि हम शर्मिंदा हैं कि आज भी हमारे यहां ऑनर किलिंग हो रही हैं। यह केवल सरकार का कार्य नहीं है। सरकार का कार्य निश्चित तौर पर कानून को बनाना है, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके जो पांच पिलर्स हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उसमें इलैक्टेड मैम्बर्स की भी जिम्मेदारी है। उसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहती हूँ कि मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता और समानता को वाइडर करने के लिए क्या सरकार की कोई मंशा है? मैं यहां पर सरकार से पूछना चाहूंगी और निवेदन करना चाहूंगी कि न केवल किलिंग, लेकिन उससे संबंधित अन्य प्रकार के कार्य, जैसे उसे आत्महत्या के लिए उकसाना और आत्महत्या के मामले दर्ज करना, इस तरह के मामले सामने आये। हमारे

पास रोज आठ से दस केसेज ऐसे आ रहे हैं जो तीन-चार महीने से लगातार इस कोने से लेकर दूसरे कोने तक कपल्स घूम रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाये। उनके प्रोटेक्शन की क्या व्यवस्था है और उन लोगों के रख-रखाव की व्यवस्था करने का क्या विचार है? मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हम लोगों ने कहा है कि इस संबंध में सुपरीटेंडेंट पुलिस या डिप्टी सुपरीटेंडेंट पुलिस से नीचे किसी भी अधिकारी को जांच करने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मामले सामने आये हैं, जो रिपोर्ट कह रही है, उसके अनुसार नीचे के स्तर के अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते और चले जाते हैं। निश्चित तौर पर इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के ऊपर कमान कसने के लिए निश्चित तौर पर कुछ कदम उठाने पड़ेंगे।

मुझे ज्ञात है कि हरियाणा कोर्ट ने जो कहा था, उसे मैं कोट करना चाहती हूँ : **When shall the State awake from its slumber?** इसी के साथ-साथ कल का सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जो 20 साल पहले के केस का जजमेंट है, उसमें जज साहब ने सजा सुनाते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अभियुक्तों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। यदि 20 साल तक ऐसे केसेज चलते रहते हैं, तो मैं माननीय मंत्री जी से इसके बारे में गुजारिश करूंगी और पूछना भी चाहूंगी कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करने के लिए क्या प्रावधान किया जाना आवश्यक है? इसके साथ ही अन्य कई अपराध जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऑनर किलिंग से संबंधित जितने भी प्रकार के क्राइम्स हैं, उनको इसमें एप्रोप्रिएट तरीके से डिफाइन करना होगा। जो बच्चे घूम रहे हैं, उनके माता-पिता को बुलाकर समझौता कराने का प्रयास किया। इस तरह के 20-30 मामले हमने सुलझा लिए हैं। ऐसे मामले रोज सामने आ रहे हैं। कोई भी स्टेट इससे बचा हुआ नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि केवल सात स्टेट्स हैं, कोई नहीं कह सकता है कि केवल कुछ जातियों से संबंधित हैं, सभी जातियों के लोग इससे संबंधित हैं। आपके माध्यम से मैं इस सदन से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि यह सदन भी गंभीरता के साथ इस पर विचार करे। इस पर केवल वोट की राजनीति न करें, इसे गंभीरता के साथ लें। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि इसके लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता है।

सती प्रथा के संबंध में भी जब इस तरह की बात उठी थी, उस समय मैं राजस्थान में मंत्री थी और यहां पर राजीव गांधी जी थे, आप सभी लोगों ने मिलकर सती से संबंधित जो कानून बनाया, उसका आधार यही था कि वह मर्डर के अंतर्गत आता है, लेकिन एक ऐसा मर्डर, जिसको अलग से परिभाषित करने और उसके लिए अलग से न्यायोचित व्यवस्था होनी आवश्यक है। इसीलिए इस सो कॉल्ड ऑनर किलिंग के लिए भी अलग से कानून की आवश्यकता पड़ी है। केवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पर ही छोड़ने से नहीं होगा, इस पर आपस में और भी संवाद हो।

मैं अंत में निवेदन करना चाहती हूँ कि इसके लिए छः पिलर्स की आवश्यकता है, इनमें से पहला है सरकार का बनाया हुआ कानून। दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस आदि की व्यवस्था, तीसरा, अवेकनिंग के कार्यक्रम, चौथा हम सभी इलेक्टेड मेंबर्स और सिविल सोसाइटी की भूमिका। मैं आपके माध्यम से सदस्यों ने निवेदन करना चाहती हूँ सभी सदस्य सामूहिक रूप से इस बात की प्रतिज्ञा करें कि उनके क्षेत्र और राज्य में इस प्रकार का जघन्य अपराध न हो।

आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ।

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Madam, my only question is this. Is it true that a political party in Haryana Assembly has given the notice for modification of registration of Marriages Act so that marriages under the same *gotra* are banned in India?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I am grateful to the hon. Members for raising this issue. In fact, this issue has been engaging the attention of the Government for many months now.

There was a debate in the Rajya Sabha on 28th July 2009. At the end of that discussion, I listed that the following issues are the issues that will be considered by the Government:

- 1) examine whether honour killing could be defined separately in the Indian Penal Code.
- 2) examine whether a provision could be made to treat the caste panchayat or *khap* panchayat as accomplices in the crime and prosecute the leading members of the panchayats.
- 3) examine whether at some point of time in the trial, the onus of proof may shift to the accused and whether a provision to that effect could be made in the Evidence Act.
- 4) examine whether the Special Marriages Act needs to be amended to provide for quicker registrations of special marriages.

Madam Speaker, since then, my Ministry has worked on these issues and after taking the opinion of the Attorney-General, we have drafted a law. That Bill has been referred by the Cabinet to a Group of Ministers. The principal question is whether it should be a stand-alone law or whether it should amend the existing provisions of the Indian Penal Code.

I can assure the hon. House that the Bill -- whether it is a stand-alone law or an amendment to the IPC -- will deal with the issues that I have listed. It is a strong Bill. It defines the crime of honour killing. It takes within its sweep some other kinds of dishonour that is inflicted upon couples, especially the girls, like stripping them in public or externing them from the village. These are just as humiliating as honour killing, and must be punished with severity.

At present, every honour killing is murder. In fact, there is no honour in this killing. Such killings bring dishonour to the families, to the community, to the State, and to this country. In the name of defending honour, persons who encourage killing of young people and couples, bring grave dishonour to this country. In fact, one of the suggestions is this. Why do you call this honour killing? There is no honour in this killing. This must be condemned as the most dishonourable act that can be done in this day and age.

Therefore, a lot of work has been done since July. This debate is coming at the end of the work. A little more work has to be done, and I am confident that the Group of Ministers (GoMs) will give its Report shortly. It is my intention -- and I hope that I am successful -- to introduce the Bill in this Session of Parliament.

SHRI GURUDAS DASGUPTA : Very good! ... (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM : There were some issues raised. My dear friend Mr. Gopinath Munde is usually very soft in his language. Today, he said that the Government is scared and the Government is sleeping. I can assure Mr. Gopinath Munde and this House that the Government is not scared. In fact, ... (*Interruptions*)

श्री लालू प्रसाद : मंत्री जी, एक मिनट अगर आप समय दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

SHRI P. CHIDAMBARAM : Do not ask me. Please ask the Speaker's permission. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदयः आप मंत्री जी को जवाब देने दें।

श्री लालू प्रसाद : मैडम, एक मिनट मेरी बात सुन लें। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, यहां पांच-दस मिनट डिस्कशन कराकर और केबिनेट में जाने से पहले आप सभी दलों की मीटिंग बुला लें, तो ठीक रहेगा। यहां बैठे-बैठे चंद लोगों का भाषण सुनकर ही कोई निर्णय न लें। मैं अपनी बात बताता हूँ। हमारा कश्यप गोत्र है। हमारी शादी गोत्र में होती है और देश में इन लोगों की बड़ी भारी संख्या है। अगर आप बैन लगाएंगे कि विदइन गोत्र शादी नहीं होगी, तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, इस पर भी विचार हो जाएगा।

श्री लालू प्रसाद : बहुत सारी बातें आई हैं इसलिए सभी दलों की मीटिंग बुलाएं। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोई भाग्य विधाता नहीं हैं देश के इसलिए ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर पहले सभी दलों की मीटिंग बुलाकर उनसे चर्चा करें। बात को समझें...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अलग-अलग समाज की अलग-अलग व्यवस्था है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब शांत हो जाएं।

...(व्यवधान)

SHRI GURUDAS DASGUPTA: Criminality is criminality. It cannot be condoned under any pretext. ... (*Interruptions*) It knows no social custom. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record except what the Minister is saying.

(*Interruptions*) ... *

श्री लालू प्रसाद: अपने देश में वही हुआ, आपने यह व्यवस्था भी की है कि महिला महिला से शादी कर सकती है, जबकि भारतीय व्यवस्था में यह ठीक नहीं है। ज्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाएं और मंत्री जी को जवाब देने दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: लालू जी, इतना गुस्सा नहीं करते। अब आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not lose your temper.

... (*Interruptions*)

SHRI SHATRUGHAN SINHA (PATNA SAHIB): He has raised a very valid point. ... (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: इतने नाराज क्यों हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM : Madam Speaker, if I may continue what I was saying?

MADAM SPEAKER: Yes, please do.

* Not recorded.



SHRI P. CHIDAMBARAM : The law that is being contemplated is a law to punish crimes that are committed against young couples on the ground that they have brought dishonour to the community or the family or the village. Under the law, as it stands today, it is a crime.

In the discussion that is taking place in society today, there is a demand that that crime, which is punishable under today's law, must be identified and punished with greatest severity. This is the law, which is being made. Therefore, I would like to assure the hon. Members that the Government is not sleeping. A lot of work is being done, and we are in the final stages of the work. We are consulting all State Governments. I have asked all the State Governments to give their views. The GoMs will also give its view. The matter will go to the Cabinet, and I repeat that it is my intention to introduce the Bill in this Session of Parliament. ...

(Interruptions)

There was some question about why FIRs are not registered. As I said, the law, as it stands today, treats this as murder; the FIRs must be registered; FIRs must be investigated; and the criminals must be prosecuted and punished. We have given advisory to the State Governments on these matters. If the State Governments are tardy or lax or remiss in registering FIRs and punishing the perpetrators of these crimes, then it is those State Governments that must be held to account. If people think that they are not accountable, then I think that they are wrong. The people of this country and the people of that State will hold them accountable. After all, they are accountable once in five years. So, some people may think that they are not accountable today and they can get away without accountability. But I think that they will be called in to account by society, and all right-thinking people will call them in to account. I think that the States must register FIRs and must prosecute the criminals.

Madam, I do not want to get into a discussion about Khap Panchayats and so on. I deal with the law as it stands and as it is made by the Parliament, and when the Parliament amends the law, then that is the law of the country. My duty

is to ensure that the laws are obeyed; the laws are enforced; and the law-breakers are punished, whoever that may be. If it is an individual; if it is a collection of people; if it is a collection of people in the name of Khap Panchayat, whoever is a cause of a crime, must be punished.

I know that various views are expressed in various meetings of people of one community or more than one community. We have to look ahead and build a society that is based on secular values and enlightened views. It is possible that there will be different views on different subjects, but I see my duty as ensuring that the laws are obeyed. It is the Parliament's privilege and responsibility to make the laws as society wants the laws to be made, reflecting the views of the people, and amending the laws when it is necessary to amend the laws.

In the debate that is going on over the last seven or eight months, there is a need felt that the law must be amended to punish honour killing and that is precisely what we are doing. We are not dreaming about the 21st Century as Shri Shailendra Kumar says. We are living in the 21st Century. Therefore, the laws must reflect what the 21st Century requires. It is entirely for the Parliament to make the law. My duty is to bring the law as I think that it is necessary, and it is your privilege to make the law as you think it necessary. ... (*Interruptions*) But once the law is made, then that law must be enforced and the breakers of the law must be punished.

MADAM SPEAKER: Thank you. I just want to say that it is a matter of satisfaction that honour killing has been discussed. I am very much concerned and so is this House that young people are getting killed, and killed by those who should love and protect them. It is a de-humanizing process. I think that we should and we have taken a very serious view of it.



MADAM SPEAKER: Now, the House will take up the legislative business. Item No. 13, Shri Ghulam Nabi Azad.

12.50 hrs

INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT) BILL, 2010*

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam Speaker, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956.

MADAM SPEAKER: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Medical Council Act, 1956.”

The motion was adopted.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I introduce the Bill.

12.5½

**STATEMENT RE: INDIAN MEDICAL COUNCIL (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2010****

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): Madam Speaker, I beg to lay on the Table an explanatory statement (Hindi and English versions) showing reasons for immediate legislation by the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance (No. 2 of 2010).

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 5.8.2010.

** Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 2757/15/10.

12.51 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

(i) Re : Situation being faced by Urdu newspaper due to the negligent attitude of Government Institutions in the country

अध्यक्ष महोदया : कौशलेन्द्र कुमार जी, मुलायम सिंह जी को बोलने दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): महोदया, यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें बोलना नहीं होता तो इतनी मेहनत करके सवाल क्यों उठाते? उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा है और पूरे समाज की भाषा है। उर्दू समाचार पत्रों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना, प्रचार प्रसार रोकना, उर्दू भाषा को खत्म करना है। अगर किसी कौम को खत्म करना हो तो उसकी जुबान, भाषा को खत्म किया जाता है। आज भी पांच करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू भाषा में पढ़ते, लिखते हैं और नौकरियों के लिए इम्तिहान देते हैं। उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई तो पांच फीसदी ऐसे लोग थे जिन्होंने उर्दू भाषा में लिखा था। लेकिन आज उर्दू भाषा को यह कह कर मिटाया जा रहा है कि उर्दू एक समाज की भाषा है। यह थोपा जा रहा है कि मुसलमानों की भाषा है। यह मुसलमानों की भाषा नहीं हिन्दुस्तान की भाषा है। इस देश में राजकाज भी उर्दू में हो चुका है। आज उर्दू की दयनीय दशा हो गई है जबकि यह सबसे मीठी और लोकप्रिय भाषा है। इस भाषा को मिटाने के लिए सरकार इस षड्यंत्र में लगी है, मैं यह इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आजादी की लड़ाई में उर्दू भाषी शायरों और नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उर्दू और हिंदी, दोनों भाषाओं ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी। उर्दू भाषा ने कुरबानी देने के लिए बहुत जोश पैदा किया था जबकि आज उस भाषा को मिटाने की बात हो रही है। मेरा आग्रह है कि सरकारी नौकरियों में 14.6 प्रतिशत मुसलमानों की भर्ती की जाए। हमने करके दिखाया है और यह भर्ती हुई है। उत्तर प्रदेश में 15 फीसदी उर्दू पढ़ने लिखने वालों की भर्ती हुई है, आप जांच करा सकते हैं। आज उर्दू अखबारों को समाप्त किया जा रहा है, मैं इसे भाषा मिटाने का षड्यंत्र ही कह सकता हूँ। उर्दू अध्यापकों की बहुत पोस्टिंग की हुई, यह हजारों में है। उर्दू भाषा के बारे में यह कहना कि यह मुसलमानों की भाषा है, यह थोपना गलत है। यह मुसलमानों की भाषा नहीं है हिन्दुस्तान की भाषा है। ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे खत्म करना चाहते हैं। माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, ये जिस कौम में हैं, इनकी कौम में सबसे ज्यादा उर्दू बोली जाती थी और आज भी लोग लिखते पढ़ते हैं। क्या ये मुसलमान हैं? यह बहुत ही बुद्धिजीवी, साहित्यकारों का समाज है। यह बहुत आगे रहा है। उर्दू भाषा का स्वतंत्रता की लड़ाई में बहुत योगदान रहा है लेकिन आज पत्रकारिता खत्म हो रही है।

आज अखबार बंद हो गये, विज्ञापन बंद हो गये। आखिर विज्ञापन बंद क्यों किये गये हैं? हम आपके सामने यह बात रखना चाहते हैं कि एक बार केन्द्र सरकार ने गुजराल समिति की रिपोर्ट इसी सदन में पास कराई थी कि उर्दू भाषा का विकास किया जायेगा। इसी सदन के द्वारा एक कमेटी बैठी थी, जिसकी अध्यक्षता भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री इंद्र कुमार गुजराल ने की थी। उस समय भी पूरे देश में उर्दू भाषा को महत्व दिया गया था। यह भाषा आज की नहीं, 18 जनवरी, 1968 में भी दोनों सदनों द्वारा सरकारी प्रस्ताव पारित किये गये थे और इस बात पर जोर दिया गया था कि शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास के दृष्टिगत हिन्दी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए, तमिल और तेलुगु भाषा का भी विकास होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान जो 14 भाषाएं हैं, उसमें उर्दू बहुत महत्वपूर्ण भाषा है।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। 2 मई, 1972 को संसद के समक्ष प्रो. नूरुल हसन द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद उर्दू को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भाषा माना गया था। यदि आप उस समय के आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में 51, 536,111 लोगों की मातृभाषा उर्दू है। गुजराल कमेटी की रिपोर्ट 8 मई, 1975 को शिक्षा मंत्रालय को प्राप्त हुई थी। हम जानना चाहते हैं कि उस पर सरकार ने क्या किया है और आगे सरकार क्या करना चाहती है? 1979 की रिपोर्ट पर तरक्की उर्दू बोर्ड की एक उपसमिति द्वारा भी विचार किया गया था।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, आप उतना लम्बा मत पढ़िये। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : मैं दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं। परंतु मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करा दी जाए और सदन की राय भी ले ली जाए। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने इस बारे में पहले ही कहा कि आजादी की लड़ाई में उर्दू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसमें देहली उर्दू अखबार के सम्पादक मौलवी मुहम्मद बाकर को भी यह सम्मान प्राप्त हुआ था और 1857 में सादिकुल अखबार के सम्पादक जमालुद्दीन को विद्रोहियों की सहायता के आरोप में तीन वर्ष का कारावास दिया गया था। यह अंग्रेज हुकूमत ने किया था, क्योंकि उन्होंने आजादी की लड़ाई में इस भाषा का प्रयोग किया था।

अध्यक्ष महोदया, मैं आज कहना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग, आर्य समाज, हिन्दू महासभा, खिलाफत कमेटी और अलीगढ़ आंदोलन उर्दू समाचार पत्रों के समाचारों में अहम् स्थान रखते रहे। केवल यही नहीं आर्थिक संसाधनों के अभाव में एवं अन्य विभिन्न कारणों से अधिकांश उर्दू समाचार पत्र आर्थिक रूप से जर्जर हो चुके हैं और इस सरकार ने उर्दू समाचार पत्रों को विज्ञापन देना बंद कर दिया है। एक भाषा को खत्म करना किसी कौम को खत्म करना है। यदि एक कौम को खत्म करना है तो उसकी भाषा

को खत्म कर दीजिए। क्या सरकार का यही कर्तव्य है? आप सरकार से जवाब मांगिये कि उर्दू भाषा के अखबारों के विज्ञापन क्यों बंद किये गये हैं? इसके अलावा कारपोरेट जगत एवं हिंदुस्तान के बड़े-बड़े उद्योगपति एवं पूंजीपति भी पूरी तरह से उर्दू समाचार पत्रों की उपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए आज एक बड़ा खतरा उर्दू भाषा को खत्म करने का खतरा पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : उर्दू भाषा के प्रति सरकार का उपेक्षापूर्ण रवैया है। जबकि इस देश में उर्दू पाठक भी करदाता है। ये लोग भी कर देते हैं। उर्दू अखबार वाले भी उर्दू की अपनी सेवाओं के लिए देश को कर देते हैं। ...(व्यवधान) उर्दू देश की सबसे अधिक लोकप्रिय और सबसे मीठी भाषा मानी जाती है।

अध्यक्ष महोदया : जो माननीय सदस्य इससे अपने सम्बद्ध करना चाहते हैं, वे अपने नाम भेज दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री लालू प्रसाद, श्री रामकिशुन, श्री राकेश सचान, श्री धर्मेन्द्र यादव, श्री नामा नागेश्वर राव, श्री अब्दुल रहमान, श्री शैलेन्द्र कुमार तथा श्री एम.बी.राजेश इस विषय से अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नारायणसामी जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : जीरो ऑवर के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या होगा। आप इस तरह मत कीजिए। दो-तीन दिन से जीरो ऑवर नहीं हुआ है। All these people who have given notice for 'Zero Hour', we have to also see them. Is it not? नारायणसामी जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप इस तरह से मत कीजिए। जीरो ऑवर चलने दीजिए। यादव जी ने स्पेशल परमीशन ली थी, हमने उन्हें दे दी। अब आप सब लोग बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)



13.00 hrs.

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो ऑवर चलने दीजिये। इन्होंने स्पेशल परमिशन लिया था तो उनको दे दिया। अब आप सब लोग बोलेंगे तो अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All these people who have given notice for 'zero hour' also have to speak.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो ऑवर चलने दीजिये. श्री नारायणसामी जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मैं रैस्पोंड कर रहा हूँ, मैं आपके फेवर में बात कर रहा हूँ।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो ऑवर चलने दीजिये। आप लोग एसोसिएट करना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Please do not make it long. I have to run the House. I have to give chance to the 'zero hour' people. मुलायम सिंह जी भी बहुत देर बोले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो ऑवर लेने दीजिये।

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): मैडम स्पीकर, उर्दू जुबान एक मीठी जबान होती है। मुलायम सिंह जी ने जो मामला यहां रखा है, मैं उनको अपना पूरा समर्थन देता हूँ। हम चाहते हैं कि सारे देश...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Then you go on and you make it so long and everybody else waits.

श्री सुदीप बंदोपाध्याय : उर्दू जुबान को अपना स्टेटस देना चाहिये। अगर उर्दू जुबान को कोई प्रोटैक्शन नहीं देंगे तो हम लोग उसके खिलाफ जरूर लड़ेंगे।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री नारायणसामी जी की बात रिकॉर्ड में जायेगी।

SHRI V. NARAYANASAMY : Madam, senior leader of the House hon. Mulayam Singh Yadavji has raised a very important issue. Urdu is a very important language of our country. ... (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Hon. Members, all those who want to associate themselves with this very important issue, namely importance of the Urdu language, please send your names to the Table. Let the hon. Minister respond now because the 'zero hour' people are waiting.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मुलायम सिंह जी, इस तरह नाराज होने से तो नहीं चलेगा कि आप नाराज़ हो जायें। आप बैठ जाइये। माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ मुंडे (बीड): अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आप एक वाक्य में खत्म कीजिये।

श्री गोपीनाथ मुंडे : अध्यक्ष महोदया, श्री मुलायम सिंह जी ने उर्दू भाषा के लिये जो कहा, उर्दू भाषा देश की भाषा है, किसी धर्म की भाषा नहीं है। इसलिये, उर्दू भाषा के महत्व को समझना चाहिये, उसे महत्व देना चाहिये। उर्दू लैंग्वेज़ के एडवर्टाइजमेंट बंद करना गलत है। हर भाषा इतनी अच्छी भाषा है, उस पर अन्याय हो रहा है, वह अन्याय दूर करना चाहिये।

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): अध्यक्ष महोदया, यह सही है कि उर्दू जुबान बहुत ही मीठी जुबान है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता है। हम लोग जानते हैं कि पुराने जमाने में खतो-किताबत उर्दू जुबान में ही लिखे जाते थे। इसलिये इस मामले पर चर्चा होनी चाहिये। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को उर्दू के विकास के लिये पूरा समर्थन दिया जाना चाहिये।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, आप बैठ जाइये। श्री महबूब बेग को बोलने दीजिये। लालू जी वौल्यूम ऊंचा न करिये। आप बहुत ऊंचा स्वर क्यों ले जा रहे हैं? आप पहले बेग जी को बोल लेने दीजिये। आप बैठिये।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग(अनंतनाग): मैडम स्पीकर, मैं अपने अपने आपको इनकी फीलिंग्स के साथ एसोसिएट करना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह क्या हो रहा है? इतनी मीठी जुबान में बात करते समय शोर नहीं मताइये। आप बातों में मिठास लाइये। बेग जी बोलिये।

डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग: मैडम, मैं हाऊस की फीलिंग्स देखकर अपने आपको एसोसिएट करता हूं। हम बहुत एनकरेज फील कर रहे हैं मगर जबानी जमा-खर्च से कुछ नहीं होगा।



काइन्डली इसकी तरफ तव्वजो दी जाये। यह भाषा हमारी तहजीब, हमारी तमदुन से जुड़ी हुई है। हमारी जड़ें इस जुबान के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उर्दू के साथ इंसोफ किया जाय। पूरा हाऊस कह रहा है कि उर्दू के साथ इंसोफ करें। मगर प्रैक्टिकली यह हो रहा है कि उर्दू भाषा में जो न्यूजपेपर शायी होते हैं, उन्हें एडवरटीजमेंट्स नहीं मिलते हैं, उन्हें कोई एनकरेजमेंट नहीं मिलता है।

महोदया, इसके लिए आपकी तरफ से डायरेक्शन आना चाहिए। यह सारे हाऊस का कंसर्न है कि इस जुबान के साथ नाइंसाफी हुई है, इम्तियाज हुआ है, इसे हमारी तहजीब और हमारी तमदुन के साथ जुड़ी हुई जुबान समझा जाये और इसकी फरोग के लिए आज से ही तमाम इक्दामात उठाये जायें, जिससे इस हिन्दुस्तान की जुबान को एक ऐसा वकार मिले, जिसकी यह पूरी हकदार है। धन्यवाद।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला): महोदया, मैं उर्दू में बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदया : आप उर्दू में ही बोलिये।

डॉ. फ़ारुख़ अब्दुल्ला : महोदया, मैं खासकर शत्रुघ्न सिन्हा साहब से कहना चाहता हूं क्योंकि ये फिल्मी दुनिया को रिप्रजेंट करते हैं। उर्दू को अगर किसी ने जिन्दा रखा है तो वह हिन्दुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है। मैं आज सारे सदन में यह कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग नहीं होते तो उर्दू कब की मर गयी होती। मैं तहे-दिल से आपकी सारी इंडस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हिन्दुस्तान में उर्दू उसी तरह चमकेगी जिस तरह बाकी जुबानें चमक रही हैं। ऐसा होगा और इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं वित्त मंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि हिन्दुस्तान की केंद्र सरकार को ज्यादा से ज्यादा एडवरटीजमेंट उर्दू के अखबारों को देने चाहिए, जिससे ये अखबार जिन्दा रह सकें नहीं तो ये मर जायेंगे।...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): महोदया, यह पहला मौका है जब हाऊस के सभी साइड्स और विशेष रूप से बीजेपी के डिप्टी लीडर ने भी उर्दू के लिए अपना समर्थन दिया है।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): हमने कभी विरोध नहीं किया है।...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैं आपकी तारीफ़ ही कर रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं। विशेष रूप से बीजेपी के डिप्टी लीडर ने भी अपना समर्थन उर्दू के लिए दिया, जो बहुत ही खुशी की बात है। अफसोस की बात यह है कि अभी दस-बारह दिन पहले पूरे देश के उर्दू के जो पत्रकार दिल्ली में हैं, वे मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि अगर इस उर्दू जुबान को जिन्दा रखना है तो उर्दू चलाने वाला पत्रकार या एडिटर, एडिटर भी वही होता है, प्रिंटर, पब्लिशर और प्रोपराइटर भी वही होता है और वह गरीब होता है। प्रिंटर, पब्लिशर, प्रोपराइटर और एडिटर एक ही आदमी क्यों होता है? वह इसलिए होता है क्योंकि वह गरीब है। वह इतना

पैराफरनेलिया नहीं रखता है। कभी-कभी कॉर्रेस्पान्डेंट भी खुद ही होता है। ऐसा गरीबी की वजह से होता है। बहुत साल पहले जब 1990 के दशक में हमारी वर्ष 1996 तक सरकार थी तो पूरे देश में उन्हें विज्ञापन मिलते थे, लेकिन बीच में कम हो गये। रीजनल भाषाएं बहुत अच्छी हैं। हमारी रीजनल भाषाएं बहुत सी हैं। मैं बहुत चाहता हूं कि तमिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी, गुजराती, सभी रीजनल भाषाएं फले-फूलें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप शांत होकर सुनिये।

श्री गुलाम नबी आज़ाद : जिन राज्यों में रीजनल भाषाएं हैं, उनके 90 प्रतिशत विज्ञापन उन भाषाओं में ही दिये जाते हैं, लेकिन उर्दू की कोई पार्टिकुलर स्टेट नहीं है। इसलिए उसे विज्ञापन कहां से मिलेंगे? उर्दू पूरे हिन्दुस्तान की भाषा है। आप बंगाल में देखिये, नम्बर वन ए क्लास के अखबार कोलकाता से निकलते हैं। ये आज से नहीं, आजादी के समय से निकलते हैं और ये आजादी की जद्दोजहद में शामिल थे। हैदराबाद साउथ में है और सबसे बड़े पेपर वहां से निकलते हैं, बेंगलुरु साउथ में है, वहां से उर्दू के पेपर निकलते हैं, मुम्बई से उर्दू के पेपर निकलते हैं, पटना से उर्दू के पेपर निकलते हैं, लखनऊ से उर्दू के पेपर निकलते हैं, चेन्नई से निकलते हैं। चार साउथ इंडियन स्टेट्स है, उन सभी राज्यों से उर्दू के पेपर निकलते हैं, ईस्ट के स्टेट्स से उर्दू के पेपर निकलते हैं।

पंजाब केसरी तो 20 साल पुराना है, लेकिन हिंद समाचार जो कि उर्दू का सबसे बड़ा पेपर है, उसका असली वर्जन आजादी से पहले का है। यह दिल्ली से पेपर निकलता था...(व्यवधान)

श्री हुस्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): सरकार आपकी है तो आप कर लीजिए। आप हमें क्यों सुना रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : इसमें सरकार को ही देना ही होगा।...(व्यवधान)

श्री हुस्मदेव नारायण यादव: आपकी सरकार है। आप उनको कहिए...(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैंने कल इस बात को कहा था। आप मेरे जवाब के समय मौजूद नहीं थे। कल वित्त मंत्री जी और मैंने जवाब दिया कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट केवल केन्द्रीय सरकार नहीं कर सकती है।...(व्यवधान) अब 70 का दशक नहीं है, जब केन्द्र और राज्यों में एक पार्टी की हुकूमत होती थी। आज सभी पार्टियां विपक्ष में हैं और सभी पार्टियां सत्ता में हैं, क्योंकि किसी राज्य में एक पार्टी सत्ता में है तो दूसरे राज्य में विपक्ष में है। इसलिए उर्दू को केवल केन्द्रीय सरकार के स्तर पर ही नहीं बल्कि सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में इसकी सहायता करनी होगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यदि आप बहस करना मुनासिब समझते हैं तो नोटिस भेज दीजिए। इस पर पूरी बहस हो जाएगी। अभी हम शत्रुघ्न सिन्हा जी को फ्लोर देते हैं।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : हम चाहते हैं कि आप इस पर चर्चा स्वीकार करें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बोल चुके हैं। अब आप इनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (पटना साहिब): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहली बात यह है कि मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत बढ़िया विषय उठाया और दुखती रग पर हाथ रख दिया है। आज उर्दू के साथ जो हो रहा है, जैसा गोपीनाथ मुंडे जी कह रहे थे, उर्दू हमारी भाषा है, यह किसी धर्म विशेष की भाषा नहीं है। उर्दू हर धर्म की भाषा है, उर्दू मानवता की भाषा है, उर्दू प्रोग्रेस की भाषा है और उर्दू हिन्दुस्तान की भाषा है। अभी फिराक गोरखपुरी का जिक्र किया गया। फिराक गोरखपुरी ने अपनी पूरी जिन्दगी उर्दू की खिदमत में लगा दी। मेरा ख्याल है कि भारतवर्ष में गालिब के बाद उर्दू में सबसे ज्यादा किसी का नाम है, तो वह फिराक गोरखपुरी साहब का है। अभी जैसा कि हमारे भाई फारूख अब्दुल्ला साहब ने कहा कि फिल्मों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, यकीनन भाषा के मामले में चाहे हिन्दी हो, चाहे उर्दू हो, दोनों हमारी अपनी भाषाएं हैं, इनके प्रमोशन में, प्रोटैक्शन में, प्रोजेक्शन में अगर सबसे ज्यादा किसी का हाथ है, तो हमारी भारतीय फिल्मों का है। भारतवर्ष का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है और शायद कोई ऐसा नागरिक नहीं है, जो अपने आम जीवन में रोज़ाना उर्दू का प्रयोग नहीं करता हो। आम आदमी तखलिया हो या तनहाई हो, आम आदमी हो या खास आदमी हो, जो भी वह सब उर्दू है। उर्दू-हिन्दी का इतना अच्छा संगम है कि हम गंगा-जमुनी तहजीब की बात कहते हैं। गंगा-जमुना तहजीब की तरह से एक दूसरे में समावेश है। यह हमारी भाषा है, भारतवर्ष की भाषा है। अब इसके लिए आगे सरकार क्या कदम उठा रही है, इसको आगे कैसे और मजबूत करेगी, कैसे इसका और प्रचार-प्रसार हो, कैसे इसको उरुज़ तक लेकर जाएं। सरकार इसके साथ न्याय कर रही है या नहीं कर रही है? हमारे उर्दू के अखबार पूरे देश में निकलते हैं, पटना में हैं, चेन्नई में हैं, महाराष्ट्र में हैं, दुनिया के हर कोने में हैं।...(व्यवधान)

यू.पी., बंगाल, चेन्नई और महाराष्ट्र से लेकर नार्थ इंडिया, नार्थ-ईस्ट, वेस्ट और साउथ सब जगह है, लेकिन क्या उर्दू के अखबारों को जो समर्थन मिलना चाहिए, वह हमारी और हमारी सरकार की तरफ से मिल रहा है? क्या उर्दू भाषा को स्कूल और कॉलेज में जो एहमियत मिलनी चाहिए, वह वहां मिल रही है और अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि यह हमारी भाषा है, आम आदमी की भाषा है,



फिल्मों की भाषा है, आपकी और पूरे पार्लियामेंट की भाषा है, सब की भाषा है। देश में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा, मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ, जो एक वाक्य भी उर्दू की बैसाखी के बगैर पूरा करता हो, कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है, यानी उर्दू बैसाखी भी है, यह हमारा साथ भी देती है, यह हमारे साथ है। उर्दू सदियों से चली आ रही है, मैं समझता हूँ कि सरकार को इसके लिए आगे कुछ और ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। उन अखबारों की और हौसला अफजाही करनी पड़ेगी, उनको बढ़ाना पड़ेगा। उर्दू का प्रचलन स्कूल, कॉलेजेस में तथा हर जगह होना चाहिए। आज हम जैसे संस्कृत और हिन्दी पर जोर दे रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं तो उतना ही उर्दू पर भी जोर देना चाहिए। धन्यवाद।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Madam, I would like to say one thing.

MADAM SPEAKER: Let these two Members also speak and then you can respond.

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, आपको हम हमेशा मौका देते हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त (घाटल): अध्यक्ष महोदया, हम यह कहना चाहते हैं कि उर्दू हिन्दुस्तान की मेहनतकश जनता की भाषा है। उर्दू की तरक्की के लिए सरकार की तरफ से कार्यवाही करना जरूरी है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैडम, हम यह बात बोलना चाहते हैं कि सिर्फ एडवरटाइज़मेंट नहीं, उर्दू की प्रमोशन और तरक्की के लिए हम हिन्दुस्तान में ज्यादा उर्दू अकादमी मांगते हैं।...(व्यवधान)

मैडम, हम चाहते हैं कि उर्दू भाषा की तरक्की के लिए सरकार कार्यवाही करे और हिन्दुस्तान की जनता की तरक्की के लिए उर्दू का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया जाए। हिन्दी के साथ उर्दू को भी स्थान दिया जाए, यह मेरी सरकार से अपील है।...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदया, उर्दू एक भारतीय भाषा है और यह सबसे मीठी भाषा है। उर्दू भाषा-भाषी हमारे देश के हर प्रांत में हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ बसुदेव आचार्य जी की बात ही रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री बसुदेव आचार्य: देश आजाद होने के बाद उर्दू को केन्द्रीय सरकार की तरफ से जितनी सहायता मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली।...(व्यवधान) उर्दू भाषा के विकास और प्रमोशन के लिए उतना समर्थन नहीं मिला।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Do not start giving a long lecture. You have to just associate yourself with it. Members have given notices to raise matters under 'Zero Hour'.

एक माननीय सदस्य: उर्दू का सपोर्ट हिन्दी में हो रहा है, धन्यवाद।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: उर्दू भाषा हमारे देश की भाषा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपने बोल लिया है, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसके विकास के लिए केन्द्र सरकार को और ज्यादा मदद देनी चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।



...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हमारे बंगाल में उर्दू अकादमी चालू हुई है, हर राज्य में उर्दू अकादमी चालू होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, उर्दू के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है कि उर्दू के विकास के लिए हर तरह का कदम केन्द्र सरकार को उठाना चाहिए। मैं माननीय मुलायम सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने आज यह महत्वपूर्ण मामला सदन में उठाया है।...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing would go on record now.

(Interruptions) ... *

 **रेल मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी):**  मैडम स्पीकर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मौके पर बोलने का अवसर दिया। मैं, जनता की मदद, इशारे, मेहरबानी, दुआ और कामयाबी से इस हाउस की बहुत समय से मैम्बर हूँ। आज उर्दू भाषा के बारे में हाउस में जो चर्चा हो रही है, वह इससे पहले मुझे देखने को नहीं

* Not recorded.

मिली। इसलिए मैं श्री मुलायम सिंह जी और हर मैम्बर को इसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। Urdu is a sweet language. I love this language.

मैं कहना चाहती हूँ कि उर्दू की जो शायरी होती है, वह सबकी जुबान पर होती है। उसका एक-एक शब्द हमारी जुबान से बुलन्द होता है। जैसे हिन्दी हमारे देश की एक महत्वपूर्ण लैंग्वेज है, वैसे ही हर प्रदेश की अपनी लैंग्वेज होती है और विशेष रूप से उर्दू। मैं कहना चाहूंगी कि रोजा का महीना भी आ रहा है। इसलिए उर्दू की तरफ ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। मैं कहना चाहूंगी कि-

“खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तदबीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।”

जब हम आज उर्दू लैंग्वेज के बारे में डिसकशन कर रहे हैं, तो दो-तीन बातें बहुत जरूरी हैं। एक तो उर्दू अखबारों को जो एड दिया जाता था, जिसे बन्द कर दिया गया है, उसे चालू किया जाए। इसमें बहुत गरीब आदमी बहुत कम संसाधनों से काम करते हैं। दूसरी बात है कि हमारे देश में मदरसों की बहुत जरूरत है। टीचर्स नहीं मिलते हैं। हमारे देश में कई जगह ऐसी हैं जहां 10 परसेंट लोग उर्दू स्पीकिंग हैं। हमारे कोलकाता में तो बहुत हैं। जैसे आसनसोल, दुर्गापुर, बानपुर, हावड़ा, बैरकपुर और इस्लामपुर एरिया जैसे बहुत एरियाज हैं, जहां उर्दू ज्यादा बोली जाती है। वहां हमारी बंगाली लैंग्वेज से भी ज्यादा उर्दू जुबान बोलते हैं, लेकिन स्कूलों में उर्दू पढ़ने के लिए कोई लैंग्वेज एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए जहां 10 परसेंट लोग उर्दू पढ़ते हैं और बोलते हैं, वहां उर्दू लैंग्वेज को स्कूलों एवं यूनिवर्सिटीज में कम्पलसरी करना जरूरी है। मैं चाहती हूँ कि उर्दू यूनिवर्सिटीज भी हों। उनमें उर्दू स्टूडेंट्स को ज्यादा स्पोसरशिप देनी चाहिए।

उर्दू को प्रोटेक्शन देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को सरकारी मदद देने की बहुत जरूरत है, फिर चाहे वह बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मराठवाड़ा, तामिलनाडु, बंगाल हो अथवा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश का कोई भी क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में उर्दू लैंग्वेज बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। हमारे देश में उर्दू भाषा बोलने वाले बहुत सारे आदमी हैं। हमारी स्टेट में 30 परसेंट के करीब लोग उर्दू बोलते हैं जिसमें मायनारिटी कम्युनिटी भी शामिल है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश और बिहार में 11 परसेंट है।


श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, उत्तर प्रदेश में उर्दू यूनीवर्सिटीज बनाई गई हैं। इसलिए जैसा उत्तर प्रदेश में किया गया है, वैसा ही उर्दू की बेहतरी के लिए सब प्रदेशों में किया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : बहुत अच्छा है। यदि किसी प्रदेश ने ऐसा किया है, तो ठीक है। मैडम, मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रदेश ने उर्दू के लिए काम नहीं किया है, वहां यह करना जरूरी है। उर्दू लैंग्वेज को बढ़ावा देने, प्रोटेक्शन देने और कम्पलसरी करने के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव प्लान बनाना जरूरी है, जिससे मायनॉरिटीज को भी लगे कि उनकी भाषा भी बढ़ रही है।

मैडम, जब मैं रेल मंत्री बनी, तो एक छोटा सा मौका मेरे सामने आया। उसी समय मैंने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षाएं देने के लिए अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-साथ उर्दू लैंग्वेज को भी कम्पलसरी कर दिया और उसमें ऑल रीजनल लैंग्वेज को भी जोड़ दिया। इस प्रकार से उर्दू को प्रोटेक्शन देकर आगे बढ़ाने की जरूरत है।

मैडम, इसके अलावा एक बात और है। मायनॉरिटीज की पॉपुलेशन इन्क्रीज हो रही है। जैसे शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स तथा ओ.बी.सी. की इन्क्रीज हुई पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाती है, वैसे ही मायनॉरिटीज की बढ़ी हुई पॉपुलेशन के अनुसार रिजर्वेशन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही, अन्त में, मैं कहना चाहती हूँ कि इस विषय पर आज हम लोगों को डिस्कशन का मौका मिला है, यह बहुत अच्छा डिस्कीजन है।

It is a very good decision. हम कहना चाहते हैं कि उर्दू को ज्यादा प्रोटेक्शन देने की जरूरत है।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आजादी की लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ी है, लेकिन जो हमारी परंपरा है, उसके लिए उन्होंने लड़ा है - चाहे गांधी जी हों, चाहे नेता जी हों, चाहे अबुल कलाम आजाद हों, चाहे अंबेडकर हों, चाहे लाल-बाद  हों, चाहे राजेन्द्र प्रसाद हों, चाहे हमारे देश के कोई भी लीडर हों, लेकिन बात यह है कि अब्दुल खान गफ्फार की लड़ाई को हम लोग याद नहीं करते हैं। जब हमारे देश में वर्ष 1857 में सिपाही युद्ध हुआ था, तब झांसी की रानी लक्ष्मी बाई, टीपू सुल्तान ने जाकर

बहादुर शाह जफर को कहा कि आप आइए और देश की आजादी की लड़ाई में साथ दीजिए। बहादुर शाह जफर ने उनके साथ ज्वाइन किया था। लेकिन बाद में इंडियन्स ने उसके दो लड़कों का मर्डर किया था। बहादुर खान जफर के देहांत होने के बाद उन्होंने एक शायरी लिखी थी कि

“कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमीन भी न मिल सकी कूँचा-ए-यार में।”
यह हमको याद करना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि

“मुद्दई लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है।”
उर्दू लैंग्वेज को हम लोग पसंद करते हैं, इसीलिए कहना चाहती हूँ कि इसको खत्म मत करिए। इसको प्रोटेक्शन दीजिए। यह बात फिल्म में भी है। जनता का भी यही कहना है।

अंत में कहना चाहूंगी कि

“सरफरोशी की तमन्ना आज हमारे दिल में, देखते हैं जोर कितना बाजू-ए-कातिल में हैं”

With these words, I thank you very much for giving me this opportunity.

श्री हुस्मदेव नारायण यादव : बिहार में भी चुनाव होने हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब मुझे बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब हम खड़े हो गए हैं। जब स्पीकर खड़े हो जाएं, तो आप बैठ जाएं, ऐसा डेकोरम भी हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप इसे जानते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इस समय सभी मैम्बरान ने उर्दू जुबान की जो हालत है, उर्दू अखबारनवीसों की जो हालत है, उसे लेकर अपनी फिक्र जाहिर की है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार इस ओर पूरी तरह से तवज्जो दे।

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam Speaker, I entirely agree with the sentiments expressed by the hon. Members including some of my distinguished colleagues in the Cabinet. There are no two opinions... (*Interruptions*) मुझे माफ कीजिए। I would have loved to speak in Urdu, but... (*Interruptions*)

श्री शत्रुघ्न सिन्हा : आपने माफ शब्द बोला, यह भी उर्दू ही है। ...(*व्यवधान*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE : Therefore, I do agree that we are a part of a rich heritage of which Urdu is an integral part. Therefore, I can assure you that the Government will take steps to strengthen this language which is a part of a great national heritage. Already the hon. Prime Minister has instructed the Ministry of Information and Broadcasting to ensure that the Urdu newspapers and other media get due share in their Government funded advertisements of all departments and Ministries which are being routed through the DAVP. Normally the House is divided on issues, but this is one occasion when the entire House was totally united and expressed its solidarity with it. Therefore, keeping that in view, I can assure you Madam and through you to the House that all proper steps will be taken.

13.29 hrs

*The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Thirty Minutes
past Fourteen of the Clock.*

14.30 hrs.

*The Lok Sabha reassembled after lunch at
Thirty Minutes past Fourteen of the Clock*

(Mr. Deputy Speaker in the Chair)

...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना): उपाध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन सुन लीजिए। हम जीरो आवर का नोटिस देते हैं। वह बड़ी मुश्किल से लाटरी में आता है, लेकिन फिर भी यहां बोलने का अवसर नहीं मिलता। यह सभी सदस्यों की शिकायत है। आप कोई समय निर्धारित कर दीजिए जब सदस्य अपनी बात कह सकें। सभी दलों के बड़े नेता किसी न किसी विषय पर रोज बोल लेते हैं, लेकिन जो नए सदस्य आए हैं और नोटिस देते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से बैलेट में नाम आता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको छः बजे बोलने का समय दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : छः बजे बहस चलती रहती है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आज नहीं चलेगी।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : छः बजे बहस चलती रहती है और सरकार की तरफ से यह कहा जाता है कि काम पूरा करने दीजिए, उसके बाद जीरो आवर लेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी काम रोककर छः बजे जीरो आवर ले लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारी प्रार्थना है कि जीरो आवर का एक समय तय कर दीजिए। उस समय सदन की सब कार्यवाही रोककर जीरो आवर ले लिया जाए और उसके बाद दूसरी कार्यवाही ली जाए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : छः बजे के बाद जीरो आवर हो जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : अगर आज छः बजे जीरो आवर नहीं लिया जाएगा तो सदन का काम नहीं चलने देंगे।...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि छः बजे जीरो आवर लेंगे।...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : श्रीमान्, मोस्ट इम्पोर्टेंट पांच जीरो आवर को स्पीकर साहब पहले ले लेते थे और शेष बाद में लेते थे। तीन दिनों से वह भी बंद है और तीन दिनों से कोई जीरो आवर नहीं लिया जा रहा है। हम साढ़े आठ बजे बिना नाश्ता-पानी किए भाग-भागकर आते हैं। हमें क्यों दौड़ाया जाता है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : छः बजे बाकी काम बंद करके जीरो आवर लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : हमारे लिए सरकार के बिजनस से ज्यादा जीरो आवर महत्वपूर्ण है।...(व्यवधान) हम अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण जन-समस्या को उठाते हैं। हमारे क्षेत्र के लोग आंख लगाकर देखते रहते हैं।...(व्यवधान)

14.34 hrs

MATTERS UNDER RULE 377 *

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over slips at the Table of the House within twenty minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed.

(i)Need to bring a Central legislation to regulate the service conditions of Nurses working in various parts of the country

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Nurses constitute a vital part of medical sector everywhere in the world. A society cannot withstand without their service. But they are being dishonored and harassed in society. Nursing is such an area that can afford employment to lakhs of youth in the country, where unemployment is a major challenge. But those who select the nursing field, are always belong to average family, whose parents expect job surety and a stable income after the completion of the course and it is a fact that more than 95% of the nursing students finish their course with the help of educational loan. But once they complete the course, they are forced to work, mostly in private hospitals with a very low remuneration and inflexible service conditions which accompany a bond with hospital management. Under these circumstances, they are being forced to work over time with meagre compensations. Their service is considered as very precious, and at the same time they are facing miserable conditions, in every part of the country. Unfair working conditions, low salary and oppressive working

* Treated as laid on the Table.

schedule are the major problems in this field. Indeed these are utter violations of human rights. Hence, the Central Government should bring a legislation to ensure legitimate salary, justifiable service rules and regulations along with better occupational circumstances for the Nurses in national perception.

(ii) Need to set up Centrally Sponsored Surveillance Committees with local MPs as members to monitor the programme of Centrally Sponsored Schemes

डॉ. संजय सिंह (सुल्तानपुर): देश के क्षेत्रीय विकास एवं लोगों के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनेक केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, जिस पर अरबों रुपये खर्च हो रहा है। कई क्षेत्रों में केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यक्रम की सूचना स्थानीय सांसद को नहीं मिल पाती है। जिसके कारण लोगों के विकास के लिए जो काम होने चाहिए और विकास कार्य के लिए जिन कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, वे नहीं हो पाते हैं क्योंकि स्थानीय सांसदों को इन केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों को सही ढंग से करवाने एवं उनके अच्छे परिणाम प्राप्त करने में स्थानीय सांसदों की कोई भूमिका नहीं है। सांसद केवल सदन में प्रश्न उठाकर एवं शिकायत करके अपनी भूमिका निभाते हैं, जिन पर कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं होती है। विकास कार्य एवं लोगों के कल्याण संबंधी केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए आवश्यक है कि ग्रामीण विकास संबंधी निगरानी कमेटी की तर्ज पर केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम में निगरानी कमेटी बनाकर स्थानीय सांसदों की भूमिका निभाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अच्छे परिणाम के लिए केन्द्र प्रायोजित निगरानी कमेटी बनाकर उसमें ग्रामीण विकास संबंधी निगरानी कमेटी की तर्ज पर स्थानीय सांसदों को निगरानी करने हेतु मौका दिया जाये।

(iii) Need to introduce the Bill for categorization of Scheduled Castes into A,B,C and D groups in Andhra Pradesh

DR. MANDA JAGANNATH (NAGARKURNOOL): There was an agitation for categorization of Scheduled Castes into ABCD groups in Andhra Pradesh, under the auspice of Madiga Reservation Porata Samiti (MRPS), consequent to which Justice (Retd.) Usha Mehra Commission was constituted by Government of India to go into all aspects of sub-categorisation of Scheduled Castes based on their population in the State.

The Commission had submitted its Report to Government of India on 1.5.2008 and with a recommendation to amend Article 341 of Constitution. This matter was raised by me in the Lok Sabha on 9.3.2010 and the Hon'ble Minister of Social Justice and Empowerment sent me the letter dated 12 April, 2010 saying that the matter is under the consideration of Government of India.

Though two years have passed since the submission of Report by the Justice (Retd.) 'Usha Mehra' Commission but no action is forthcoming from the Government of India. I request, the Government of India to take necessary steps to introduce the Bill in the current Session to categorise the Scheduled Castes in Andhra Pradesh into ABCD Groups.

(iv)Need to take steps for revival of Damodar Valley Corporation in West Bengal

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Damodar Valley Corporation is recognized as the 1st Public Sector Undertaking in Independent India. The multipurpose river valley project bears its unique distinction which was conceived by Pundit Lawahar Lal Nehru.

But the age old standard bearer of PSU is now suffering from paucity of funds and virtually grasping for its survival in spite of all the potentialities it hold.

A couple of power units of DVC are crippled due to the acute shortage of coal. It is reported that inadequate supply of Coal rakes from Coal India/ BCCL has been further hindering the availability of coal.

Coal Rakes on the way to Thermal Power Plant are being systematically looted thereby creating shortage of coal. As a result the Mega Thermal plant is compelled to discontinue it's prescribed programme.

The Central electricity Regulatory Authority has also imposed a huge penalty on DVC to the tune of Rs.5000 crores. Now its incumbent upon the Government to save the DVC from the financial crisis.

)

(v) Need to ensure the safety of Railway passengers in the country

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I would like to draw the attention of the Railway Ministry towards the incidents of robbery in trains which has become order of the day. Unscrupulous criminals befriend the bona-fide passengers and administer them drugs and psychotropic substances in foods and drinks. Because of this kind of inhuman activities not only the valuables of the bona-fide passengers are lost but they also lose their lives. Railways which earns revenue from the passengers for travel have the responsibility to ensure the safety of the passengers. Immediate steps need to be taken to protect the passengers from criminals. I, therefore, suggest to the Minister of Railways that whenever the person boards the train with a reserve ticket, the train ticket examiner while checking the tickets should obtain his thumb impression in a given format and that record should be kept till the journey is over. This measure will cost nothing to the Railways. Further, video coverage for obtaining photograph of those passengers who perform journey in reserve compartments is also an effective method to check the incident of robbery in train. I, therefore, urge upon the Minister of Railways to take such measures which will ensure the safety of bona-fide railway passengers in the country.

(vi) Need to review the decision of Divisional Railway Manager, Dhanbad and re-open the various closed railway crossings and VIP parking at Dhanbad in Jharkhand

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): पूर्व मध्य रेल के फुसरो रेलवे क्रॉसिंग, चन्द्रपुरा स्टेशन का मानव रहित समपार, नेशनल अंगार पथरा कतरासगढ़ का रेल समपार और धनबाद रेलवे स्टेशन का वी.आई.पी. पार्किंग स्थान मंडल रेल प्रबंधक धनबाद द्वारा बंद कर दिया गया है, जिसके कारण आमजन काफी परेशान हैं। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के लोगों द्वारा बंद और हड़ताल का आयोजन किया गया। रेलवे के अधिकारियों ने पुनः सेवाएं बहाल करने हेतु आश्वस्त किया था लेकिन आज तक इस संबंध में सार्थक परिणाम नहीं आए हैं। इस व्यवहार से जनक्रोध बढ़ रहा है। इस संबंध में हमने अध्यक्ष रेलवे बोर्ड और अन्य

संबंधित अधिकारियों से साक्षात्कार कर मामले पर विस्तृत चर्चा की है और समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों की प्रति के साथ अपने पत्र के माध्यम से उक्त बंद सेवाओं को पुनः बहाल करने का आग्रह किया है। अभी तक उक्त अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई का सार्थक परिणाम नहीं मिला है। आंदोलन एवं हड़ताल से रेल राजस्व की क्षति होती है और जन सुविधाएं बाधित होती हैं।

अतः सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त बंद सुविधाओं को जनहित में पुनः चालू कराने हेतु शीघ्र आवश्यक निर्देश सक्षम अधिकारी को जारी करने की कृपा की जाये।

(vii) Need to accord permission for opium farming in Himachal Pradesh

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अफीम अपने आप में एक सामाजिक बुराई जरूर बनी, लेकिन औषधीय विज्ञान में इसका नाम सबसे ऊपर आता है। यह केवल नशे के लिए ही प्रयुक्त नहीं होती है, बल्कि आयुर्वेद, आयुष, होम्योपैथ एवं एलोपैथिक दवाओं में बहुतायत से प्रयोग की जाती है। हमारे देश में दो-तीन प्रदेशों में इसकी खेती के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन एवं वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पहले अफीम की खेती बहुतायत में होती थी, लेकिन कतिपय कारणों से उसे बंद कर दिया गया है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश के किसानों की स्थिति दयनीय हो गई है। हिमाचल प्रदेश की जलवायु, विशेष रूप से सिरमौर जिला अफीम की खेती के लिए सर्वथा उपयुक्त है एवं वहां बहुत अच्छी पैदावार हुआ करती थी। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, विशेषकर सिरमौर, शिमला, मंडी और कुल्लू आदि जिलों में अफीम की खेती किए जाने की अनुमति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान की जाये।

(viii) Need to provide special financial package to Bihar for the over all development of the State

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): बिहार आज कई दृष्टियों से पिछड़ा राज्य है जबकि विकास संबंधी सारे तत्व यहां मौजूद हैं। बिहार की भूमि की उर्वरता अन्य राज्यों की अपेक्षा ज्यादा है। बिहार के पिछड़ेपन की वजह से सबसे ज्यादा गरीब लोग बिहार में रहते हैं। यहां के लोगों की औसत आय अन्य राज्यों की औसत आय से बहुत ही कम है। औद्योगिकीकरण हेतु कच्चा माल भी बिहार में उपलब्ध है। अत्यंत गरीबी एवं उद्योगों के अभाव के कारण बिहार के लोगों का पलायन अन्य राज्यों को हो रहा है। बिहार में चीनी आधारित उद्योग, एथनोल आधारित उद्योग, स्टील उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की अपार संभावनाएं हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार की संस्कृति एवं बिहार में जन्मे लोगों ने विश्व को एक नई दिशा प्रदान की है। अगर केन्द्र सरकार बिहार में निरक्षरता, उद्योगों के पिछड़ेपन एवं बाढ़ की समस्या के स्थाई निराकरण हेतु आर्थिक सहायता पैकेज दे तो बिहार की गरीबी को दूर किया जा सकता है एवं यहां के लोगों की औसत आय को अन्य राज्यों के समान किया जा सकता है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर आर्थिक सहायता पैकेज दिया जाये।

**(ix)Need to display banners & signages in Hindi language
during Commonwealth Games**

श्री हुस्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): दिल्ली में राष्ट्रमंडल देशों का खेल होने जा रहा है। उसमें हजारों करोड़ रुपये खर्च होने जा रहा है। परंतु, खेद की बात है कि राजभाषा हिन्दी की उपेक्षा की जा रही है। देश भर के हिन्दी प्रेमियों, साहित्यकारों और राष्ट्र के स्वाभिमानी नागरिकों को इस बात से क्षोभ है। कनॉट प्लेस में निजी दुकानों के साइनबोर्ड सरकारी खर्च से बनवाये जा रहे हैं। उस पर पहले हिन्दी में लिखा जाना चाहिए। राजभाषा अधिनियम के तहत दिल्ली "क" क्षेत्र में है, जहां सौ फीसदी काम हिन्दी में होना है। सभी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग, पम्फलेट और प्रचार सामग्री हिन्दी में बनवाये जायें। पुलिस के दिशा-निर्देश सूचक पट्टिकाएं हिन्दी में लिखवाये जायें। उद्घाटन और समापन के कार्यक्रम हिन्दी में किये जायें। कमेन्ट्री सभी हिन्दी में की जायें। सरकार और आयोजन समिति इस पर ध्यान दें।

(x) Need to complete the construction of various roads in Madhya Pradesh which are pending with Ministry of Road Transport and Highways

श्री गणेश सिंह (सतना): भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय में मध्य प्रदेश की विभिन्न मर्दों में सड़कों की स्वीकृति लम्बित है। मैं जानना चाहता हूँ कि कल कितने प्रस्ताव राज्य सरकार ने भेजे तथा उनमें से कितनों पर स्वीकृति दी गई है। शेष सड़कों की स्वीकृति कब तक होने वाली है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्र० 75 में सतना नगर में एक बाईपास बनाने का प्रस्ताव लम्बे समय से विचाराधीन है, उसकी स्वीकृति तथा राष्ट्रीय राज्यमार्ग 7 एवं 75 के 4 लाईन सड़क बनाने पर जो विचार हो रहा था, उस पर क्या प्रगति है।

मैंने केन्द्रीय सड़क निधि से अपने क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर से बगहाई, हिनौती, घुंघचिहाई, खमहरिया, अकौना, अवेर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति तथा अंतर्राष्ट्रीय सड़क योजना में सतना से सेमरिया इलाहाबाद मार्ग के निर्माण की मांग की थी, जिस पर क्या कार्यवाही हुई, जानना चाहता हूँ।

(xi) Need to direct the banks of the country to follow the guidelines issued by Reserve Bank of India in order to allow the students from minorities to open scholarship accounts in various banks

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): There are disturbing reports that banks are not allowing Muslim students to open scholarship accounts. In 2005, the RBI issued guidelines to banks for opening ‘No-frills accounts or Nil balance accounts’. These guidelines are still in operation. If banks are reluctant to do so, this is clear violation of Government directives. In Andhra Pradesh, banks have refused to open accounts of Minority Students. About 90,000 Muslim Students could not open their accounts. The Hindu newspaper has reported that there is a sharp decline in the number of bank accounts opened by the Minorities in some states. A Reserve Bank of India report states that the number of bank account holders in the 121 Minority Concentration Districts increased by a mere four per cent during 2008-09 compared with that of 83.80 per cent during 2007-08. It means the banks in minority districts are not adhering to the RBI lending norms for the minorities.

Keeping in view of the above, I sincerely appeal to the Central Government to take this matter seriously and with utmost urgency in the national interest and direct the banks to adhere to the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

(xii) Need to keep alive Subarnrekha Sanskar Project in the pendency list of the Central Water Commission

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): A proposal regarding Subarnarekha Sanskar Project amounting to Rs. 970.28 Crores was submitted by the Government of Orissa to Director, Union Territory Directorate, Central Water Commission, New Delhi during December, 2008. Subsequently as per the observation of Hydrology Directorate, Cost Engineering Directorate and Interstate Directorate of Central Water Commission, the revised Detailed Project Report (DPR) along with compliance to the observation of CWC amounting to Rs. 933.16 crores have been submitted by the Government of Orissa to Central Water Commission. Again as per further observation dated 7.1.2010 of Hydrology Directorate, compliances have been submitted to Central Water Commission. In the meantime, the project has been placed in the 112th Technical Advisory Committee (TAC) of State Flood Control Board and approved by Government in Department of Water Resources. Also the project was placed and approved by the State Flood Control Board on 19.3.2010 under the Chairmanship of Hon'ble Chief Minister of Orissa. The observation of Central Water Commission now made vide their letter dt. 30.3.2010 are being complied. In this context request has been made by the State Government to Central Water Commission that the proposal may not be delisted from the pendency list of the project for the time being. After compliance to observations of Central Water Commission and collection of requisite data from the field authorities, the revised DPR will be prepared by the State Government and submitted to Central Water Commission for examination. Therefore, I urge upon the Government not to delete the above proposal from the pending list of the project for the time being.

(xiii) Need to expedite approval of proposed transfer of State Government land of Nizam Bunglow premises to Defence (Army) in exchange of defence land for four laning of State Highway No. -60 in Maharashtra

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I would like to draw the attention of the Union Government to the urgency and importance of four-lane widening of the Golwadi Crossing (KM 223.600) to Nagar Naka (KM 228.750) section of Aurangabad-Ahmednagar-Pune (SH No.60). This is a very important road having very high traffic density. This stretch gets congested and accidents occur on this road due to heavy traffic which flows from Aurangabad city to Waluj Industrial Area. The four lane widening work of Waluj to Golwadi was completed 12 years ago. The remaining stretch from Golwadi to Nagar Naka is presently two lane only due to non-availability of Defence land on time.

A proposal for transfer of State Government land of Nizam Bunglow premises to Defence (Army) in exchange of Defence land has been mooted and agreed to by the State Government of Maharashtra, World Bank Project Division and other Stakeholders of this project. Speedy approval by the Union Government for this land's transfer proposal would expedite the four laning work of this stretch of SH No. 60.

In view of the above, I urge upon the Union Government to expedite necessary approval for the above mentioned land transfer proposal in the public interest.

14.35 hrs.


**DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY
GRANTS (GENERAL), 2010-2011**

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General) for the year 2010-2011.

Shri Prasanta Kumar Majumdar has tabled two cut motions to the Supplementary Demands for Grants in respect of Budget (General). If the hon. Member wants to move his cut motions, he may send a slip at the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions he would like to move.

Shri Yashwant Sinha may speak now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending  31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 9, 11 to 20, 22, 27, 29 to 33, 35, 41, 46, 49, 51 to 54, 56 to 60, 62, 72 to 74, 81, 84, 87, 88, 90, 92 to 96, 100, 101 and 103 to 105. ”

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग): उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। इस सदन की एक परम्परा रही है कि सरकार का जो वित्तीय कार्य होता है, उसे हम पास कर ही देते हैं। उसे रोका नहीं जाता है, क्योंकि अगर उसे रोका जायेगा, तो सरकार ठप्प हो जायेगी, देश की गति रुक जायेगी। इसलिए यह जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने रखी हैं, वह भी पास हो ही जायेगी। सरकार का काम-काज चलता ही रहेगा और 54,588 करोड़ रुपये उसे अतिरिक्त प्राप्त हो जायेंगे। जिसे सप्लीमेंट्री डिमांड्स का नेट कैश आउटगो कहते हैं, यह वह राशि है यानी जो बजट वित्त मंत्री जी ने इस साल 26 फरवरी को पेश किया, उसके पांच महीने के बाद वे फिर इस सदन के सामने आये हैं कि उनको 54,588 करोड़ रुपया कैश में और चाहिए। यह टेक्नीकल सप्लीमेंट्री नहीं है, अलग से है। विभिन्न मदों में जिसका जिक्र उन्होंने इस पुस्तिका में दिया है। वह इस मांग को सदन के सामने रख रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि सदन वित्तीय काम को पास कर देता है क्योंकि आपको याद होगा कि सन् 1999 में इस सदन के सामने एक ऐसा अवसर आया था कि बजट पास होने से पहले ही सरकार एक वोट से हार गयी थी, अपदस्थ हो गयी थी। लेकिन फिर सबकी सहमति से यह तय हुआ कि पूरे बजट को बिना किसी चर्चा के पास कर दिया जायेगा और वर्ष 1999-2000 का पूरा बजट इस तरह पास हुआ था।

जहां तक सप्लीमेंट्री डिमांड्स का सवाल है, इसमें दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक यह है कि साइज ऑफ डिमांड कितना है? मुझे याद है कि वर्ष 2008-09 में तत्कालीन वित्त मंत्री ने लगभग 7 लाख 50 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया था और उसके बाद फर्स्ट, सैकिंड और थर्ड सप्लीमेंट्री सदन के सामने आयी थीं, जिसमें उन्होंने 1 लाख, 53 हजार करोड़ रुपया और एडिशनल लिया। उस समय मुझे याद है कि मैंने कहा था कि *this is actually a fraud on Budget making*, क्योंकि बहुत सारी मांगें ऐसी थीं, खर्चे ऐसे थे जिनको बजट बनाते समय ही हम शामिल कर सकते थे। लेकिन हम सब जानते हैं कि वित्त मंत्री क्यों उन खर्चों को नहीं शामिल करते हैं। वे इसलिए उसे शामिल नहीं करते हैं कि जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसे वह कम करके दिखा सकें। अब 54, 588 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग सदन के सामने आयी है, यह लगभग वन परसेंट ऑफ जीडीपी है।

मैं मानता हूं कि यह एक बड़ी मांग है। यह पांच हजार करोड़ या दस हजार करोड़ रुपये की बात होती, तो कहते कि सामान्य बात है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो फरवरी में ध्यान में नहीं होती हैं, लेकिन 54,000 करोड़ रुपये एक बड़ी राशि होती है और इतनी बड़ी राशि की आवश्यकता क्यों पड़ी, मुझे लगता है कि इसका स्पष्टीकरण वित्त मंत्री जी को सदन के सामने देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि बजट बनाते समय क्या यह डिमांड सामने नहीं थी? अगर थी, तो उसको बजट में क्यों नहीं शामिल किया गया? मैं



कुछ आइटम्स की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं जैसे Grant No. 35 – Transfers to State and Union Territory Governments for (a) Special Plan Assistance to Jammu and Kashmir, (b) Special Central Assistance to Special Category States including Jammu and Kashmir, (c) Additional Central Assistance (ACA) for establishment of Zero Liquid Discharge System in Tirupur, Tamil Nadu for effluent treatment to sustain textile industries, and (d) ACA for Externally Aided Project. The total amount is Rs. 6,379 crore. मेरा मानना है कि यह सारा कुछ जो इसमें लिखा गया है, बजट बनाते समय एंटीसिपेट किया जा सकता था और ऐसा नहीं करना बजट मेकिंग की प्रॉसेस का अपमान है। Likewise, Ministry of Petroleum and Natural Gas Grant No. 72 – for providing compensation to Oil Marketing Companies towards estimated under-recoveries on account of sale of petroleum products. This could have been easily anticipated. कोई कारण नहीं है कि यह मांग सप्लीमेंटरी डिमाण्ड में आए। Likewise, Grant No. 81 – meeting additional requirement of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) (Rs. 6,300 crore), meeting additional requirement of Rs. 337.50 crore of Indira Awaas Yojana under Rural Housing towards construction of additional one lakh houses in the State of Jharkhand. इसे क्यों नहीं एंटीसिपेट किया जा सकता था बजट बनाते समय? मैं यह प्वाइंट आपके सामने रखना चाहता हूं कि थोड़ी-बहुत स्वतंत्रता, छूट वित्त मंत्री को रहती है बजट बनाते समय, लेकिन अगर फर्स्ट सप्लीमेंटरी में ही 54,000 करोड़ रुपये की मांग के साथ वित्त मंत्री आते हैं, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि यह सर्वथा अनुचित है और यह राशि उनको बजट में ही इनक्लूड करनी चाहिए थी।

इस समय जो आर्थिक प्रबंधन है पूरे देश का, उसका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, जिस पर पिछले दो दिनों में चर्चा हुई थी। मैं उस चर्चा को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन कल जब वित्त मंत्री जी उत्तर दे रहे थे, तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब थियोरी इस सदन के सामने रखी। उन्होंने कहा कि चूंकि ग्रांथ रेट बढ़ रही है, इसलिए महंगाई बढ़ेगी और महंगाई को रोकने के लिए उपाय बताने की बजाए उन्होंने महंगाई का औचित्य इस सदन के सामने रखा।



वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं, होते, तो मैं उनसे पूछता कि क्या वह अर्थशास्त्री हैं? Is he a trained economist? और मैं स्वीकार करता हूं कि मैं ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, कुछ अनुभव है वित्तीय मामलों का, लेकिन मैं ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हूं। जहां तक मुझे ज्ञात है कि प्रणव बाबू भी ट्रेंड इकोनॉमिस्ट नहीं हैं। इसलिए उन्हें किसी ने बताया होगा कि यह इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि अगर ग्रोथ होगी तो महंगाई बढ़ेगी।

मैंने पिछले नौ वर्षों के आंकड़े इकट्ठे किए हैं। ये 21वीं सदी के पहले दशक के आंकड़े हैं। ये आंकड़े हैं कि इस अवधि में जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही और महंगाई की दर क्या रही। मैं उन आंकड़ों को सदन के सामने आपके माध्यम से रखना चाहता हूं और खुद सदन और आप इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि बढ़ती महंगाई का ग्रोथ रेट से कोई ताल्लुक है या नहीं है।

मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं कि सन् 2001-2002 में ग्रोथ रेट 5.8 प्रतिशत रही। आज की सरकार के मुताबिक उसे लो ग्रोथ रेट माना जाएगा। बल्कि वित्त मंत्री जी ने एडीए सरकार पर आरोप लगाया कि आपके समय में महंगाई इसलिए कम थी क्योंकि ग्रोथ रेट नहीं थी। उस साल ग्रोथ रेट 5.8 प्रतिशत रही और होलसेल प्राइस इंडेक्स मात्र 1.6 प्रतिशत रहा। छः प्रतिशत की ग्रोथ रेट कोई बहुत कमजोर नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी होलसेल प्राइस इंडेक्स 1.6 प्रतिशत रहा। सन् 2002-2003 में ग्रोथ रेट मात्र चार प्रतिशत रही जीडीपी की, वह इसलिए कि आप जानते हैं, आपको याद होगा कि देश में उस समय सबसे भीषण सुखाड़ आया था। उस समय 40 मिलियन अनाज कम पैदा हुआ था। कृषि का उत्पादन 18 प्रतिशत से घट गया था। इसलिए उस साल ग्रोथ रेट चार प्रतिशत और महंगाई की दर 6.5 प्रतिशत रही यानि ग्रोथ रेट घटी और महंगाई की दर बढ़ी। उसके बाद सन् 2003-2004 में देखें, जो हम लोगों के शासन का अंतिम वर्ष था, उस साल ग्रोथ रेट 8.5 प्रतिशत रही और महंगाई की दर 4.6 प्रतिशत रही। ग्रोथ रेट बढ़ा और 8.5 प्रतिशत तक आ गया और महंगाई की दर घटकर 4.6 प्रतिशत तक हो गई। इनके यूपीए वन के कार्यकाल में सन् 2004-2005 में जीडीपी 7.5 प्रतिशत थी और महंगाई की दर 6.5 प्रतिशत थी यानि पिछले साल की तुलना में ग्रोथ रेट घटी और महंगाई की दर बढ़ी। उसके बाद सन् 2005-2006 में ग्रोथ रेट 9.5 प्रतिशत तक चली गई और होलसेल प्राइस इंडेक्स 4.4 प्रतिशत तक घटकर आ गया। कहीं पर भी दूर-दूर तक ग्रोथ रेट और महंगाई की दर का रिश्ता नजर नहीं आता है। सन् 2006-2007 में ग्रोथ रेट 9.7 प्रतिशत और महंगाई की दर 5.4 प्रतिशत हो गई। सन् 2007-2008 में ग्रोथ रेट नौ प्रतिशत और महंगाई की दर 4.7 प्रतिशत हो गई। सन् 2008-2009 में ग्रोथ रेट 6.7 प्रतिशत और महंगाई

की दर यानि मुद्रास्फीति की दर 8.4 प्रतिशत हो गई। सन् 2009-2010 में ग्रोथ रेट 7.2 प्रतिशत और होलसेल प्राइस इंडेक्स घटकर 1.6 प्रतिशत आ गया।

दस साल के आंकड़े किसी भी अर्थशास्त्री के लिए इस बात को साबित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, मैं वित्त मंत्री जी की अनुपस्थिति में बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन राज्य मंत्री यहां हैं और वे मेरी बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे, इन आंकड़ों को देखने के बाद कोई भी व्यक्ति चाहे वह अर्थशास्त्री हो या गैर-अर्थशास्त्री हो, वह एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेगा और वह यह है कि ग्रोथ रेट का मुद्रास्फीति की दर से कोई लेना-देना नहीं है। अगर ऐसा है, तो वित्त मंत्री जी ने जो सिद्धांत कल सदन के सामने निरूपित किया, वह हमें स्वीकार नहीं है। उसके साथ-ही-साथ यह भी कहना पड़ेगा कि जो महंगाई है, उसके दूसरे कारण है। इसी कारण मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि वित्त मंत्री जी ने हमें उपाय नहीं बताए हैं। उन्होंने सदन को विश्वास में ले कर नहीं बताया कि वे महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए कौन-कौन से कदम उठा चुके हैं और कौन-से कदम उठाने वाले हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पूरे मामले की समझ ही गलत है। अगर डाक्टर डायग्नोसिस ही गलत करेगा, तो वह बीमारी का सही इलाज नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि आज जो प्रबंधन सरकार के पास है, उसकी डाक्टरी की पढ़ाई में त्रुटि जरूर है, इसलिए आज हमें इस दृश्य को देखना पड़ता है।...(व्यवधान)

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): इलाज आप ही बता दीजिए।


श्री यशवंत सिन्हा : इलाज बताने की जरूरत नहीं है, आप ही का जो आर्थिक सर्वे है, उसे पढ़ लीजिएगा। इसी में इलाज है।...(व्यवधान) सेंट्रल हाल में चाय पिला कर अलग से आपकी क्लास ले लेंगे।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बातचीत मत कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हर इकनोमिक सर्वे में एक आंकड़ा होता है कि मनी सप्लाई का ग्रोथ, एम-थ्री एक साल में कितना बढ़ा है। अगर मनी सप्लाई का ग्रोथ अर्थव्यवस्था में बढ़ता है, तो उसका मुद्रास्फीति पर सीधा असर पड़ता है। तब इसका उपाय किया जाता है, तो रिजर्व बैंक आफ इंडिया इंटररेस्ट रेट को बढ़ाता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ताकि हम मनी सप्लाई को कम कर सकें। आप पिछले नौ वर्षों के आंकड़े देखिए। एम-थ्री का ग्रोथ वर्ष 2001 से शुरू करता हूं 14.1%, 14.7%, 16.4%, 12%, वर्ष 2005-06 में 16.9%, वर्ष 2006-07 में 21.7%, वर्ष 2007-08 में 21.4%, उसके बाद 2008-09 में 18.6% और वर्ष 2009-10 में 16.5% है। यह परसेंटेज ग्रोथ मनी सप्लाई का है। हमारे जैसा कोई भी अनट्रेंड व्यक्ति भी अगर मौका मिलता है और मैं वित्त मंत्री बन जाता हूं, यह देखूंगा कि मनी सप्लाई एम-

श्री किस परपोरशन में बढ़ रहा है और उसकी चिंता करता हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था में अगर मनी सप्लाई ज्यादा होगी, तो मुद्रास्फीति के ऊपर उसका असर पड़ेगा। इसमें एक और सिद्धांत है, जिसे लिक्विडिटी ओवर हैंग कहते हैं, इसका असर एक-डेढ़ साल के बाद अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। इसलिए वर्ष 2006-07 में, वर्ष 2007-08 में अगर मनी सप्लाई का ग्रोथ 21 परसेंट से ऊपर रहा, तो उसका असर वर्ष 2008 में देखने को मिलेगा, वर्ष 2009 को देखने में मिलेगा। इस बार हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति में जो ऊफ़ान आया है, उसका कारण पिछले सालों का लिक्विडिटी ओवर हैंग है।

मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री इस बारे में सदन को बताएं कि लिक्विडिटी ओवर हैंग का कितना असर पड़ा? अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कान्ट्राडिक्ट करें। इसमें एक बहुत अजीबोगरीब घटना घटी कि वर्ष 2008 में विश्वव्यापी संकट का निर्माण अमेरिका में हुआ, जिसे ग्लोबल मैल्ट डाउन कहते हैं, वर्ष 2008 के मध्य के बाद शुरू हुआ। इसी प्रकार के कार्यक्रम में मुझे अमेरिका का निमंत्रण मिला। यह सितंबर, 2008 की बात है, वहां इस बात पर विचार करने के लिए वाशिंगटन में  करने के लिए कई विशेषज्ञ जुटे कि यह किस प्रकार का संकट है, इसके बारे में क्या करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने अमेरिकन्स इसमें हिस्सा ले रहे थे, उन्हें भी इस बात का कम ज्ञान था कि कितना बड़ा संकट उनके दरवाजे पर आहत दे रहा है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा -This is our problem, we will fix it. उन्होंने कैसे फिक्स किया, यह सारी दुनिया जानती है। यह एक और बहस है, मैं आज के दिन इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप भारत सरकार के सारे दस्तावेज उठाकर देख लीजिए, दस्तावेज का मतलब उस साल का इकनॉमिक सर्वे, वित्त मंत्री का बजट भाषण है। आप वर्ष 2008 का बजट भाषण को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसकी भनक भी भारत सरकार को नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा विश्व अर्थव्यवस्था के साथ होने वाला है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ है यह किसी को आइडिया नहीं था। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि संकट वर्ष 2008 में आ गया। अमेरिका में एक के बाद एक विशाल वित्तीय संस्थाएं धराशायी होने लगीं। वॉल स्ट्रीट में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं हुआ था। लोग 1932 और 1933 के साथ ग्रेट डिप्रेशन के साथ इसकी तुलना करने लगे। बिलियन ऑफ डालर्स का बेल आउट पैकेज बना। यह मौका भारत सरकार के लिए बड़ा माफिक साबित हुआ। **Because the Government of India could take shelter behind the global crisis for all the liberties they wanted to take with the Budget.** मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने इस साल का आर्थिक सर्वे देखा जिसमें उनका कहना है कि वर्ष 2007-08 में 2.6 परसेंट, 2008-09 में 5.9 परसेंट और 2009-10 में 6.5 परसेंट फिसकल डेफिसिट था। आर्थिक सर्वे एक्सपलेन करता है कि 2.6 परसेंट से दोनों

वर्षों में जो ज्यादा फिसकल डेफिसिट हुआ और उसे स्टिम्युलस पैकेज मानिए। कैसे मान लें? कोई जबरदस्ती है कि इसे स्टिम्युलस पैकेज मान लें? यह 2.6 परसेंट ही रहेगा, बिल्कुल अक्षुण रहेगा। This ratio will not change. यह कहाँ लिखा हुआ है? हर साल फिसकल डेफिसिट वेरी करता है। उन्होंने कह दिया हमारा स्टीमुलस पैकेज 3.33 परसेंट वर्ष 2008-09 में और 3.9 परसेंट वर्ष 2009-10 में था। यह ठीक नहीं है। दरअसल सच्चाई यह है कि ये चुनाव वर्ष थे।

15.00 hrs.

भारत सरकार ने चुनाव वर्ष में बजटरी आकड़ों के साथ लिबर्टी ली, उसी का नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार का जो डेफिसिट था, वह सारी सीमाओं को लांघते हुए जो Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act), इस संसद का एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, जो हम लोगों के समय में पास हुआ था और इन्होंने जिसे इम्प्लीमेंट किया था, उस एफआरबीएम एक्ट की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। They allowed the fiscal deficit to go completely out of hand. और अब कह रहे हैं कि इसे स्वीकार कर लो कि यह हमारा स्टीमुलस पैकेज है। अब मैं आपको बताऊं कि जब इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है तो वह सारा एक्सपेंडीचर मार्केट में जाता है, वह गवर्नमेंट का एक्सपेंडीचर है। Government is the largest spender in this country. कहीं न कहीं उसका असर मुद्रास्फीति और महंगाई के ऊपर पड़ेगा। लेकिन इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सपेंडीचर का नेचर क्या था, यह किस प्रकार का एक्सपेंडीचर था? ब्रडली हम लोग जानते हैं कि एक कंजम्पशन एक्सपेंडीचर होता है और एक इनवैस्टमेंट एक्सपेंडीचर होता है। अगर इनवैस्टमेंट में यह गया होता, कोई भी इनवैस्टमेंट, कोई भी खर्च अगर आप करते हैं और उससे कुछ प्रोडक्शन होता है तो उसका मुद्रास्फीति के ऊपर असर नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पैसा लगा उसके एवज में गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त हुईं। लेकिन अगर आप सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडीचर करेंगे तो उसका मांग के ऊपर जरूर असर पड़ेगा और मांग पर असर पड़ने के बाद प्राइसेज के ऊपर असर पड़ेगा। इनका यह सारा का सारा जो एक्सपेंडीचर था, जिसे यह कह रहे हैं कि यह हमारा स्टीमुलस पैकेज था, That was consumption expenditure; it was not investment expenditure. एक तो यह कारण बना। मैंने कई बार इस सदन में कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र आप ले लीजिए। कौन सी बड़ी योजना यूपीए-1 के समय में शुरू हुई। हम लोग छः साल सरकार में थे। अब वे छः साल रेफरेन्स प्वाइंट बन गये हैं। जब कभी हम कोई बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि तुम्हारे समय में यह हुआ। 63 साल आजादी के हो गये। 63 सालों में मात्र 13 साल दूसरे लोगों ने राज किया है और पचास साल आपने राज किया है। 50 साल का हिसाब-किताब कुछ नहीं। हम लोग छः साल शासन में रहे,

सब हिसाब-किताब उसी का होता है। आप जब थे तो यह हुआ।... (व्यवधान) आज मैं कह रहा हूँ कि आज भी जब उधर से उत्तर आयेगा तो ठीक यही बात आयेगी कि आप जब थे तो ऐसा था, आप जब थे तो वैसा था। फिर हम पचास साल का हिसाब-किताब करें। छः साल का हिसाब-किताब क्यों करें।

श्री संजय निरुपम : यशवंत बाबू, आप भी तो छः साल के किस्से याद दिलाते रहे हैं कि हम जब छः साल सरकार में थे तो हमने यह किया... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : यह कितना गलत है, जो वित्त मंत्री ने कल कहा। मांग बढ़ गई, कहां किसकी मांग बढ़ गई, मैं उस पर आता हूँ। पिछले दो-तीन वर्षों में यह जो पैसा खर्च हुआ, यह पैसा सिर्फ कंजम्पशन एक्सपेंडीचर नहीं था। अधिकांशतः यह पैसा भ्रष्टाचार में गया, यह मेरा कहना है, करप्शन में गया। That was consumption expenditure; it was not investment expenditure.

थम्बीदुरै जी यहां बैठे हुये हैं। 2जी का मामला है जो वे उठाते रहे हैं। He has become the biggest campaigner against 2G and the corruption in 2G. हम भी साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या यह भंयकर करप्शन का मामला नहीं है? क्या हज़ारों-हज़ार करोड़ रुपये का घोटाला 2जी में नहीं हुआ है?

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): It is a fact. ... (Interruption) 

श्री यशवंत सिन्हा : कॉमनवैलथ गेम्स में 35 हजार करोड़ या 87 हजार करोड़ रुपये का बजट है। इसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ है और रोज़ समाचार पत्रों के माध्यम से घोटालों की बात आ रही है... (व्यवधान) मैं सप्लीमेंटरी को ही सप्लीमेंट कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष जी, इस साल नरेगा, जिसे अब महात्मा गांधी नरेगा का नाम दिया गया है, उसका 40 हजार करोड़ रुपये का बजट है। हम यहां लोक सभा के जितने सदस्य बैठे हुये हैं, उनके जिले की एक ही कहानी है... (व्यवधान) NREGA is the factory of corruption right down to the block level. It is the factory of corruption. It is the fountainhead of corruption. ... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): You admit it in Bihar; you admit it in Chhattisgarh; you admit it in Madhya Pradesh. You are admitting that it is the factory of corruption in these States, when you are saying that it is the factory of corruption. ... (Interruptions)

SHRI YASHWANT SINHA : Shri Narayansamy's contribution has been that he has taken this corruption right down to the Panchayat level. पंचायत लैवल तक आप इस करप्शन को ले गये हैं।

SHRI V. NARAYANASAMY: In the BJP ruled States you admit that in the implementation of Employment Guarantee Scheme there is corruption. You say that. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : It is there in every State including the State of the Rural Development Minister. ... (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके सामने जो बिन्दु रख रहा था, वह यह था...(व्यवधान)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, the supervision and implementation of this NREGA is under the control of the State Governments. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA : I will let you know what that supervision is. I will come to it. You will agree with me when I come to it. ... (*Interruptions*) It was not even consumption expenditure. यह कंसपक्युस कंजम्पशन एग्जम्पशन है क्योंकि किसी के हाथ में भ्रष्टाचार से पैसा आता है तो वह कंसपक्युस कंजम्पशन में खर्च होता है। वह इस देश में खर्च होता है या देश के बाहर जाता है, स्विस बैंक एकाऊंट में जाता है, मारिशस जाता है, वहां से अगर आता है तो इस देश में आता है, नहीं तो वहां रहता है। अगर हम जस्टिफिकेशन करें तो जब मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं इस बात को रखता हूं कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी योजना शुरू की थी। वह नेशनल हाईवेज की थी, वह कैसे चल रही है, उस पर मैं आज कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन वह बिलकुल नहीं चल रही है, बैठ गई है...(व्यवधान) क्या बेहतर चल रही है, इस सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं। वह बिलकुल ही बैठ गई है। इनफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्री यशवंत सिन्हा : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इसी तरह देश को जोड़ने वाली योजनाओं के बारे में सोचते हुये रिवर लिंकिंग की बात की थी। मैंने इस सदन में खड़े होकर कहा था कि अगर सरकार एक योजना ले ले, वह नदियों को जोड़ने की योजना है। इस मुल्क में इतना बड़ा इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और इतनी डिमांड जेनरेट हो जोकि इनवैस्टमेंट डिमांड होगी, कंजम्पशन डिमांड या कंसपक्युस कंजम्पशन डिमांड नहीं होगी।

जिससे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, लेकिन छह साल में इस सरकार ने रिवर लिकिंग को न केवल भुला दिया है, बल्कि ये उसका कभी जिक्र भी नहीं करते हैं। ये क्यों जिक्र नहीं करते हैं? अभी क्या स्थिति है? आज के दिन स्थिति यह है कि पंजाब, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बाढ़ आयी हुई है और बिहार और झारखंड सुखाड़ की चपेट में हैं। कहीं सुखाड़ और कहीं बाढ़ है और इससे देश को निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने रिवर लिकिंग की बात सोची थी कि एक ऐसी योजना बनाओ, जिसमें सरप्लस पानी सुखाड़ वाले क्षेत्रों में जाये और वहां की कमी को दूर करे। उसे इन लोगों ने छोड़ दिया है। आज के दिन यह स्थिति है। वित्त मंत्री जी इस बात के पीछे छिपकर शरण नहीं ले सकते कि उनके समय ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया है और इसीलिए महंगाई बढ़ गयी। I completely discredit that statement on the basis of what I have stated in this House. Nobody is going by that statement. मैं महंगाई के बारे में एक बात और कहना चाहता हूं। मैं होल सेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं कि अगर आप देखेंगे पिछले दो-तीन वर्षों में जो महंगाई रही है, वह फूड इन्फ्लेशन, खाद्यान्न की कीमतों में बढ़त के चलते रही है। यह रहा कम्पोनेंट और इसमें यह सरकार विफल रही है। यह इन्हीं का इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि यह सप्लाय साइड प्रॉब्लम है। मेरे जैसा व्यक्ति बार-बार जोर देकर इस सदन में कहता रहा, बाहर भी कहता रहा कि इस प्रकार की महंगाई से आप मॉनेटरी मेजर्स से नहीं निपट सकते। पिछली बार भी बजट के ऊपर बोलते हुए मैंने वित्त मंत्री जी को सावधान किया था कि आप मॉनेटरी इकोनोमिस्ट्स के चक्कर में मत पड़िये क्योंकि इसका एडवर्स इम्पैक्ट ग्रोथ पर होगा। यह इस तरह होगा कि जब होल सेल प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो इन्हें इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। वह आज बढ़ा है। जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो सारे बैंकों ने डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया। जब वे डिपॉजिट रेट बढ़ायेंगे तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Money will become more expensive. The cost of money will go up. हम इन्फ्रास्ट्रक्चर में रात भर मे सुधार नहीं कर सकते हैं। सड़कें जो हैं, वे हैं, रेलवे जो है, वह है, पोर्ट्स जो हैं वे हैं, लेकिन अगर एक जगह कोई भी सरकार जोरदार काम कर सकती है, हाई कोस्ट इकोनॉमी के कोस्ट को कम करने के लिए तो वह इंटरेस्ट रेट का क्षेत्र है। यह विशियस सर्किल है, vicious circle of high inflation, high interest rates and high cost of economy. उस विशियस सर्किल को हम लोगों ने तोड़ा था। आप अपने आंकड़े देख लीजिये, 14.5 परसेंट जो इंटरेस्ट रेट था, उससे घटकर इंटरेस्ट रेट साढ़े पांच, छह परसेंट पर आ गया था। यह हर क्षेत्र के लिए था, कृषि के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सर्विसेज के लिए। अगर इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबली काम्पटीटिव बनी तो उसके पीछे एक बड़ा कारण था, that we were able to reduce the cost of money. अब हम दुबारा उसी विशियस सर्किल की तरफ जा

रहे हैं। मैं आज के दिन फिर वित्त मंत्री जी को आगाह, सावधान करना चाहता हूँ कि we get into this trap of high inflation, high interest rates and high cost of economy, then it does not augur well for the future of our economy, for the growth rate. इस विषय पर बोलते हुए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन, होल सेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट में है, 10.55 परसेंट, 11 परसेंट है।

If your food inflation is also in double digit इसका असर इस देश के गरीब के ऊपर पड़ता है। How many people are being pushed below the poverty line as a result of this price rise? आप कह रहे हैं कि ग्रोथ करेंगे तो रोजगार बढ़ेगा। मैंने इसी सदन में कहा था कि जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ तो मेरे सामने एक बूढ़ी औरत आती है, जो मुझ से कहती है कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, खाने का कुछ इंतजाम करो। मैं उसे यहाँ कह सकता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने सदन में कहा था कि ग्रोथ रेट 9 प्रतिशत और 10 प्रतिशत हो गया है, इसलिए वह ग्रोथ रेट खा लो। गरीब ग्रोथ रेट नहीं खाएगा। गरीब तो दाल-रोटी, रोटी-सब्जी खाएगा। इसीलिए मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूँ कि यदि ग्रोथ रेट का आवश्यक परिणाम ऊँची मुद्रास्फीति है तो हमें ऐसा ग्रोथ रेट नहीं चाहिए। हम इस ग्रोथ रेट को नकारते हैं। We reject such a growth rate. दुनिया में अनेक उदाहरण हैं। चीन, जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है how they have combined a high growth rate with low inflation. वित्त मंत्री जी यह आवश्यक नहीं है कि यदि हम 9 प्रतिशत की दर से ग्रोथ करते हैं तो हमें 12 प्रतिशत की दर से मुद्रास्फीति वहन करनी होगी। ऐसा जरूरी नहीं है। It reflects poorly on the economic management of this Government. यदि आप सही हैं। you will be able to establish that balance. आपने वह बैलेंस नहीं बनाया है। वह संतुलन कहीं न कहीं खो गया है, जिसके कारण आज यह स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी के आने से हमें बहुत रिलीफ मिलेगा। यह जीएसटी लाएं। आपने हमारे घोषणा पत्र में पढ़ा। We stand committed to what we have said in our manifesto. We are for GST. But I would like to tell the Finance Minister, through you, that he will have to carry the States with him. जब मैं वित्त मंत्री था तो मैंने वेट लागू करने के लिए Empowered Group of Finance Ministers बनाया था। वह इसलिए बनाया गया था क्योंकि इसके बिना वेट लागू नहीं हो सकता था, without taking the States on board through this Empowered Committee device. I not only created an example

of cooperation between the Centre and States, but also I gave the States the responsibility to work it out.

महोदय, सदन में चर्चा हो रही थी, जिसमें निशिकांत दूबे जी बोल रहे थे कि वित्त मंत्री ने सूपर रैगुलेटर बना लिया और स्वयं को उसका अध्यक्ष बना लिया। उसी प्रकार से जीएसटी के बारे में खबर आ रही है कि आप जो संविधान संशोधन लाने जा रहे हैं, उसमें आप वीटो पावर अपनी रखना चाहते हैं, जो कि राज्यों को पसंद नहीं हैं। इम्पवार्ड कमेटी ने कहा है we cannot give this veto power because this is affecting our rights and responsibilities. इसलिए जीएसटी हो, जरूर हो, 1 अप्रैल, 2011 से लागू हो। But please ensure that you carry the States with you because you can have any veto power with regard to your GST rate but the States cannot give you the veto power as far as their rates are concerned because they also have their economy to manage.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंत में एक-दो बातें अपने राज्य के बारे में कहना चाहता हूं। झारखण्ड में भयंकर सूखा पड़ा है। बिहार में भी पड़ा है। पिछले साल भी सूखा था। इससे किसानों की कमर टूट गई है, वे खड़े नहीं हो सकते हैं। पिछले साल उनके खेत परती रह गए थे। झारखण्ड में एक ही फसल होती है, जो कि मारी गई थी और इस साल फिर से मारी गई है। पैडी का सीडलिंग सूख गया, वह लगा नहीं और ट्रांसप्लान्टेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। झारखण्ड में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जिस पर हमारे मित्र विस्तार से बोलेंगे।

मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल जो फसल बीमा योजना की योजना चालू हुई है, उसके अनुसार किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं दी गई, बिहार में भी नहीं दी गई। हर जगह के बारे में, हर जिले से यही खबर आई है। सिर्फ नाममात्र को फसल बीमा का ड्रामा दिखाने से कोई फायदा नहीं। झारखंड में राष्ट्रपति शासन है, वहां की सरकार ने 12 जिलों को सुखाड़ ग्रस्त घोषित किया है। मेरा जिला हजारीबाग है, बगल का जिला चतरा, धनबाद, रामगढ़ और गिरिडीह सुखाड़ ग्रस्त है, लेकिन हजारीबाग सुखाड़ ग्रस्त नहीं है। इन्होंने हजारीबाग में कहां वर्षा देख ली, राष्ट्रपति शासन में जो पिक एंड चूज की पॉलिसी चल रही है, यह नहीं चलनी चाहिए। मैं इस सदन में जोरदार ढंग से मांग करता हूं कि पूरे झारखंड राज्य को सुखाड़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें, चुन कर नहीं, कि एक-दो को छोड़ दिया और बाकी को किया। हमारा जिला नक्सल प्रभावित है, मेरा अपना जिला हजारीबाग देश के उन 32 या 34 जिलों में है, जो सबसे बुरी तरह नक्सल प्रभावित हैं। उनके लिए विशेष योजनाएं बन रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कहा है कि वे नक्सल प्रभावित जिलों में काम करने के लिए दो हजार करोड़ रुपए देने जा रहे हैं। यहां पर सभी संसद सदस्य बैठे हैं, हमारे एक मित्र वहां से कह रहे थे कि उस निगरानी समिति के आप ही अध्यक्ष हो, जो निगरानी समिति जिले के स्तर पर काम करती है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के प्रोग्राम्स को देखती है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, सब एमपीज़ हैं। इसी सदन में मैंने ऊर्जा मंत्री जी से मांग की थी कि जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना चल रही है और नहीं भी चल रही है, उसे भी देखने की जिम्मेदारी दें। मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि 700-800 करोड़ रुपए नक्सल प्रभावित जिलों में जा रहा है। Rs. 700 or 800 crore is not a small sum of money. I had been a District Collector myself. मैं आपको कहता हूँ कि उस ज़माने में हमारे पास सरकारी गाड़ी भी नहीं होती थी। किसी बीडीओ का जीप बोरो करके हम लोग उस इलाके में जाते थे, जहां हमारी अपनी कार नहीं जा सकती थी। आज जिलों के पास भरमार राशि है। They are flush with funds. लेकिन उसमें आपकी और हमारी भूमिका क्या है कुछ नहीं है। I am telling you that I had been a District Collector myself. I left the Service when I was a Joint Secretary in the Government. I have spent 24 years in the IAS. I had been the Finance Minister of this country. I had been the External Affairs Minister of this country. I am the Lok Sabha MP today from my district. मैं एक कुंआ नहीं खुदवा सकता। अगर मैं कहूँ कि सुखाड़ से निपटने के लिए कुंआ खोद दें तो मुझे किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा, हुजूर, मालिक, कुंआ खोद दें, दो कुंआ, पांच कुंआ दे दें। इसी के लिए हम लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ, मैं सारे लोगों की, खास कर अपने झारखंड की बात कर रहा हूँ, जहां पर मेरे ख्याल से पंचायती राज का चुनाव 40 वर्षों से नहीं हुआ है। कल कोई नौजवान ऑफिसर आ गया तो हम उसके सामने हाथ जोड़ कर खड़े रहें और कहें कि सर, किसी तरह हमारी बात मान लीजिए। मैं आप सब लोगों की तरफ से मांग करना चाहता हूँ कि जिलों में जितनी विकास की योजनाएं चल रही हैं, ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: लाल सिंह जी जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

* Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। आपका भाषण रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान)

DR. M. THAMBIDURAI : The MPs and MLAs are given funds for development. ... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: You are absolutely right. उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हमारे राज्य में एक-एक एम.एल.ए. को तीन-तीन करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड के रूप में उपलब्ध हैं। एक-एक संसदीय क्षेत्र में छः से लेकर आठ विधान सभा क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार देखें, तो वे 15 और 20 करोड़ रुपए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर खर्च करेंगे और हम केवल दो करोड़ रुपए खर्च करेंगे। यह कुछ नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से, जो खुद लोक सभा के सदस्य हैं, उनसे आप सब लोगों की तरफ से, पूरे सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से मांग करता हूं कि जिलों में जितनी भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, उनकी निगरानी की जिम्मेदारी लोक सभा के एम.पी. को दीजिए और तभी सच मायने में विकास होगा, क्योंकि तब जनता विकास के साथ जुड़ेगी और It will not merely be a few officers who will divide the money amongst themselves and say money has been spent.

आप यहां फायनेंस मिनिस्टर के रूप में बैठे-बैठे कहेंगे कि एक्सपेंडीचर हो गया और जमीन पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एम.पी. को उसके क्षेत्र में चल रही सभी योजनाओं की प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपी जाए। दोनों में सांसदों की भूमिका होनी चाहिए और तभी इंसोफ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री जी जब इस बहस का उत्तर देंगे, तो अपने जवाब में इस विषय पर सदन की भावना को ध्यान में रखते हुए निश्चित रूप से कुछ कहेंगे।

CUT MOTIONS

SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT): I beg to move:

TOKEN

DR. K.S. RAO (ELURU): Mr. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I seek your permission to speak from here.

Thank you very much for giving me an opportunity. I heard the excellent speech out of the experience of the hon. former Finance Minister Shri Yashwant Sinha and also the criticism that he has made on the Budget proposals that are made as well as the Supplementary Budget that has now been brought before the House.

I just wanted to say one thing. While I agree that the role of the Opposition is to criticize the ruling Party wherever it went wrong, I always feel that constructive criticism was not coming from the Opposition except on political grounds. I will just narrate some of the events that have occurred. I have been in the Parliament for the last five Lok Sabhas. This is my fifth term. I never heard NDA speaking about the poor man. If they were to speak, I have not seen any proposal for the improvement of the living standards of the common man except in the last six years because you are sitting in the Opposition. When they were in power, they spoke all the time about the industry, trade, exports, communalism, Ayodhya temple, Babri Masjid and other related things.

But I am happy today that not only the NDA but all the parties in the country are speaking about the common man day in and day out. I will go through once again what happened yesterday when the issue of price rise was raised in this House and the biggest conflict was under what rule it has to be initiated.

If it were to be with a view to discuss the failure of the Government in controlling the prices, an effective criticism could have been made there, but asking for a discussion under Rule 184 was purely political, possibly to take advantage of the present situation or with the hope that some of the allies of the present Government may help them or some of the parties, which are supporting this Government from outside, may help them. Only with this view, the working of the House was disturbed for one week and

not with the view to have a useful discussion in this House, which has caused an expenditure and loss to the Government and the people.

Now I come to the speech given by hon. Yashwant Sinha today. I agree that he is a very senior member and former Finance Minister. I also heard the analysis given by him. Hon. former Finance Minister said that expenditure should be made more on investment than on consumption. I totally agree because any expenditure on investment will definitely lead to production and bring down the prices and will definitely control the price inflation. But expenditure should be made on what kind of investment? Possibly they are talking of investment on industry, investment on trade, investment on exports. It is right that if the investment were to be made on trade, import, export or industry, the products that are produced by them are not for the common man.

The difference is that the investment, that is being made now, is the investment on rural areas and agriculture. So, there is a lot of difference between using the same slogan – expenditure should be more on investment rather than on consumption – by the two sides. It is true not for investment on industry; it must be investment for the rural areas.

I will give some statistics of how Budget allocations were made by Shri Yashwant Sinha in the year 2003-04. I do not want to go into the details of period prior to that. In 2003-04, the budget allocation made for education was Rs. 4,956 crore and in the Budget presented for the year 2010-11, it is Rs. 70,555 crore. Please compare the allocation of Rs. 4,956 crore and Rs. 70,555 crore. The investment in rural development in 2003-04 was Rs. 17,845 crore and in the last Budget, it is Rs. 1,45,225 crore. The investment on fertilisers, which are being used by the farmers living in the villages, was Rs. 14,450 crore in 2003-04 and it is Rs. 53,075 crore in

the last budget. About 72 per cent of the people are living in rural areas today.

A lot of discussion went on investment in agriculture and a lot of criticism was also made by the Opposition. Investment in agriculture in 2003-04 was Rs. 3,943 crore and it is Rs. 24,521 crore in the last Budget. Apart from this, Rs. 68,425 crore has been spent on food and Public Distribution System. Investment in healthcare in 2003-04 was of Rs. 9,146 crore and it is Rs. 25,336 crore in the last Budget. I can give you many other details. The investment on labour and employment in 2003-04 was Rs. 971 crore and it is Rs. 4,114 crore in the last Budget. Today the investment on social justice and women empowerment is 4,574 crore, on tribals affairs is Rs. 3,220 crore and on women and children development is Rs. 11,070 crore. Investment on youth affairs was Rs.495 crore in 2003-04 and it is 3,781 crore today.

Sir, do you find fault with these investments today? Are you referring to the investments made on these things?

Are you referring to the investment made on industry, trade or exports? Please check up on what your criticism is!

You are also finding fault in regard to Shri Pranab Mukherjee's statement yesterday that if the GDP were to go up, naturally, there will be an increase in inflation. You found fault with it and gave the statistics. It is true that when there was no purchasing power with the poor people -- whatever be your growth rate in the industry, trade and exports -- definitely there will not be inflation in the prices of food commodities. You cannot compare the GDP growth rate and the rate of inflation in such a situation.

You deny some of the points, which I say. Every one of us agrees on the point that all that is required today by the common man is food, shelter, education, health and employment. I had just now read that the investment made on food,

shelter, education, health and employment made in the 2010-2011 Budget has no relevance compared to the 2003-2004, and so much investment is made on these things, which are required for the common man and the farmer.

I was always of the opinion and I was making noise in the Parliament that unfortunately the sweat of the common man and the sweat of the farmer in this country were not valued in the way the industrial goods are valued. If there were to be a little price rise in the petrol or diesel, the manufacturer of tyre will increase the price of tyre in 15 days or every month. But when it comes to the question of produce by a farmer in a village, the Government should not come forward even for 1/10th of the price rise, which is required. The sole reason being, the Party, which is not in power will make *dharna* and will make criticism left and right on everything both inside the House and outside the House that the Party in Government is a useless Government; is an ineffective Government; they do not know the administration; and they are the people responsible for all this price rise. This is all the comment, and ultimately, they say that they have to get down. But the same Opposition Party -- when it comes back to power again -- does not touch that subject at all. The reason being if the price of the farm products were to be increased, then naturally, the prices of the essential commodities will go up. Thereafter, there will be this furore.

What is the consequence of this? Once again they have to face the same Opposition; the same criticism; and the choice of losing power in the next elections. Therefore, which Party in the Government will have the courage to increase the price of agricultural commodities that will affect the consumption of the common man? But all of us will say in public meetings that farmer is the backbone of this country; the prices have to be increased; and they have to be doubled or tripled, but do not touch them as long as we are in power.

You must accept that the Minimum Support Price (MSP) for farm products -- the statistics are given -- was increased from Rs. 550 to Rs. 1,000 with regard to paddy; from Rs. 630 to Rs. 1,100 with regard to wheat; and several other items

only in the span of five years. Naturally, when the prices have increased so much, it will go up. The prices of essential commodities will go up. But I am of the definite opinion that there is no harm. More particularly, I will give you the statistics when 72 per cent of the people are living in the villages. The moment you increase the prices of the farm product, the wage of the farm labourer increases enormously. He is not being affected; the farm labourer is not being affected; the farmer is not being affected; and the rest of the people below the poverty line are being covered by the TPDS.

As one of my friends suggested, if you say that TPDS must cover all the essential commodities which are required by the common man, I shall support it. Similarly, in urban areas, it does not affect the rich man because the total expenditure on the essential commodities, food grains, will not be even one per cent of the income of the rich man. Then, who are the people who are affected? Possibly, the employees whose income is fixed, they may suffer. Similarly, those people who are not touched by the TPDS may suffer, or those poor people who were not given the quota of their consumption in full may be affected because they will have to do a part of their purchases from the market. They can also criticize and I appreciate that, but not otherwise.

Who are the people left now who are being affected by increase in the prices of essential commodities? Possibly, it is about 20 per cent of the total population in this country. If the TPDS was not effectively implemented in a particular State, I cannot say anything. But in the States where TPDS is effectively being implemented, the number of people affected by the increase is very nominal. However, I am not supporting the increase in the prices of essential commodities. The Government must come forward, and as many of the Members have suggested, and the Essential Commodities Act must be made so stringent that any trader who hoards beyond a limit must immediately be put in jail. There should not be any mercy shown on him. Then, if two people were to be jailed in that manner, how many people will have the courage to do black-marketing or

hoarding of essential commodities? We are not doing it. There also I will agree if you find fault with this Government that the Essential Commodities Act which was diluted by you during your tenure was not amended to make it stringent by this Government in the last few years. I appreciate such type of a criticism. When you yourself have diluted it, how will you be able to criticize the Government in that regard? You do not have any face even in that regard also.

Sir, many of the Members may find fault with me if I say that this price rise is acceptable. I do not say that price rise is acceptable. The Government must take all necessary steps to control the prices of perishables. All of us are aware that vegetables and fruits are one of the major items which affected the prices in the market. There is no facility to store them. This year, if the price of tomatoes were to be Rs. 25 a kilo, all the farmers will go for the production of tomatoes with the hope that they will get some extra money, but suddenly it comes down to twenty-five paise and as a result, they will have to destroy that crop in their own field because they do not have money to transport it to the market. We have to come into the field there. We must force the Government to create enough facilities for the farmer or the poor man to see that it can be stored for enough time or till such time when he gets the right price for his produce.

In the last Budget, I remember the Finance Minister and the Prime Minister have made a commitment that they are going in for cold-storage chains, cold-storage transport, and that they are prepared to lend any amount of money for that purpose. If we were to encourage research and development so that the technology for the storage of these perishables is innovated, then these things can be stored to an extent that the farmer will not be deprived of the right price. Then, all these questions will not arise.

You mentioned about dal. Where is dal in this country? We have been importing pulses, we have been importing edible oils, but to what extent? Sixty lakh tonnes of edible oils are being imported today in this country. That is why I made an uproar recently that the farmers of this country are competent,

progressive, intelligent and also very enthusiastic to produce oilseeds in this country if only a proper price is paid to them. If the Government is prepared to give a subsidy of Rs. 10 or Rs. 15 per kilogram for oil, if one quarter of it is passed to the farmer, he can produce enough oil in this country. If you criticize on that, I am happy. But you never touched on these aspects. You only say in a routine manner about technology, GDP, inflation rate, whether it is inverse or direct, and all those other things.

I will come to kerosene or petrol or cooking gas. It is the statistics and it is not my telling that the price of crude oil in 2001-02 was 22.75 dollars per barrel; in 2002-03, it was 26.59 dollars per barrel; in 2003-04 it was 27.98 dollars per barrel. In these years, they had increased the price of petrol at least nine times. ...

(Interruptions)

श्री यशवंत सिन्हा : जब हम लोगों ने कीमतें बढ़ायीं, तब क्या विजय चौक पर खड़े होकर आपने हमारा माला पहना कर सम्मान किया था? आपने हमें क्रिटिसाइज किया कि दाम बढ़ा रहे हैं, तो अब हम आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। I said that when we increased the prices, you did not honour us with garlands at Vijay Chowk. So how do you expect us to honour you? We will criticise you like you criticised us.

DR. K.S. RAO : I did not ask you to garland us. I wanted you to criticize this Government. I wanted you to criticize in a constructive manner. ... *(Interruptions)*

SHRI YASHWANT SINHA : I will garland Shri Murli Deora privately! ... *(Interruptions)*

DR. K.S. RAO : I am only telling you that the Opposition is failing in criticizing the Government in a constructive manner. I am in favour of your criticizing the Government. But where did you criticize constructively? I heard everything and not at one point was a concrete suggestion made or was there a constructive criticism. The price of crude oil in 2004-05 was 39 and later it was 55, then 62, then 79. In 2008-09 it was 83.57. In all these six years, the Government has got the tenacity or the ability to withstand all these price rise and absorb it themselves

and they did not raise the price at all. It is only recently that the price was increased because there must be a limit to it. It is all right if the oil companies lose it. Hon. Leader of the Opposition was telling yesterday that the oil marketing companies were shown as earning profit of Rs.4000 crore and then how can the Finance Minister say that they are losing? If one has to go through, this profit of Rs.4000 crore has come after the upstream companies of ONGC and other companies like Oil India have subsidized these oil marketing companies. The Government of India is also subsidizing the oil companies to an extent of Rs.1,03,000 crore. After subsidizing Rs.1,03,000 crore, these oil marketing companies have come to a stage of showing Rs.4000 crore profit. That means, there is a loss of Rs.99,000 crore because of under recovery. All of us will say that do not increase the price at all. Then how can we have our money to be secured? Oil is not available in this country. About 77 per cent of the oil is being imported from outside. You and I have no control on the international price of oil. In that case, we have to meet it from the Budget. When we say Budget, whose money is this? It is our money. In one way or the other, it is going to be public money, either directly charged or through the Budget. Its impact will always be there on the market.

My point is that if the petrol prices are to be increased, who is using the petrol? A poor man, living below the poverty line is not using the petrol. How many of us are using petrol? It is only a rich man or above middle class man who is using the petrol. If the petrol prices are to go up, who is going to be affected? It is the rich man or a above middle class man and certainly not the poor man. Now take diesel. Somebody may argue that if the diesel prices are to be increased, the whole country would be upset and the entire market would go up. Who is using diesel? Once again, it is the same thing. An industry might be using, the Railways might be using. But as long as the prices of the railway passenger fares are not increased, if the Government is to check the price of railway passengers particularly the ordinary passengers, then there is no effect of increase in diesel

and oil price. If the industries are to use diesel, naturally the price of the product might go up. But they have to absorb.

What is the percentage component of this increase of oil prices in the total cost of production of the industry? It is negligible. And we make a hue and cry and say, "Do not increase the prices". But then, where do we get the money from?

There must be a reason behind criticism. It has been stated that the price of kerosene should not have been increased. Yes, there is a reason for that demand. Because kerosene is used by the poor man, he should not be burdened. I support that argument. But the practical observation is that much of that kerosene is being used for adulterating petrol. The difference in price between Rs.9 of kerosene and Rs.50 of petrol is leading to adulteration of petrol. It is also a common observation that tankers after tankers of kerosene are being taken away for the purpose of adulteration. If you want to give benefit to the common man, give it directly. There cannot be any cheating or adulteration in that. You charge him full and subsidise it by giving him cash.

Similar is the case of cooking gas. The common housewife should not be affected by rise in the price of cooking gas. I support that viewpoint. But we read in newspapers day in and day out that much of this subsidised cooking gas is used either by restaurants or for industrial purposes. That is because of the difference in price. Here also the benefit can be passed on to the people living below poverty line in different ways in some other way. It is not necessary to do it by enabling others to misuse it.

In spite of all these things, the UPA Government did not raise the price of kerosene for six years. We took six years to increase the price of kerosene from Rs.3 a litre to Rs.9 a litre. It is only this time that we have increased it from Rs.9 a litre to Rs.12 a litre. In what circumstances was that done? Even the Kirit Parikh Committee suggested a minimum increase of Rs.6 per litre on kerosene. The Government could once again reduce it to Rs.3 a litre and then increase it to Rs.9. Should one not go into all these details before one criticises the Government?

If the hundreds of crores of rupees that are to directly go into the hands of rich people were to be stopped, why should we worry? If the common man were to be affected, we should worry. In yesterday's discussion also the subject given was, "The Impact of Price Escalation on Common Man". I specifically say that it has two aspects – one is price inflation and the other is its effects on common man. These are totally two different issues. There is a price escalation. But to what extent it has impacted the common man is questionable. You go into the statistics.

Once again, why have the prices gone up? There are several reasons for it. Earlier, as I said in the beginning, all the 72 per cent of the people or at least 60 per cent of the people living in villages, their property and their wealth is not going up at all. A farmer who had got 20 acres of land fifty years back has got only two acres only now. If they were to purchase a piece of land in a village from somebody's land, it is not a village farmer that is purchasing that land. It is the businessman from outside who is doing it. Or the farmer's son who is doing business or employment outside is doing that, but certainly farmer not out of his farming income.

If this was to be the situation of the farmer, where is the money in the villages? There is no money there. Now what this Government has done is from 2003-04, when you have given Rs.75,000 crore credit to the farmers, today we are giving Rs.3,75,000 crore. That means Rs.3 lakh worth additional credit has gone to the villages. Under the name of rural development we have spent Rs.2 lakh crore every year. We have written off Rs.72000 crore of debt to the farmers. The liquidity in the villages, in the hands of the farmers has gone up.

I am not talking of not only money in their hands, I am talking of myself, a son of a small farmer of four acres in my village. In those days, if we were to cook one egg in the family, all the members of the family used to share. There was not habit of eating fruits because we cannot afford. If you were to consume one apple any day, either it must be when we are ill or when a relative has come. If we were to cook chicken in our house, it is not any day, it must be on a festival or when a

guest comes to my house. Those are the days! Today, even a poor man is in a position to consume all these things. In some places, every day. For example, people working in Singhereni collieries – I say with authority – you come and I can show anybody. Workers who are working in industrial concerns, have got the capacity to eat. Food habits have also changed. It was not those days habits. Today habits are different. So, the consumption of fruits and vegetables has gone up substantially. Consumption for non-vegetarian items like chicken, eggs, and everything else has gone up substantially. Naturally, prices will go up.

Now, I come to the awareness of the poor man. Earlier, I never used to think of traveling in an airline. I thought it was not my privilege. I used to think that I can travel only in a third class compartment of train. But today anybody can think of traveling in air. If a person is not having money, he would catch hold of anyone and buy a ticket to travel in air. That means there is an awareness; there is a thinking. Standard of life has gone up. In these circumstances, if the inflation were to increase, inflation for what? Inflation for essential commodities. Essential commodities produced by whom? By farmers of your own village or your own country. And the money is not going outside. If you do not increase the production of the farmer, and if you were to import the food grains from outside, what would be the situation? One day, let the Agriculture Minister announce in Parliament that this country is short of wheat and we are going to import one million tones of wheat, the next day, in the global market, the price will be doubled.

Similarly, if you were make a statement that next year, we would fall short of paddy or rice, then you would not find paddy or rice anywhere also. No matter, what price you pay. Then, why should we not allow a farmer to produce more by getting adequate credit, by getting remunerative price so that there will not be inflation in essential commodities. That way, by investing in the rural area, by increasing the production in the rural area, we can control the inflation of essential commodities. Only when his purchasing power goes up, then, he can construct a house. When he constructs a house, he needs cement and steel. Then only industry

comes in. Otherwise, there will be a glut in cement; there will be a glut in steel. Why did the price go up in the last four years from Rs.27,000 per tonne to Rs.54,000 per tonne overnight because the utility and the construction activity has gone up so much in this country, the prices have gone up. But, we controlled it. We brought it down to Rs.27,000 or Rs.28,000 per tonne. So, unless the purchasing power of the 72 per cent of the people living in the villages were to go up, no industry can flourish; no GDP can grow, no discussion would be there in Parliament. We will be holding discussion on some other issues. So, my humble request to Yashwant Sinha ji - I am not saying that he made any mistake in criticizing... .. (*Interruptions*) You criticize.

SHRI YASHWANT SINHA : From next time, when I speak, I will praise the Government!

DR. K.S. RAO : In this context, I want to request the hon. Minister of Finance to bring the Essential Commodities (Amendment) Act immediately so that it would become so stringent that no person can even think of indulging in black-marketing or hoarding in this country. Then, there will not be any shortage of food grains in this country; there will not be inflation. Similarly, we know that there are food crops but there is no storage. I am happy that in this revised Budget, whatever provisions have been made are all only for such thing. If you are to make a provision – there was a reference of crop insurance scheme – in the Supplementary Budget, he has provided Rs.2,212 crore for National Agricultural Insurance Scheme.

16.00 hrs.

The Supplementary Budget provisions are made only on this. He made extra provision of Rs.6,000 crore for education; he has made Rs.1,012 crore for national knowledge network. He made provision for PMGSY, of Rs.7,000 crore for building roads in the villages. Is it wrong to provide these things in the revised Budget? Is it wrong estimation in the original Budget?

He said that he should have thought about all this much before; no matter, how much we think, there can always be some adjustment; a Supplementary Budget is not a new thing to the Lok Sabha or to the Government.

So, I find that the allocations made in the Supplementary Budget are most genuine and are required, more to the common man and the man in the villages. In this regard, he provided Rs.800 crore for making godowns in the rural areas, for increasing the storage capacity which is very urgent. As they complain, in some godowns of the FCI, some of the food grains are getting rotted, which is a crime; neither we are giving to the poor man nor we are keeping it intact. So, on a war-footing, either with the private sector or on PPP mode, these godowns must be built not in 10 months or a year; they must be completed in six months.

Similarly, he provided Rs.800 crore for sugar development fund. There was surplus sugar in this country 3-4 years back. The farmers had produced more; they can produce much more, but remunerative prices were not there; so, they diverted the crops. Suddenly, after two years, there is a shortage of sugar. In those days, they asked for increasing the price of sugarcane of Rs.30 per quintal of sugar. The Government would not agree, but now, it is paying Rs.129 per quintal and the farmers must be paid much more so that they are encouraged to produce more so that we do not need to purchase more from outside. We were purchasing these things from outside at double the rate of what we would be paying to the local persons.


To avoid all these things, I wish the Government take necessary steps in this regard. Whatever steps that it has taken are in the right direction, particularly in transferring the wealth from urban to the rural areas, from the trader, businessman, industrialist to the farmers and farm labour. This trend must continue and I am sure, all the Opposition Parties also will support this. If still there is any lacuna, they can criticise.

श्री मंगनी लाल मंडल (झंझारपुर): महोदय, श्री यशवंत सिन्हा जी ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के प्रस्ताव पर बहुत तार्किक बातें कही हैं। सरकार की ओर से विकास दर और महंगाई को एक साथ जोड़ा गया है, जिसके बारे में बहुत ही तथ्यात्मक बातें सदन में रखी हैं। यह बात सही है कि सप्लीमेंटरी बजट संविधानिक प्रावधान है, लेकिन यह बात भी सही है कि जो सरकार अपनी नीतियों और वित्तीय प्रबंधन में तालमेल रखती है, उसके लिए सप्लीमेंटरी बजट बार-बार लाने की आवश्यकता नहीं होती है।

16.04 hrs.


(Dr. Girija Vyas in the Chair)

यह चार महीनों में पहला है और जैसा कि यशवंत बाबू ने पहले बताया है कि 54 हजार करोड़ रुपया नेट कैश आउट गो है। तीन तरह की मांग रखी गई है, जिसका कुल जोड़ 68294.30 करोड़ रुपए का है। जिसमें नेट कैश आउट गो 54588.63 करोड़ है।

तकनीकी पूरक, टेक्नीकल सप्लीमेंटरी 13705.09 करोड़ और सांकेतिक पूरक, टोकन सप्लीमेंटरी 0.58 करोड़ है। सरकार यह सप्लीमेंटरी बजट लेकर आई है इसमें कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं जिनके बारे में यशवंत जी ने चर्चा की है। सरकार नीतिगत निर्णय लेती है। अब 11वीं योजना की मध्यावधि समीक्षा हुई है और सरकार ने टिप्पणी दी कि आधारभूत संरचना, कृषि, बिजली तमाम चीजों पर जोर दिया जाना चाहिए। सरकार विकास दर की बात कहती है जबकि इसमें  की उपलब्धि में भारी असंतुलन है। विनिर्माण और खनन के मामले में पिछले महीनों से प्रगति हो रही है और इसी आधार पर सरकार बार-बार 8.6 और 8.1 प्रतिशत विकास दर अचीव करने की बात कहती है। जहां तक विशेष दर्जे के राज्यों को विशेष सहायता देने की बात है, इस मामले में एक असंतुलन है, सैक्टरल इम्बैलेंसिस, रीजनल इम्बैलेंसिस है और सरकार कहती है कि विकास दर बढ़ रही है, देश में प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है। पिछली एनडीसी की बैठक में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने यह बात नहीं कही, लेकिन सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन मिटना चाहिए और सरकार विकास दर का दावा करती है कि इसे बढ़ाएंगे इसलिए आदमी-आदमी के बीच आमदनी का फर्क मिटना चाहिए।

आइटम में आया है कि विशेष दर्जे वाले राज्यों को अतिरिक्त साधन देंगे, मुख्यमंत्रियों ने यह बात उठाई थी कि पहले 74 परसेंट केंद्रीय राजस्व में राज्यों का हिस्सा था। उसे घटाकर 23 प्रतिशत कर दिया गया। केंद्र का प्रतिशत 66 प्रतिशत था उसे बढ़ाकर 77 प्रतिशत कर दिया गया है। यह कहा गया जब तक यह रहेगा तब तक विकास दर प्राप्त करने में सैक्टरल एप्रोच में भी संतुलन बना रहेगा। इसके साथ राज्यों और क्षेत्रों के बीच संतुलन होना चाहिए लेकिन उसमें असंतुलन बना रहेगा। अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है इसके अनुसार आठ राज्य ऐसे हैं जहां 42 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। सरकार कहती है विकास

दर बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। सरकार कहती है विकास दर बढ़ रही है इसलिए प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है। सरकार कहती है कि विकास दर और प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ रही है इसलिए देश खुशहाल हो रहा है लेकिन देश में महंगाई के चलते गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। आठ राज्यों में 42 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यह क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार को बांटा गया, हमने करीब 1,87,000 करोड़ रुपये की मांग रखी क्योंकि सारे संसाधन झारखंड में चले गए हैं इसलिए बिहार को विशेष पैकेज दीजिए। लेकिन इसे सरकार ने आज तक नहीं माना है। इस सदन में बार-बार सवाल उठा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए क्योंकि इसके अपने कोई रिसोर्सिस नहीं हैं लेकिन केंद्र सरकार अन्य राज्यों की तरह बिहार की भी केंद्रीय हिस्से में हिस्सेदारी घटा रही है। पिछले कई वर्षों से सरकार कह रही है कि कि बिहार का प्रस्ताव विचाराधीन है।

इसमें आपने जम्मू तथा कश्मीर को दिया, ठीक है, जम्मू-कश्मीर को मिलना चाहिए, लेकिन अन्य गरीब राज्यों को भी मिलना चाहिए। हमारा इस पर कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जब सप्लीमेंट्री बजट लाते हैं तो जिन राज्यों को आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया है, उनके बारे में मार्च में जो मूल बजट आया था, उसमें आपने निर्णय क्यों नहीं लिया। इसीलिए यशवंत बाबू ने भी ध्यान आकृष्ट किया था कि जो आपका नीतिगत निर्णय है, आपने विशेष राज्य का दर्जा दिया है तो विशेष राज्य का  मिलने वाले राज्यों को कितनी केन्द्रीय सहायता मिलेगी, यह निर्णय आपको बजट बनाने के समय लेना चाहिए था।

इसी तरह से ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसमें कहा है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए 6,300 करोड़ रुपये की मांग सदन की स्वीकृति के लिए की गई है। मैं बिहार से आता हूँ। बिहार में इस बार जो वित्तीय वर्ष 2009-10 बीता है और वर्तमान वर्ष 2010-11 जा रहा है, जो बिहार का कोटा होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से, अतिरिक्त की बात मैं नहीं करता हूँ, इसमें अतिरिक्त की 6,300 करोड़ रुपये की बात कही गई है। लेकिन प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में बिहार को जो हिस्सा मिलना चाहिए, वह हिस्सा बिहार को नहीं दिया गया और कई राज्यों के लोगों ने कहा कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना एक महत्वकांक्षी योजना है और यह विलेज कनेक्टिविटी के लिए है। लेकिन उसमें राशि का उपबंध नहीं है। राशि देने के लिए आपने बजटरी प्रोविजन नहीं किया और एडीशनल प्रोविजन आपने सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा किया है, मैं समझता हूँ कि सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन है, सरकार की जो आर्थिक नीति है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि के मामले में जो आइटम नं.2 है और जो खाद्यान्न का उत्पादन है, खाद्यान्न के उत्पादन के मामले में वर्ष 2020 तक का आपने टारगेट रखा है। आपने टारगेट रखा है कि 2020 तक हम 20 करोड़ मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे। इसमें कृषि तथा सहकारिता

विभाग तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग है और दूसरी जगह भी कृषि मंत्रालय में आइटम नं.74 पर कृषि एवं सहकारिता विभाग को तीन जगह अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरीके से आपने पैसे का इस सप्लीमेंट्री बजट में उपबंध किया है। जब खाद्यान्न के उत्पादन के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा की जा रही थी तो उसमें कहा गया था कि कृषि पर जोर देना चाहिए। जब आपने राष्ट्रीय विकास दर 8.6 घोषित की तो यह तय किया था कि कृषि में विकास दर चार प्रतिशत के हिसाब से बढ़ेगी और कृषि का यह योगदान होना चाहिए। लेकिन पिछली बार कृषि का योगदान मात्र 0.2 प्रतिशत हुआ और आपकी विकास दर घटी। उसका और कारण हम दे सकते हैं कि आर्थिक मंदी हुई। वैश्विक मंदी में हमारा रेगुलेटरी सिस्टम इतना अधिक मजबूत था कि हमने अपने आर्थिक ढांचे को डगमगाने नहीं दिया। विकास दर थोड़ी घट गई। लेकिन यह बात भी सही है कि कृषि के मामले में सरकार का जो भी नीतिगत निर्णय होता है, उसके आलोक में खाद्यान्न के उत्पादन पर, अनुसंधान पर, बीज के मामले में और रिसर्च के मामले में जो आपको जोर देना चाहिए, वह आपने मूल बजट में नहीं दिया। इसीलिए आपको यह सप्लीमेंट्री बजट में लाना पड़ा। इसका मतलब है कि सरकार को अपनी नीतियां बनाने के मामले में बहुत ज्यादा कांफीडेंस नहीं रहता है। सरकार को नीतिगत मामले में विश्वास रहना चाहिए।

यशवंत बाबू ने ठीक कहा कि यह बजट पास हो जायेगा। हम लोग इसे रोक नहीं पायेंगे और रोकना भी नहीं चाहते हैं। यह सप्लीमेंट्री बजट पास हो जायेगा। लेकिन जो खाद्यान्न उत्पादन वाले प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में इस बार भयंकर सुखाड़ आया है। इसका खाद्यान्न के उत्पादन पर विपरीत असर पड़ेगा। सिर्फ झारखंड, बिहार में ही नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुखाड़ की आहट नहीं बल्कि सुखाड़ आ गया है। बिजरा खत्म हो रहा है। लेकिन सरकार ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया है।

यह जो सप्लीमेंटरी बजट आया है, उसमें उसका कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है। जो सुखाड़ वाले प्रदेश हैं, वहां धन न देने से हम उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिहार और झारखंड को विशेष सहायता मिलनी चाहिये। अभी बिहार सरकार ने 38 जिलों में से 28 जिलों को सुखाड़ प्रभावित घोषित किया है, उन्हें आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार के सप्लीमेंटरी बजट का समर्थन करता हूं।



श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी (संत कबीर नगर): सभापति महोदय, आपने मुझे अनुपूरक मांगों पर बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपका आभार मानता हूँ।

सभापति महोदय, आज यहां अनुपूरक मांगों पर चर्चा हो रही है। सरकार ने आम आदमी की जो परिभाषा परिभाषित की है, उसे मजबूत करने के लिये हम लोग बैठकर ये सब बातें कर रहे हैं। आम आदमी कितना सुखी है, यह किसी से छिपा नहीं है। ग्रामीण इलाके में आम आदमी रहता है। हमारी खेती भी एक मुख्य इंडस्ट्री है, क्या गत 63 साल से केन्द्र सरकार ने उसे खुशहाल बनाने के लिये कोई कदम उठाया है जिससे हमारे किसानों, गांव में रहने वाले नौजवानों को खुशहाली मिल सके। उनके बच्चों का पोषण सही तरीके से हो सके, इसके बारे में भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, हमारी जमीन खुशहाल नहीं होगी, हमें हरियाली नहीं दिखेगी। इसके बारे में सरकार को जरूर सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, हम लोग ग्रामीण इलाके से आते हैं। हमारे क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बात कर रहे थे कि बिहार और उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता की बुनियादी जरूरतें हैं, जिनको पूरा करने के लिये कुछ नहीं किया जाता है। हर साल वहां बाढ़ आती है जिससे हजारों एकड़ फसलें डूब जाती हैं। सरकार को बाढ़ की रोकथाम के उपाय करने चाहिये क्योंकि जल जमाव हो जाता है, किसानों की फसलें डूब जाती हैं और वह बरबाद हो जाता है। यहां तक कि किसान को अपने बच्चों की शादियां टालनी पड़ जाती हैं। इन लोगों की बुनियादी आवश्यकतायें अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं। सरकार को इस पर गौर करना चाहिये। वहां छोटे-छोटे लघु उद्योग हैं - जैसे बुनकर और कामगार हैं, उन को रोज़ी के अवसर देने के लिये जो पिछला बजट था, उसमें कोई प्रावधान नहीं था। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना में उत्तर प्रदेश में पिछले आठ महीने से फेज-8 और फेज-9 में कोई पैसा विकास के लिये नहीं गया है।

सभापति महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सरकार के पास यहां रिपोर्ट आ गई है और उस का लक्ष्य था कि सर्वे कराकर वर्ष 2012 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत से जोड़ देंगे। गांवों में रोशनी जगमगाने लगेगी लेकिन कोई पैसा उत्तर प्रदेश सरकार को उस मद में नहीं दिया। आज भी गांव का आदमी जब बाढ़ आती है, उस एक ही बंधे पर जानवर और इनसान रहते हैं। जब उसे सांप काट देता है, अगर उसके बच्चे की मौत हो जाती है तो उसकी मां से पूछिये कि उसके दिल पर क्या बीतती है? हमारे यहां की यही समस्या है।...(व्यवधान)



सभापति महोदया : आप चेयर को सम्बोधित कीजिये।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, मैं आपके जरिये सरकार को बताना चाहता हूँ कि खेती हमारा मुख्य उद्योग और पेशा है। भारत के गांवों में लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां गरीबों की संख्या ज्यादा है। उनके उत्थान की बात होनी चाहिए। पिछले बजट में इन चीजों का प्रावधान होना चाहिए था। ये जो राष्ट्रमंडल खेल हो रहे हैं, इसके लिए पैसे का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहां एस.सी., एस.टी. से संबंधित गरीब छात्रों के हकों का 700-750 करोड़ रुपया राष्ट्रमंडल खेलों में खर्च करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी पैसा कम पड़ रहा है।...(व्यवधान) हमारे यहां उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम डिमांड्स पड़ी हुई हैं। पैसा अवमुक्त नहीं हुआ है। हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी भयानक बीमारी होती है। बाढ़ आने के बाद जल जमा होता है और पानी सड़ जाता है। इंसिफेलाइटिस जैसी बीमारी होती है। उसे जापानी इंसिफेलाइटिस कहते हैं। भारत सरकार की तरफ से एक बार टीकाकरण हो चुका है, दूसरी बार जब वह टीकाकरण किया गया तो यहां के वैज्ञानिक वहां गये और उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट में यह पाया गया कि वह टीका काम के लायक नहीं है। मैं यहां के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ। वे वैज्ञानिक दिल्ली से गये थे और उन्होंने चैकिंग की थी। यहां पर बैठे हुए हमारे तमाम सांसद लोग इस बात को जानते हैं। कई बैठकें हो चुकी हैं, एक बैठक गोरखपुर में हुई थी, बनारस में बैठक हुई थी, इलाहाबाद में बैठक हुई थी, लेकिन आज तक, मई के महीने से और अब यह बरसात खत्म होने का समय आ रहा है, लेकिन टीकाकरण के लिए जो धन या टीके जाने चाहिए थे, वे भारत सरकार ने नहीं भेजे हैं। अगर आपके पास पैसा कम है तो आप निश्चित रूप से इस तरह के कार्यों के लिए पैसा लीजिये। जिन्हें आवश्यकता है, जिनकी बुनियादी जरूरतें अभी तक पूरी नहीं हो पायी हैं, कम से कम उनके बारे में आपको ध्यान देना चाहिए। जब तक बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, तब तक भारत समृद्ध नहीं बन सकेगा। खेती से जुड़े, गरीब लोग जब तक मजबूत नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता, इनके बारे में आपको सोचना होगा और ध्यान देना होगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदया: भीष्म शंकर जी आप दायें, बायें की बातें मत सुनिये, आप अपनी बात कहिये।

श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी : महोदया, मैं आपको उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में खनिज सम्पदा होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम खनिज सम्पदा चीन चली जाती है और इसी के कारण नक्सलिज्म की समस्या है। यह समस्या पशुपतिनाथ मंदिर से शुरू होकर तिरुपति मंदिर तक चली गयी है। यह समस्या दिन-रात बढ़ती जा रही है। वहां का आदमी मजदूरी करता है,

लेकिन कुछ नहीं पाता है। कमाने वाला नहीं खाता है, उसे हक नहीं मिलता है, उसका हक मारा जाता है। दूसरे लोग जो दलाली का काम करते हैं, उन्होंने इसे एक व्यवसाय बना दिया है और वे इससे फायदा उठा रहे हैं। तमाम तरह की खनिज सम्पदाएँ हैं- चाहे लोहा हो, कोयला हो इनका बुरी तरह से दोहन हो रहा है। वहाँ के गरीब लोग प्रताड़ित होते हैं और वे आज हथियार उठाने पर मजबूर हो गये हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। उत्तर प्रदेश में केवल तीन जिले नक्सल से प्रभावित थे और वहाँ पर कम से कम सरकार ने विशेष पैकेज सड़कों और बिजली की व्यवस्था के लिए दिया था, लेकिन वहाँ पर आज तक उन सड़कों के लिए धन नहीं गया।

महोदया, बाढ़ आती है और बाढ़ के लिए गाइडलाइंस भी होती हैं। सीठब्ल्यूसी की गाइडलाइंस है, जिसके अनुसार पैसा दिया जाना चाहिए। पंचेश्वर, करनाली और अन्य परियाजनाओं पर भारत सरकार के प्रतिनिधि दस्तखत कर चुके हैं। यदि उस पर रोक लगा दी जाए तो वहाँ बिजली पैदा होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को बाढ़ से राहत भी मिलेगी। बाढ़ से उनके खेत बर्बाद हो जाते हैं। इससे उनका बचाव होगा और उनकी जिंदगी खुशहाल होगी।



महोदया, हमारे देश के नौजवान को बाढ़ की विभीषिका से पीड़ित होकर दूसरे प्रदेशों में जाकर नौकरी खोजनी पड़ती है। आप भी तमाम अखबारों में पढ़ते होंगे कि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश और बिहार के नौजवानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। इसके लिए पीएमजीएसवाई, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और इंसीप्लाइट्स जैसी बीमारी के इलाज के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

महोदया, हमें जितने उर्वरक की आवश्यकता होती है, उतना प्रदान नहीं किया जाता है। गोरखपुर का उर्वरक कारखाना बीआईएफआर के पास पड़ा हुआ है।...(व्यवधान) उसे चालू कराने के लिए उपाय होने चाहिए...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Thank you Madam Chairman for permitting me to speak on this subject. I am not going to take much time of this House.

On behalf of the DMK, I support the Supplementary Demands for Grants. Our hon. leader from the BJP, Shri Yashwant Sinha has stated in his speech that this Supplementary Demands for Grants has been placed now, as the Government wanted to present a Budget in a way that it is not an inflationary Budget. But, on going into the expenditures mentioned in the Supplementary Demands for Grants, I beg to differ from his views. Most of the expenditures mentioned in the Supplementary Demands for Grants are for expenses relating to matters which had occurred after the presentation of the Budget. Take, for example, the Bhopal Gas Victims Fund, National Knowledge Programme or the implementation of Right to Education Act – the amount spent is Rs. 4,000 crore – the Bill was passed after the Budget was passed; for recruitment of special police force to deal with left wing extremism which is a growing concern in the country. All these things need money. So, most of these expenditures were required now, which were not required during the presentation of the annual Budget in February, 2010. Shri Yashwant Sinha also talked about corruption. But I do not know why he has left tax evasion.

It may be because that was the ransom claimed from him in the year 1998 to save his Government, he being a witness to that. So, tax evasion and corruption are two enemies of the country that, I think, Shri Yashwant Singh will accept.

Madam, most of these expenditures like the Prime Minister's Gram Sadak Yojana, Creation of Capital Assets to various institutions under technical education is Rs. 2,070 crore, Transfer to State and Union Territory Governments is Rs. 6,379 crore; to increase RBI shareholding in NABARD and National Housing Bank is Rs. 1,900 crore. Most of these expenditures are required today for claim disposal of National Agricultural Insurance Scheme is - Rs. 2,212 crore; The ICAR Revision of Salary Provision is – Rs. 1,074 crore; and New Raisings in the

Easter Sector for the Ministry of Defence is Rs. 1,500 crore. All these expenditures are required after the presentation of the General Budget. So, these are all expenditures which the country need – the Non-Plan Expenditure is Rs. 29,575 crore and Net Plan Expenditure is Rs. 25,012 crore.

Madam, on behalf of the DMK Party, we support the Supplementary Demands for Grants (General).

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Madam thank you very much for giving me an opportunity to speak.

Madam we had discussed the General Budget in detail in this House. Our hon. Minister of Finance has presented the Supplementary Demands for Grants for getting the sanction of this House. Though it is not possible to go through each and every subject where the expenditure is made, yet, at the same time, I think, this is also the time to review and examine the functions of the Government, especially after the last Budget is passed.

The Government claims that the growth rate is 7.4 per cent of GDP in 2009-10. It is true that India could avoid financial meltdown owing to the public sector domination, especially the public undertakings and also the public sector banks. But, at the same, when we go through the overall growth position, we cannot see such glaring examples in many of the sectors.

Madam, India being an agricultural country, agriculture grew only by 0.2 per cent in 2009-10 after slow growth rate of 1.6 per cent. Again, food grains production has fallen by 7.5 per cent in 2009-10 over last year.

Madam, the trade deficit is also widening and it is expected to be nine per cent by the end of 2010-11. Compared to 2004-05, the total contribution of agriculture came down from 18.9 per cent to 14.6 per cent in 2009-10. It is true that there is some progress in some sections, especially in the service sector, real estate and business services. Of course, there is progress and there is profit. But if you see that is mainly in the elited upper class sector where they are living. At the same time, the employment production is less in this sector. It is capital intensive instead of labour intensive. When we speak about the total work force in India, the half of the India work force is agriculturist.



But, at the same time, agriculture is still not in a better position. If we remember, in the Fourteenth Lok Sabha, we had given a loan waiver to the extent of Rs.70,000 crore to the farmers. Even then, there is no better position as far as the agricultural sector is concerned. Here, the Government has to make some more deep study. Though the Government is taking so much money to the farmers, yet it is not reflected. Though there is a progress in respect of the middle-class and the upper middle-class, yet, the situation with regard to the agricultural workers, peasants, small farmers is not quite good. We have not seen the progress to such an extent. That is why, yesterday also, when we discussed the price rise, on the one hand, we said that there is a better position. In 2004, what is the number of millionaires in the country? I do not blame that. The point is that their number has increased from 9 to 59. In 2004, it was 9. That means, Rs.4600 crore. Now, the number has increased. On the other hand, with regard to your Report, about 70 to 75 per cent of the people are getting only Rs.20 per day as minimum earnings. So, this gap has to be addressed fully.

It is true that you are doing something. At the same time, it has not gone to the people who deserve it, especially to the agricultural field. The National Sample Survey Organisation's Report makes it clear that the lowest rate of job growth is in the last three decades. Compared to the period in 1999-2000 and 2004-05, it was 12 million per year in those days. Now, it is only 8 million per year! So, employment creation is not in a better position. As the Western countries are advocating, jobless growth has become the idea on which we are focussing. Whether you intend it or not, that has become the reality.

As a result of the global recession, it has affected the employment market; export has reduced in the textile, plantation and the traditional industries, small-scale industries. As a result, employment opportunities, day by day and year by year, are sharply declining. That has become a fact. Of course, it will affect the day to day life of the people.

Another major issue that I would like to point out is the public sector. Public sector undertaking, by definition, is owned by the people. It was for the people, by the people. It was managed by the people. The Government has taken a drastic step of disinvestment in the public sector – whether it is profitable or not. Rs.25,000 crore worth of public equity has already been sold. The Government has decided to get Rs.40,000 crore again. The Government says that it is people's participation – a very attractive name that it has given. The Report of the NCAER revealed that only 0.5 per cent of the Indian households invest in equity. It means that a vast majority of the equities goes to the big business houses. It is really a looting the public asset that the Government has done. How can we say that it is for the *aam aadmi*? It is really the big persons who get the benefit. That is what the statistics reveals. I do not bring in any other politics in this. Instead of privatising the PSUs, they should be protected.

Here, I would like to give an example. In Kerala, there are 32 PSUs which are running in profit. We have also started another 8 PSUs. They have given about Rs.200 crore to the Exchequer not by way of disinvestment but by way of contribution. At the same time, the Government there is giving protection to the PSUs.

Sir, here, the Government is trying to open all sectors to foreign capital. The Commerce Ministry is pushing for 51 per cent FDI in multi-brand retail trade. I think the Congress itself is opposed to it. There are about four or five crores of retail traders in our country. If it comes, then, lakhs of people, lakhs of small traders will be thrown out of their livelihood. This policy is really dictated by the US-India CEO Forum. How can we say that the Government is functioning in a better way? The Government has also decided to allow the entry of foreign capital in the education sector also

That also is going to become a centre of corruption no doubt. I do not like to touch upon price rise because it was discussed in detail only day-before-yesterday. But at the same time I do not understand why the strong advocates of



the Government policy are very much silent with regard to universalisation of the Public Distribution System. Shri Baalu of the DMK strongly advocated that. In this connection, I would like to quote the examples of two States, namely Kerala and Tamil Nadu. Tamil Nadu has to give Rs. 4,000 crore as food subsidy and Kerala has to give Rs. 600 crore as food subsidy. So we are able to control the price rise. These are two good examples we can give. Therefore, these two States have to be compensated adequately by way of adequate financial assistance from the Centre.

MADAM CHAIRMAN: Please conclude now.

SHRI P. KARUNAKARAN: Madam, I have to touch upon only two or three points more.

The recent Supreme Court verdict has criticized the Government because the food grains are rotting in the godowns and not only that, the Supreme Court directed the Government to distribute it to the needy people. This is really a very big mistake on the part of the Government. In the Estimates Committee, it was mentioned that about 15 to 20 per cent of vegetables and fruits are getting wasted due to the absence of proper cold storage facilities.

Now, I would like to speak on some issues pertaining to my State.

MADAM CHAIRMAN: You can speak next time. Please conclude now.

SHRI P. KARUNAKARAN : I am concluding.

Then, in the norms prescribed for natural calamities, the States are requesting that lightning, sea erosion and land slides should also be included as they are not included now. I would request the Government to consider this. When the Government announces a relief package, the damage caused due to these calamities are not taken into account and they also do not take into account the human lives lost due to these calamities in States like Kerala and in many other States.

There is a long-pending demand for opening an IIT in the State of Kerala, but it has not materialized so far. The Prime Minister himself promised that, but it

has not materialized. This has to be sanctioned at the earliest because Kerala is considered as the first State to have achieved 100 per cent literacy rate.

With regard to food quota, I would request the Government to retain the food quota which was there in 2007.

As far as electricity allocation is concerned, earlier the allocated quota for Kerala was 1,400 megawatt. Now we are getting only 641 megawatt. In addition to that, we have got 183 megawatt of electricity which is unallocated to us. But there is no quota of allocation. So, I would request the Government to consider the request of the Government of Kerala as electricity is very important for agriculture and industries.

We discussed the issue of corruption charges in the allocation of 2G spectrum, but not action has been taken so far.

Then, the people of India, especially the women folk are eagerly waiting for the Women's Reservation Bill to be passed. You are in the Chair, Madam. But I do not think there is any chance of passing this Bill even during this Session.

This is not the time to speak about the IPL, but the Government has to consider the issues of APL and BPL seriously. I hope the Government would come forward to consider these important issues. So, a better introspection on the part of the Government is needed and that would be better both for the Government as well as the country.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): Madam Chairman, I thank you for allowing me to participate in the discussion on Supplementary Demands for Grants (General) for 2010-11.

The first batch of Supplementary Demands for Grants (General) for 2010-11 involving an additional massive expenditure of Rs. 68,294.30 crore over and above the expenses budgeted for 2010-11 in February is before us for consideration.

This additional expenditure includes a net cash outgo of Rs.54,588.63 crore. This net cash outgo will not have any adverse impact on the fiscal deficit the Government projected in the Budget 2010-11 due to excess receipts under non-tax revenue. A larger than expected revenue mop up of Rs.1.07 lakh crore from the auction of 3G and broad band spectrum has definitely bolstered the finances of the Government. You had only budgeted Rs.35,000 crore as non-tax revenue from 3G and broad band spectrum auction during the current fiscal. The additional mop up has definitely provided some cushion for managing the fiscal but do it carefully and do not squander it away.

The extra expenditure could not add to the budgeted fiscal deficit of Rs.3.81 trillion and it would largely be used to reimburse public sector oil marketing companies, top up expenses of educational projects and channel money through development programmes to Jammu & Kashmir and Left Wing extremist affected districts or States.

Here, public sector companies are going to receive Rs.14,000 crore as reimbursement for fixing the retail price of some petroleum products below cost between January and March. Additional expenses are Rs.7,333.53 crore towards rural development projects, such as road building and Rs.4,000 crore towards school education projects.

The Army has been sanctioned Rs.1,500 crore to create a Mountain Division on India's border with China. I am given to understand that trouble prone areas such as Jammu & Kashmir and districts affected by Maoist rebels

have received allocation under different heads spread across Ministries towards development projects, such as, skill building for youth and security services in the region.

The Government will be spending Rs.6,300 crore under PMGSY. The interesting aspect of this Supplementary Demands for Grants is that for India's quota increase in International Monetary Fund, the cash outgo would be Rs.2,860.11 crore. The Government would also create securities for Rs.8,467.04 crore towards India's quota increase at IMF.

There are many other details also. I am of the opinion that with another Demands for Grants likely to come towards the end of this year, fiscal deficit would be partially high. One may say that most of the extra spending is essential but some of it could have been avoided essentially so early in this fiscal year. The Government would have to strengthen its fiscal consolidation resolve and I find it lacking in this Supplementary Demands for Grants.

I would draw the attention towards the PMGSY. It is one of the most ambitious schemes which has huge socio-economic benefit.

It was conceived by the NDA in 2000 and re-packaged by the UPA. However, for five years now, the PMGSY is stuck because of crippling shortage of funds. Soon after the UPA-2 reign began in May 2009, the agency implementing PMGSY has 'put on hold' clearance to any new projects. I think, all the hon. Members present in this House are aware about it because they monitor the rural development programmes in their districts. It is stuck up. There is no improvement after this year's budget. The only exception made is for roads in Maoist-affected areas or districts, in border regions and some leftover projects.

This year's Budget enhanced the gross support to the scheme only marginally, by about 5 per cent, from Rs 10,650 crore to Rs 11,110 crore. To compensate, the credit component to fund the scheme was hiked by more than 50 per cent — from Rs 6,500 crore provisioned in 2009 to Rs 10,000 crore. This

money was to come from the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) window of NABARD.

However, it turns out that the project cannot avail even this credit facility fully – and this is the tragedy – this year as it has lost considerable leverage because of debt servicing of earlier loans from NABARD.

During 2009-10 and 2010-11, the Government has not sanctioned any road projects to provide connectivity in the non-Left Wing extremist affected 25 districts in Orissa. There are still 4932 unconnected habitations in Orissa which require all-weather connectivity as per the existing PMGSY guidelines. Why do you not allow the State to prepare the DPR for sanction of such road projects? That apart, 1237 individual habitations eligible under Bharat Nirman, as per cluster approach, are to be connected. These projects have not been included. The Union Government has declared only five districts of Orissa as Left Wing extremist affected districts. But, practically, Sundargarh, Dhenkanal, Kandhamal, Koraput, and Nabarangpur should be declared as Left Wing affected districts. This is my first point.

MADAM CHAIRMAN : Mahtab *ji*, please wind up. I am sorry; we have to finish this discussion by 6 o'clock. The time allotted to your Party was only five minutes.

Kindly, finish in four-five minutes.

SHRI B. MAHTAB : Orissa has claimed Rs. 380.17 crore compensation on account of CST reduction for the year 2007-08. ... (*Interruptions*)



The Union Government had sanctioned Rs.137 crore for that year. Against a claim of compensation of Rs.438 crore for the year 2008-09, the Union Government had sanctioned Rs.425 crore. For the year 2009-10, up to December 2009, Orissa had claimed Rs.363 crore but the Union Government had sanctioned Rs. 106 crore. This is the policy of the Government. ... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): How much money had been sanctioned? ...
(*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : The sanctioned amount for 2009-10 was Rs. 106 crore but the claim was Rs.363.84 crore. We are not asking gratis. What we are asking is as per the policy of the Government. It is the Central Sales Tax that we have foregone, which the Government has to compensate.

We are talking about GST. As per the guidelines for compensation of loss on account of phasing out of CST, the actual CST revenue during the year 2006-07 shall be taken as the basis of actual collection for the purpose of assessing the revenue for 2007-08, 2008-09, and 2009-10. You see the compound annual growth rate of total CST revenue for the period from 2003-04 to 2006-07. I fail to understand it. This must be the case with other States also. Why is it not being given? As per the revised guidelines also, Orissa has a claim and yet the Union Government is sitting over it.

Madam, one good thing has happened and everybody, cutting across Party line, should appreciate this. The Finance Minister has come out very openly on that aspect. Everybody should appreciate that. Within the last one year, there has been a tremendous investment, in a way one can say, in agriculture credit. It has overshoot the credit targets. The credit targets have overshoot in certain public sector banks, and it is mostly because of the Cooperatives. The reason is different. But the fact that it has overshoot the target and the Finance Minister also has increased the target this year.

My limited point here is this. Let us find out where this investment has actually taken place. Has it provided a mechanism that our growth in agriculture has increased or has it been invested in developing the machinery, mechanization of agriculture or has it been invested in construction of certain buildings or car sheds or on other aspects? Let us find out where this investment has taken place. It is a good thing but at the same time we also have to monitor where this investment has taken place. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN Shri Mahtab ji, you have already spoken for 15 minutes. Please conclude now.

SHRI B. MAHTAB : I will come to the demands of the people. I am limiting it to those now.

Taking a cue from the initiator of this debate, Shri Yashwant Sinha ji, I am reminded of the rural housing scheme, namely Indira Awas Yojana. ... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Now, Shrimati Harsimrat kaur ji.

SHRI B. MAHTAB : Madam, I will just take two more minutes.

Investment is there in the rural housing scheme. As a Member of Parliament, in the last Lok Sabha and also in the previous Lok Sabha, we were told that at the district level, the District Planning Committee should prepare a list of the beneficiaries for the next five years. The five years have been completed. How much is the allotment under IAY? I would like to give you one example here. We claim 14 districts in our State as the Maoists-affected areas. There, a total of 16,28,493 is the demand under IAY but the allotment this year is only 65,000. Another 15 lakh are left. We do not know how many years you require to provide the money under IAY to those Maoists' affected poor people.

17.00 hrs.

Next is Rajiv Gandhi Gramin Vidyuticaran Yojna. The same is the situation there. There is no proper monitoring. Same is the case about the National Rural Health Mission. I think, you will be more interested in this Health Mission. The



Comptroller and Auditor General has come out with their Audit Report and it clearly demonstrates that the corruption had taken place.

MADAM CHAIRMAN : Mahtabji, please cooperate. We have to discuss Supplementary Demands for Grants (Jharkhand) also.

SHRI B. MAHTAB : This is an important aspect. Yesterday, of course, the discussion was on a different footing and I did not mention it there. On the National Rural Health Mission, crores and crores of rupees are invested. We are in the fifth year and this programme is going to continue for another two years. But MPs have very little role to play in that Mission to monitor.

MADAM CHAIRMAN: Now, Shrimati Harsimrat Kaur Badal

SHRI B. MAHTAB : When a question was posed, we were told that all respective MPs will be chairing the monitoring mechanism as we are doing it in the rural development. When I asked: "Whom did you entrust this job with?", it was said that the Ministry had written a letter to the Chief Secretary of respective State Governments. Already six months have passed. I do not know any Member is aware about this... (*Interruptions*) Not a single Member is aware about it because the respective State Governments have not informed any MP. The MP is just a Member of that Committee, which is chaired by the District Magistrate.

The tragedy is that in my State in a place called, Koraput, which everybody remembers, spurious drugs were purchased by this programme and casualties had also taken place. A Minister had to lose his job. I am yet to know what action is being taken against the officers, who were involved in it.

MADAM CHAIRMAN: Mr. Mahtab, please cooperate.

SHRI B. MAHTAB : All this has been reflected in the report.

MADAM CHAIRMAN: Nothing will be reported, now.

(*Interruptions*) ...*

MADAM CHAIRMAN: Mahtabji, please cooperate.

* Not recorded.

SHRI V. NARAYANASAMY: The National Rural Health Mission Scheme is being implemented by the State Governments and the fund is provided by the Central Government. If the spurious drugs have been distributed there, the District Administration and the State Government are responsible for that. You tell them to take action... (*Interruptions*)

MADAM CHAIRMAN: Mr. Minister, please.

... (*Interruptions*)

SHRI YASHWANT SINHA: The issue is, why do you not give a role in it... (*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Proper implementation lies with the State Government and not with the Central Government... (*Interruptions*)

SHRI B. MAHTAB : Madam, my last issue is relating to the MPLAD... (*Interruptions*)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

SHRI B. MAHTAB : I think, the Minister of Planning and Programme Implementation looks into it.

सभापति महोदया : अब श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की बात के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान) *

सभापति महोदया : महताब जी, आपने अपनी बात कह दी है। Please conclude.

* Not recorded.

SHRI B. MAHTAB : This is a request to everyone. Let us not give any project to a District Magistrate. Instead of asking and pleading for increasing of funds or to withdraw scheme, let us not implement this programme. Let us not give any suggestion to the Collector. Let it lie idle. Then only, I think, some sense would prevail on this Government.

With these words, I conclude my speech.

MADAM CHAIRMAN: Thank you.

Now, Shrimati Harsimrat Kaul Badal.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL (BHATINDA): Thank you, Madam. I would not take too much of your precious time as I understand the time constraints. So, I would just get straight to the point.

While we discuss the Supplementary Demands for Grants, I will hope that when I raise a few points regarding my State, they will not fall on deaf ears but the genuine difficulties and the plea of the people of my State will be heard because it is surprising that in the last six years the Budget that has been passed by this Government has never ever addressed any of the major problems that have been faced by my State, which in spite of being only 1.5 per cent of the total area of India, contributes over 60 per cent of the food grains to the Central pool. It feeds the hungry mouths of this nation.

17.07 hrs

(Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

At times we have felt that we have been penalised for shouldering this responsibility and it is sad that now when the State faces a huge crisis in terms of food production because of its natural assets, there is no attention at all that the Government pays towards stabilising, modernising and helping out the State in this hour of need, a State which shoulders this responsibility of feeding the nation for the last so many years.

Sir, I would also like to point out that being a border State and having a live and active border of almost 550 kilometres, today the State faces a variety of challenges. But before I get into that, I would just like to flag something for the notice of this House because often people refer to Punjab as a very prosperous State. I would like to set the fact right.

Till 1986, Punjab was a cash surplus State, a revenue surplus State, which then saw a long period of militancy. The longest President's Rule of nine years in the State has such an effect that the Government followed a policy of high expenditure and no raise in taxes. Due to this, the State fell into such a huge debt

trap that from cash, revenue surplus State, today Punjab has a standing debt accumulated basically over the nine long years, which is the longest period of President's Rule in this country. Today that debt stands at Rs.64,924 crore, almost Rs.65,000 crore. Out of this amount of Rs.65,000 crore, which is our debt, I would like to point out that each year we pay an interest of Rs.5,700 crore. With the implementation of the recommendations of the new Pay Commission, we pay Rs.12,000 crore to our employees. As a result, when you calculate just the interests and the salary payment to the employees, it comes to Rs.17,700 crore.


What is the earning of the State? I would like to point out, including what we get from our share of the Central taxes, it is only Rs.16,600 crore, which means, every year the State is getting into a bigger and bigger debt trap for no reason of the State but because the way the President's Rule, the way the taxes were administered and the high expenditure that was obtained three decades ago. But it is surprising that this Government, instead of looking at a State which is a border State, a live border State, where narcotics are being passed through our neighbouring State, where terrorists are being passed through our neighbouring State, instead of stabilising and securing this State, it is adding to its problem and not doing a thing to lift a finger to stabilise the conditions of the State.

So, I would like to point out that today the State faces such an acute financial crisis that we have no funds to safeguard us from the challenges that we face today and to put in our own resources to mobilise them, and that is why I look towards the Centre to realising the problems faced by my State.

The most important thing today we are talking about passing of Food Security Bill. I think it is a joke when this Government talks about food security without realising that food does not grow in thin air but it needs water for agriculture to be sustainable and for food to grow. First, you have to talk about water security. If there is no water security, where is the food going to get produced? But this country does not talk about water security.

I would also like to point out that the State, which produces 60 per cent of the food grains today, has an irrigation system which is 150 years old. I would like to know what this Government makes today which would even last 150 years.

But we have an irrigation canal system which is a 150 years old, which for the last century has received no funds for maintenance, for rejuvenation, for upgrading or for repair. As a result, almost 20 per cent of our precious water is getting wasted because of this canal irrigation system being too old.

MR. CHAIRMAN : Try to be brief. This is a discussion on Supplementary Demands. At 5.30 p.m. we have to complete it. There are many speakers. The  Non-Minister is going to reply.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : This is a huge problem. It is very important. Please do not ring the bell because I am not an expert to know what to say. Please allow me to complete myself. Just give me ten minutes. I will wind up in ten minutes. I have very few remarks.

MR. CHAIRMAN: You have already taken seven minutes. Please try to be brief.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Water is a very important issue not just for my State, but for the rest of the country. If you do not think that this is an important issue, I can sit down and forget all about it. Punjab has been pushed under the carpet for too long. It is time these issues were addressed. That is why I stand here.

Canal irrigation system is leading to 20 per cent loss of water. Our reservoirs are functioning at only 20 per cent of their capacity. As a result, when there is a rainfall, instead of storing that water, all that water is getting wasted. The rules that this Government makes are so biased that at times we feel that they are only made to make sure that Punjab cannot gain out of it. There is a rule under the AIDP scheme which says only when one project is complete, can the next project be taken up under Accelerated Irrigation Benefit System. In a State which has a two to three cropping cycle, how can we stop the water in the canals for not more than two months? And the rejuvenation work of the canals can only take place in

those two months. If all the work has to take place only two months in a year, it is easily going to take three or four or five years to complete it in one canal. If all the canals have to wait until one round gets complete, we will be looking at the next 60 years before work in all the canals in Punjab are done.

According to the World Health Water Survey, the water tables of Punjab have gone down so much that in the next 35 years Punjab can turn into a desert. Today the only difference between Rajasthan and Punjab is the difference that Punjab has the natural resource of water. If we do not have water there is no difference between the desert Rajasthan and Punjab. If we allow our water to get wasted like this, it is just a question of a few years before we actually turn into a desert. I would request this Government to make Punjab into a special agricultural zone and to remove these conditions in the State, so that the whole canal system is treated as one project and funds be given to them for the entire project instead of one canal at a time.

Also, please look at the bias. You may think that I just talk like that. There is an inter-State project for re-railing of the Rajasthan Feeder and Sirhind Canal. These are two canals which go parallel. You will be surprised to know that whereas Punjab has to put in 75 per cent of the money for this project, Rajasthan has to put in only 10 per cent. What is the reason? I do not know. I would like an answer from this Government. When two canals go simultaneously, they are affecting both the States, why should one State have to put in 10 per cent and the other State 75 per cent? ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not interrupt her. When your turn comes, you can reply for that if you want.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Is it that our farmers are not poor? Is it that a State is cash rich? While I appreciate the grants that have been given to Rajasthan, I appeal that we be given the same amount as well and this discrimination not be done.

You saw the damage that the river Ghaggar did in the last few months and the last month we saw a great damage. This is an inter-State river. I would appeal that looking at the massive damage to human lives to crops to cattle to infrastructure to food grains, this taming of the Ghaggar river be created, the canalization be done and it be treated as a national project.

I would also like to mention that there is a Calamity Relief Fund which is such a joke and I would like all the Members to hear this. When the destruction caused by the Ghaggar river happened, you will be surprised to hear the norms of CRF that a farmer who faces total loss of crop gets only Rs.1600 per acre as compensation. The bigger joke is that the farmer who has had to leave his house, leave his property, leave his cattle and find some place to stay and feed himself gets Rs.20 a day for food and Rs.15 a day for his child. Do you think that anybody can sustain with food from this Rs.20 a day? Can any child live on Rs.15 a day? Can any farmer be compensated with Rs.1600 per acre? I appeal to this Government to revise this nonsensical norm urgently. (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. The Minister is going to reply at 5.30 p.m. Please cooperate.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, also I would like to say that there is a great talk about the shortage of storage facilities.

MR. CHAIRMAN : You have already mentioned it.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: Everyday we read in the newspapers how an amount of Rs. 60,000 crore is being spent. ... (*Interruptions*) Sir, this is a very important point.

MR. CHAIRMAN : I now call Shri Shailendra Kumar to speak.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, please allow me. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Already during the discussion on price rise, so many Members raised this point. Please cooperate.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : I will take only two minutes. ...
(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister of Finance has to reply at 5.30 p.m.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, storage is a very important point in the State of Punjab. I would like to tell you that how, besides the fact that Rs. 27 crore worth of grain is rotting even today.

MR. CHAIRMAN : Madam, you have to cooperate. The hon. Minister has to reply and there are ten more Members to speak.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : In reply to a Question asked in the Parliament we were told that the Government carries a surplus stock of grain and for carriage of this surplus stock of grain they are spending Rs. 27 crore per day and if you calculate it comes to almost Rs. one lakh crore a year. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar to speak.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Sir, in the Budget they have put aside only Rs. 40 crore to create new facilities.

MR. CHAIRMAN : Shri Shailendra Kumar is not present. Shri Anandrao Adsul may speak now.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : We are spending Rs. 10,000 crore on carrying excess surplus. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Please cooperate. The hon. Minister has to reply at 5.30 p.m.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : Why do they not create modern silos in which the grains do not rot and the rodents are not eating them and human beings can consume it?

Sir, at the end, I would like to urge two-three more things because this is very important for the State. I hope that for the canalisation we will get some money. I hope that this Budget that is going to be coming up right now will see Punjab's name in it and since we produce 60 per cent of the foodgrains we should be compensated. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : You have already said it. You have mentioned these points. Shri Adsul, you may start now. Nothing else will go on record except the speech of Shri Adsul.

*(Interruptions) ...**

MR. CHAIRMAN : Madam, you have taken 15 minutes and you are saying you are not given time. I am very sorry for that.

Shri Adsul, please conclude in five minutes because at 5.30 p.m. the hon. Minister has to reply and there are three-four more Members to speak.

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL : कहा जाता है कि परमात्मा के घर भी देर है अंधेर नहीं। मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह सरकार के बजट में भी देर है अंधेर नहीं।

* Not recorded.

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Yes, sir. I will be very brief.

The first batch of Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011 includes 61 Grants and two Appropriations the total expenditure of which comes to Rs. 68,294.30 crore. Ultimately, as our senior colleague Shri Yashwant Sinha has told, we all have to support it for the sake of running the Government. I will come to only two points which I think that they are controversial schemes.

The first thing is that the Government, in the Ministry of Rural Development, provides a sum for the Prime Minister's Sadak Yojana. But wherever there is a tribal area and there is a tiger project, we can build only concrete roads there. As per this scheme, the estimate comes to more than whatever is projected. The Government has to look into it. I have written letters so many times. But no response has been given from the Government's side.

Secondly, in my constituency, Amravati, there is a tribal area called Melghat. There is a tiger project. In that tiger project, there are 68 villages belonging to the tribals. Whenever we are deciding about the tiger project, if the tigers are there, rehabilitation is essential and it was announced. A package of Rs. 10 lakh was also declared. But, unfortunately, for the last one year we are asking for this amount of Rs. 261.10 crore. Yesterday night one incident has taken place where six persons belonging to the tribals were killed by the tiger. That is a very serious thing and the Government has to take note of this point and immediate action has to be taken for the rehabilitation of those tribal families as early as possible.

MR. CHAIRMAN : Thank you very much. You have taken less than the time given. Mr. Semmalai to speak now.



SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Supplementary Demands for Grants and Appropriation Bill moved by the hon. Finance Minister. Even though the grants now proposed do not cause any fiscal deficit, as mentioned in the introductory note, I would suggest that future budgetary prescription should conform to the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. It should also be the prime duty of the Finance Minister to contain fiscal deficit within the manageable limits. At the same time, Non-Plan expenditure must be pruned. This is an absolute need.

Among all the departments, the Department of Agriculture has to be given more importance. If we neglect agriculture, it will result in lesser production and productivity. While the population growth stands at 1.9 per cent, growth in production on farm front is only 1.2 per cent. This situation necessarily results in food shortage and alluring poverty. The figure of persons dependent on agriculture has come down from 71 per cent to 62 per cent, indicating lack of interest in farm operations. Hence as urged by the experts, it would be better if the Government allocates more amount to agriculture sector.

I would also like to emphasise on the need for construction of additional godowns for storage of procured food grains, as told by other hon. Members, because what is produced must be saved for consumption. At least in the next year's Budget, the Planning Commission should be more liberal in allocating sufficient funds for construction of godowns.

The Budget allocation and the grants now made to education are not sufficient. The grant made under the head 'Right to Education' is only Rs. 4,000 crore. Some States are urging the Central Government to grant more allocation and implement the programme as a fully Centrally-funded programme. Taking into account the importance of the programme and the States' financial position, the Centre should come forward to bear the expenditure up to maximum level for the Right to Education so that our dream becomes a reality.

Our lofty aim to make higher education accessible to poor students and to raise its coverage from 12 per cent to 25 per cent, grant of education loan by banks is an important instrument. Even after the Government gave an assurance that there will be a moratorium on interest chargeable to educational loans, the banks are insisting on payment of interest when the students approach for loan for the second year. The bankers say that there are no clear instructions to them to postpone the payment of interest. I think, there is some snag in it. Even though in the present grant under the head of higher education, there is no mention about allocation for reimbursement of interest to the banks, the Government has to bear the interest on the loan payable to banks by way of reimbursement through the Reserve Bank of India. I request the hon. Finance Minister to streamline the procedure and ensure speedy reimbursement of interest amount to banks because they are all commercial banks and only after collecting the interest, they would be able to move forward.

Then, rural development is the pivotal point of progress of any nation. The allocation to PMGS Scheme continues to suffer from inadequacy of funds. So, I request the hon. Finance Minister to allocate more funds to PMGS Scheme.

The Supplementary Grants for the IT Ministry is about Rs. 1,012 crore. I wonder why the Ministry demands such an allocation when the 2G spectrum deal has ended up with a loss of Rs. one lakh crore to the exchequer due to the questionable and highly-debatable method adopted by the Ministry. One day, the cat will be out of the bag and the Ministry is bound to answer the public in this regard.

Even though the hon. Prime Minister has said that : “Although, there is a huge gap in the prices of spectrum for 2G and 3G services, the whole issue needs to be seen in proper perception.” The Government is yet to initiate credible action to enable the people to see the issue in clear perception. Why is the Government shying away from initiating action and who is behind it? The people are waiting curiously to know as to what has happened in the spectrum deal.

In conclusion, it must be the endeavour of everyone to see that the amount allocated and the grants made under various heads reach the targeted beneficiaries in full by strengthening the monitoring system.

MR. CHAIRMAN: The next speaker is Shri Shailendra Kumar. You have three minutes at your disposal to speak because by 5.30 pm, we have to complete the discussion. Therefore, be very brief.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे वर्ष 2010-2011 की अनुदानों की अनुपूरक मागों पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। जब मेरे बोलने का समय था, मैं यहां नहीं था, एक आवश्यक काम से चला गया था क्योंकि स्व. जनैश्वर मिश्र का आज जन्म दिवस था। उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूँ।

सभापति महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्री बहुत ही विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हैं। जब प्रतिवर्ष जनरल बजट पेश होता है, उसके बाद हमेशा से ही सप्लीमेंटरी बजट पेश होता आया है। मैं ने श्री यशवंत सिंहा जी के भाषण का कुछ भाग सुना है। वह भी श्री अटल जी की सरकार में काफी अनुभवी वित्त मंत्री रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि अगर जनरल बजट में इसका प्रावधान कर दिया जाता तो आज इसे लाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे माननीय सदस्यों ने बड़े विस्तार से अपनी-अपनी बातें रखी हैं। हमारे संविधान में कई प्रदत्त बातें हैं, लिखित हैं जिनकी हम शपथ भी लेते हैं - मंत्री के रूप में या सांसद के रूप में। उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात कही गई है। अगर आंकड़े देखेंगे तो मेरे ख्याल से बजट का प्रावधान आरोप-प्रत्यारोप के रूप में गुजरता है। यहां बहस होती है और जो उस समय की सरकार होती है कि तुम्हारी सरकार के समय यह हुआ और जब वह विपक्ष में चली जाती है तो आने वाली सरकार पिछली सरकार के बारे में कहती है। इस तरह एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगते रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान देना होगा। जब यूपीए-2 की सरकार आयी और हम सदन में आये तो कहा गया कि 100 दिन के रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, हम 100 दिन में काया-कल्प कर देंगे। ऐसा लग रहा था कि सरकार के पास संसाधन पर्याप्त हैं और समय भी ठीक है लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि जब से यूपीए-2 की सरकार आयी है, तब से महंगाई बढ़ी है। जब भी हम लोग मूल्य वृद्धि पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करते तो सरकार की तरफ से जवाब आता कि हम महंगाई रोक लेंगे। इसी संदर्भ में कल भी माननीय वित्त मंत्री ने बहुत सारी बातें बतायीं कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन कहीं भी महंगाई रुक नहीं पा रही है। जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम इस सरकार के हैं, उन पर ठीक से अमलीजामा नहीं पहनाया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि जो आम आदमी है, गरीब मजदूर, किसान है उन तमाम लोगों की दिक्कतें हैं, उन सब की ओर बड़े विस्तार से देखना पड़ेगा।

खासकर हमें ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ देखना पड़ेगा। आज किसान परेशान है और वह आत्महत्या कर रहा है। मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि जो सरकारी सर्विसेज में लोग हैं, जो लोग फौज में हैं, वे भी आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? हमें इन तमाम कारणों का पता लगाना पड़ेगा। इस सरकार पर कहीं न कहीं आम जनता ने विश्वास जताया है। आम जनता के साथ धोखा न हो, यह सरकार को सोचना पड़ेगा। बातें बहुत सी थीं, लेकिन अभी दूसरा बजट भी लेना है, आपकी ओर से बार-बार घंटी बज रही है। मैं यही कहना चाहूंगा कि चाहे जैसा भी हो, हमें इसका समर्थन करना ही है। हमें इसे पास कराना ही है।... (व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा (जहानाबाद): आप एमपीलैड के बारे में भी बोलिए। एमपीलैड को बढ़ाना चाहिए। सम्पूर्ण सदन की यह भावना है।... (व्यवधान) आप अभिभावक है, आप सदन के नेता हैं। आप एमपीलैड को बढ़ाइये।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : महोदय, मैं अंत में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सम्मानित सदस्यों की भावनाओं से अवगत कराते हुए प्रणव दादा से गुजारिश करता हूं कि, इसके पहले भी आपसे निवेदन किया गया था और यह बात बार-बार उठती है, या तो एमपीलैड को खत्म कर दीजिये या फिर इसे बढ़ा दीजिये।... (व्यवधान)

श्री जगदीश शर्मा: महोदय, या तो यह वापस हो या इसे बढ़ाइये।... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I am aware of the time constraint, even then please allow me to complete all my points. I am not going to make a long speech.

The Supplementary Demands for Grants total Rs. 54,589 crore. This number is not a small number. In terms of GDP ratio, it is one per cent of the GDP. In terms of the Budget which was placed earlier, it amounts to five per cent of the Budget. So, it seems that it is a poor performance in terms of fiscal management. I do not know what will be the amount in the next Supplementary Demands for Grants which will be presented in the Winter Session. In the next Session, I do not know how much money will be demanded and that is not clear to us. This is a huge Demand. It should have been properly managed in the earlier Budget.

The next point is about the source. I do not know whether these Demands will have any impact on the fiscal deficit or not. Our fiscal deficit was 5.5 per cent, but with this huge amount sanctioned, I do not know whether it will be having any impact on our fiscal deficit or not.

It has appeared in the print and other media that Rs. 1,06,000 crore was generated from the sale of spectrum, that is, from the sale of broadband and third generation mobile spectrum as against Rs. 35,000 crore which had been budgeted for. My point is how this fiscal deficit will be met. Will they borrow or will they sell the family silver? This is an example that they are going to sell the family silver. This is their attitude and this is their philosophy, taking the money received from non-tax revenues. This is not a very happy state of affairs. This is not a very good economy, as far as our country is concerned.

Now coming to expenditure, yesterday during his reply, the hon. Finance Minister mentioned that Rs. 14,000 crore have been provided to the petroleum companies; they have already been too much subsidy earlier.



There is already a subsidy of Rs.3,1,800 crore. In addition to that, Rs.14,000 crore are being provided. I would like to know whether with the increase in the petroleum products, they would earn much. Not only that, deregularization has already been done. Even then Rs.14,000 crore have been provided to the total amount. On the other hand, in agriculture only Rs.3,286 crore have been provided putting together all the aspects of agriculture. In Women and Child Development Ministry, only Rs.0.02 crore, that is, only Rs.2.00 lakhs have been provided to the Women and Child Development Ministry. In irrigation, only Rs.30 crore have been proposed. Irrigation is the most important area.

My predecessor speaker has rightly said about the situation of water in the country. It may be the drinking water problem; it may be for irrigation and other things. Irrigation is the most important component. Not only that, the rain fed area is there. But only Rs.30 crore have been proposed for irrigation.

Now we are talking about the Green Revolution. I appeal to the hon. Finance Minister in this regard. Only Rs.4,00 crore for Green Revolution in the Eastern area is not sufficient. It is quite meagre. How will the six States be covered by only this meagre amount? I would request him, if possible, to increase the amount. As it is the Demands for Grants, there is a convention and we would not stand in the way. We are not opposing it. But I think what is missing is the prioritization of this area. With these words, I conclude.

*SHRI C. SIVASAMI (TIRUPPUR): Mr. Chairman, I thank you for giving me an opportunity to speak on the supplementary Demands for Grants 2010-11. The Government has taken measures to enhance the fund allocation to various Ministries and I welcome the same. But at the same time I would like to point out that textile sector a big job provider next only to Agriculture ought to have got more of fund allocation. Textile units that have facilities to compete with the global competitors were getting incentives from the Government but such grants are not being extended now for want of funds. This greatly affects the entrepreneurs and naturally the textile industry. I would like to point out that Government has failed to monitor the growth of textile sector. Cotton price rise, yarn price rise, power cuts, fall in Dollar and Euro values have all greatly affected the textile sector. Many of the textile units all over the country, especially those in Tiruppur, the knitting industry town, are all meeting with huge lose this year. Small and medium units are being closed. Lakhs of textile workers dependent on these units are at the verge of losing their livelihood. This is due to our inability to cope up with the competition from China, Bangladesh and Pakistan. Yarn price in India has increased only because our permitting export of cotton. It is a misconception to believe that cotton growers benefit out of cotton exports. In fact, the middlemen traders procure all the cotton from the farmers at the time of yield and resort to hoarding. When cotton is to be exported, farmers do not have cotton. So naturally, it is the cotton traders who make huge profits. So cotton exports are not profitable to cotton growers. This has brought about stiff challenges to the textile industry. Hence, I urge upon the Government to allocate more funds to agriculture and extend a grant of at least 5000 rupees per acre to a cotton farmer. This will directly benefit the cotton growers and will pave way for a significant growth in the textile sector.

*English translation of the speech laid on the Table originally in Tamil

Cotton grown in our country must be processed entirely here and yarn must be manufactured here itself. Cloth production and Garments manufacturing provide a cycle of opportunities to all the textile workers. It is needless to remind the Government that this attempt at self-sufficiency will help us to generate job opportunities and increase money flow helping Government to earn foreign exchange.

NH-47 that pass through Tirppur in the Coimbatore district is being converted to a six lane road for which the Government is in the process of acquiring land both the cultivable land and patches of lands in the residential areas. The compensation paid to the agriculturists are found to be meagre. Sengappalli, Perumanallur, Avinashi and Karrumatthampatti are the places near Tirppur and Coimbatore through which passes NH-47. In the open market, the agricultural land there sells one crore per acre but the Government while acquiring pays just one lakh per acre. So, farmers get 90 per cent loan when they handover their land for a public cause. So, I urge upon the Governments to take into consideration the plight of the farmers and enhance the compensation.

It is widely known that our Air India in the Civil Aviation sector is not having a competitive edge over the private air line operators. For instance, Air India operates a flight between Delhi and Coimbatore via Mumbai which takes 6 hours whereas private airlines like Spice Jet links Delhi with Coimbatore via Hyderabad taking just 3 hours and 45 minutes. The passengers are discouraged to go in for Air India. Conscious efforts must be made to change this trend. Air India must reschedule its flight timings and change the route as per the ground needs. This will help Air India which was operating till recently CRZ-7603 directly between Delhi and Coimbatore to make profits. Hence, I urge upon the Union Government and the Civil Aviation Ministry to operate an airbus between Delhi and Coimbatore. I also urge upon the Government to enquire into the

reported loss of about one lakh crores of rupees accrued to the Ministry of Information Technology in the allocation to 2G spectrum band width.

***श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़):** अनुदान की अनुपूरक मांगों पर चर्चा में कभी तो सदस्यों ने विकास एवं मुद्रास्फीति के प्रति चिंता व्यक्त की है। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी है किन्तु इस मत को नजर अंदाज कर दिया गया कि रुपये का अवमूल्यन हुआ है कोई भी चीज खरीदने के लिए बहुत अधिक रुपया देना पड़ रहा है। विकास के लिए हो रहे निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ गयी है। अतः कई योजनाओं के पुर्नमूल्यांकन न होने के कारण कई कार्य अधूरे पड़े हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ (म0प्र0) के अंतर्गत महत्वपूर्ण सिंचाई योजना के बेतवा नदी जोड़ने कार्य जो कि नदी जोड़ो अभियान के प्रथम फेस में स्वीकृत हुआ था अभी इसका कार्य पैसों के अभाव में रुका है जबकि इस योजना से छतरपुर, टीकमगढ़, सागर, विदिशा जिले एवं उत्तर प्रदेश के कई जिले लाभान्वित होंगे। अतः अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए प्राथमिकता से राशि का आवंटन होना चाहिए।

म0प्र0 बुन्देलखंड क्षेत्र से निकलने वाली ललितपुर सिंगरोली रेलवे लाईन का कार्य भी धीमी गति से चल रहा है। अतः इसे भी शीघ्र प्रारम्भ करने के लिए बजट का प्रावधान अनुपूरक बजट में करना चाहिए।

बुन्देलखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है अतः कृषि को बढ़ावा देने के लिए बुन्देलखंड में प्रस्तावित केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ छतरपुर में ही खोलने के लिए अनुपूरक मांग में शामिल करके प्रारम्भ किया जाना चाहिए। शिक्षा को बढ़ावा देने टीकमगढ़ में अभी केन्द्रीय विद्यालय ही नहीं हैं अतः इसे शीघ्र प्रारम्भ करना चाहिए। ताकि वहां के विद्यार्थियों को भी केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने का लाभ मिल सके।

* Speech was laid on the Table.

संसदीय विकास की राशि बहुत ही कम है जबकि अनेक राज्यों में विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए 1.5 करोड़ से 3 करोड़ तक की राशि मिल रही है। अतः संसद सदस्यों की कठिनाईयों को देखते हुए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए संसदीय क्षेत्र विकास राशि कम से कम दस करोड़ रुपये किया जाना चाहिए तथा केन्द्र द्वारा प्रवर्तित सभी योजनाओं की मानीटरिंग का कार्य भी सांसदों की समिति को दिया जाना चाहिए।

***श्री नारनभाई कछाड़िया (अमरेली):** माननीय मंत्री जी ने जो पूरक बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से एक बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में रखना चाहता हूँ।

हमारा देश आज भी कृषि और ऋषियों का देश माना जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि अगर सही भारत को देखना है तो गांव में जाकर देखो लेकिन आज हमारे देश के किसान और गांव, गरीब मजदूर भूखे हैं। उनके तन पर कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए मकान भी नहीं है और हमारे देश के किसान की बात कहूँ तो किसान जो हैं वह हमारे देश की गले की हड्डी की तरह है। अगर गले की हड्डी टूट जाती है तो आदमी जिंदा नहीं रहता। उसी तरह हमारे किसान टूट जायेंगे तो हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। आज अगर मैं जो बात कहूँ तो मैं भी एक किसान हूँ और हमारे सभी दल के सासंद किसी न किसी तरह खेत से जुड़े हुए हैं। अगर देश की उन्नति और हरियाली को आगे बढ़ाना है तो दृढ़ता के साथ हमें कार्य करना है।

आज किसान लुप्त होता जा रहा है। गांव का शहरीकरण होता जा रहा है। क्यों?

जब किसान खेत में बीज बोते हैं तभी से फसल का ध्यान रखने के लिए खेत में ही रहना पड़ता है। क्यों बोये हुए बीज को पशुओं के झुंड जमीन में से निकाल खा जाते हैं। जब फसल थोड़ी बड़ी होती है तब रोज जो एक जंगली पशु है वो खेत में पूरे झुंड में आते हैं और पूरी की पूरी फसल बरबाद कर देते हैं। आज किसान जो है वो अपनी जान से भी अधिक प्यार खेत को करता है। वह बस फिर गांव छोड़ कर शहर की ओर भागता है और जमीन खरीदने वाला कोई किसान नहीं होता। वह बिजनेस मैन होता है और वही जमीन पड़े-पड़े बंजर हो जाती है। अगर उसे रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में हमारे देश की खेती नष्ट हो जायेगी। इसलिए किसानों को उसकी फसल की रक्षा के लिए किसानों को सभ आवश्यक सुविधायें दी जानी चाहिए। वायर फेंसिंग तार सुविधा, जितना भी हो सके देना चाहिये। आज भी किसानों की वर्षों पुरानी फायर इंश्योरेंस की मांग कृषि विभाग और वन विभाग में पड़ी हुई है।

* Speech was laid on the Table.

किसानों को समय पर न तो अच्छा बीज मिलता है, न ही समय पर सारी दवायें मिलती हैं और न ही समय पर रासायन खाद मिलती है। समय जाने के बाद जो चीज मिलती है तो उसकी उपयोगिता नहीं रहती। अगर हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें हमारे देश के खेत और किसानों को मजबूत करना अति आवश्यक है। किसान मजबूत तो गांव मजबूत और गांव मजबूत तो हमारा देश अपने आप ही आगे बढ़ेगा। मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : We are discussing Supplementary Demands for Grants (General) 2010-11 in this House and I want to raise the following issues.

Firstly, in the agricultural sector, the farmers used to sow seeds, cultivate their own land and then sell their produce in the market. But now-a-days hybrid, genetically modified seeds and high yielding variety seeds are grown in the laboratories which are very expensive. Often Crops can not be grown from these seeds. As a result of which the quality of land suffers, farmers incur huge losses. In Maharashtra, one of the reasons of farmers' suicides is crop failure.

In my district, Patiram Agriculture Laboratory is functioning. I urge upon the minister to allocate adequate funds for the development of this laboratory.

Education : If we come to the education sector, the implementation of the Right to free and compulsory education has not started as yet. What is the reason for this? The Government must take initiative to begin the work right away.

After the 6th Pay Commission, only some people have received the revised salaries. But the teachers, professors of colleges and universities are still not getting the enhanced pay. They should be immediately paid salaries at the revised rate.

Law and Justice : There is also much confusion among various political parties regarding the Election Photo Identity cards. At times the foreign nationals are also given these cards and genuine citizens are deprived of the privilege. This issue must be seriously looked into.

Commonwealth Games : Everyday we find lots of news about the ensuing Commonwealth Games. In print media as well as in audio-visual media, news of corruption, irregularities and mis-appropriation of funds are

* English translation of the Speech laid on the Table originally in Bengali.

pouring in. The Stadia which are being constructed by CPWD are sub-standard – the tiles are breaking everyday. The Central Vigilance Commission has submitted a report in this regard which has pointed out to the corruption and mishandling of funds.

Airports : We all know that Mangalore, Leh, Patna airports are in a dangerous condition. Most of the airports are being handed over to the private players. I have also read in the newspapers that incidents of thefts are taking place there. Even the mobile phone of honourable MP Shri Rahul Gandhi was also stolen. In my constituency, there is an airport but it is not functional.

Chemicals : On 2nd of December in 1984, poisonous gas leaked from the factory of Union Carbide in Bhopal as a result of which 20,000 people died. Lakhs of people have become handicapped and have been incapacitated and can not work anymore. Mr. Anderson and Mahendra did not pay adequate compensation to the victims and fled. Most of the sufferers did not get even that meager compensation amount.

After 26 long years, the verdict of the case has been given and has ignited thousand minds giving rise to widespread repercussions among the people of this country thereby the Government now wants to give more compensation to the victims. But the actual culprits have been allowed to go scot free. They have not made to pay anything. Instead, the people of the country are paying from their taxes. The factory infact should be sold off to mobilise the compensation money.

Home Affairs : I would also like to mention that the enumerators of the census have not been paid properly. They should at once be paid their due in the interest of the huge project undertaken.

Rural Development : My constituency South Dinajpur is mostly inhabited by the tribal communities. In the tribal villages, infrastructure is not up to the mark and there is lack of metalled road connectivity. This is due to

sparse population in these areas. But the tribal people are not happy with this situation and there is much resentment among them. The parameter linked to population must be changed.

***श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर):** माननीया अध्यक्ष महोदया, सरकार द्वारा अनुपूरक मांगों का बजट लाया गया। इस बजट में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न मदों में मांगें गये धनराशि का ख्याल नहीं किया गया। यदि अनुपूरक बजट लाया गया तो अति महत्वपूर्ण मांगें छोड़ना नहीं चाहिए था। पूर्वांचल में गोरखपुर व बस्ती मंडल जैनिज इन्सेफिलाइटिस एक वर्ष पांच वर्ष के बच्चों के टिकाकरण हेतु 79.20 लाख वैक्सीन भारत सरकार से मांगी गई। 17 लाख डोज का आदेश किया गया। अभी तक 15 लाख डोज पहुंचा है। गोरखपुर मंडल में अतिमहत्वपूर्ण टीका जो भेजे गये, वह खराब थे। सरकार द्वारा दक्षता विकास मिशन युवाओं को रोजगार देने के लिए बनाई गई पूरे देश के लिए केवल 3 लाख लोगों को दक्ष बनाने का लक्ष्य किया गया। उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम हेतु सरकार की देय धनराशि 94 करोड़ की प्रतिपूर्ति अब तक नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ के नवीन भवन हेतु 50% धनराशि अब तक नहीं दी गई। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को पूर्व दशम छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार से कोई धनराशि नहीं मिली। भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 1993-94 से संचालित की जा रही है। जिसके लिए चार हजार छः सौ इक्कीस मदरसों हेतु 13.240,985 लाख उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित किये गये थे, जिसमें मात्र 856 मदरसों हेतु धनराशि उपलब्ध कराई गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए पूर्वदशम दशमोत्तर छात्र-छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु 50% की धनराशि, केन्द्र सरकार को देनी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 538.09 करोड़ की मांग की, मिला मात्र 55 करोड़। आखिर यह धनराशि क्यों नहीं दी गई। शीघ्र न्याय के क्षेत्र में 242 फास्ट कोर्ट के संचालन हेतु 43.610 करोड़ की धनराशि मांगी गई, लेकिन इसको नहीं दिया गया। प्रदेश के 12 जनपदों में 15 पारिवारिक न्यायालय कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय ने शेष सभी जनपदों में पारिवारिक न्यायालय खोलने का निर्देश दिया, जिसके लिए 19.32 करोड़ भारत सरकार से मांगे गये, अब तक नहीं मिले। उत्तर प्रदेश में हर एक ब्लॉक में तहसील स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के संचालन हेतु केन्द्र सरकार से धन मांगा गया, जो नहीं मिला।

अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम के संचालन हेतु 22.86 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी, नहीं दिया गया। सड़क, परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया। सी.आर.एफ. तथा इंटर स्टेट कनेक्टिविटी योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई धनराशि के प्रतिपूर्ति नहीं की गई। पूर्वांचल के जनपद बलिया, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, कुशीनगर, संत कबीर नगर, मउ गाजीपुर को बाढ़ व सूखा से निजात दिलाने के लिए कोई बजट नहीं दिया जा रहा

* Speech was laid on the Table

है। बाढ़ परियोजनाओं के निर्माण में प्रदेश सरकार के योजना के मुताबिक एआईबीपी योजना अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मानक से आधी धनराशि स्वीकृत की गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।

दलहन एवं तिलहन योजना के विकास हेतु योजना बनाई गई। फूटी कौड़ी नहीं दी गई। विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत (ऊर्जा) के आबंटन में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है। राजीव गांधी विद्युत हेतु उत्तर प्रदेश द्वारा 10.86 करोड़ की परियोजना भेजी गई, जिसका पैसा अब तक नहीं मिला।

***श्री गणेश सिंह (सतना):** महोदय, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर अपने विचार रखते हुए वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण विकास के लिए आपने 7337.50 करोड़ रुपए रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को पूरा करने हेतु राशि दिए जाने की मांग करता हूँ। मध्य प्रदेश के महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र में बांध की दायीं तरफ नहर, जो इसकी जीवन रेखा है, उसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने हेतु जल बोर्ड ने प्रस्ताव भेजा है, मैं इसकी मंजूरी की मांग करता हूँ। केंद्र सरकार कह रही है कि 20 किलोमीटर सड़क बना रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि सड़कें बड़े पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं और उसकी वसूली जनता की जेब से हो रही है।

मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का काम अच्छा चल रहा है। 15,000 किलोमीटर सड़कों के निर्माण हो रहा है। अक्टूबर, 2009 से आज तक एक रुपया भी नहीं दिया गया है। 7,000 गांवों के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे लेकिन बिना किसी कारण के वापिस कर दिया गए हैं। हर रोज प्रदीप जैन जी ग्रामीण विकास मंत्री, मध्य प्रदेश को खुले आम केंद्र की राशि बंद करने की बात सर्वत्र कह रहे हैं। क्या यह उचित है? केंद्र सरकार से राज्यों के लाभ के लिए विशेष पैकेज दिए जाते रहे हैं, हमारी इसमें कोई शिकायत नहीं है। परंतु राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने महाकौशल एवं विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु विशेष पैकेज की मांग की थी क्योंकि यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है।

*SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): Sir, I rise to support the Supplementary Demands for Grants that we are discussing today. I must mention that our country is passing through a critical juncture.

Sir, after the world wide economic melt down – we have the future that our country is affected very little.

Sir, the respectful Yashwant Sinhaji alleged that Mahatma Gandhi NREGA is full of corruption. Sir, Central Government is not implementing Mahatma Gandhi NREGA directly. Sir, Central Government is giving money as much as the State Government is demanding. Sir if there is any corrupt practices in NREGA who is responsible for that? No doubt the State Government. Sir, implementation-wise the Mahatma Gandhi NREGA is walking under the strict control of State Government officials. If there is any corruption, it is the duty of the State Governments to find out the solutions.

Sir what is the standard of MNREGA implementation in rural areas. Sir, in district level Joint Commissioner is there. Who is the sole controller. Sir, under his control Block level officer and below his Grampanchayat level officer, and technical experts like engineers and data entry operators and village estates Officer. Sir, below this Supervisory nature of 'mates' who is looking after the entire work which is done by the ordinary labourers who are entitled as jobseekers.

Respected Sinhaji, these are all officers who are State Government employees. Is there is full of corruption why not the State Governments take initiatives to stop the corruption. Respected Sinhaji tens and thousand of poor villages and the real downtrodden people are eagerly waiting for Mahatma Gandhi NREGA job. It is really a blessing for the Crores of people. In this occasion I would like to mention the initiative taken by our beloved leader Sonia Ji and Respected Prime Minister.

* Speech was laid on the Table.

Sir, in this supplementary demand for grants our government allotted a total amount of 68,294 crores. Sir out of this 25,981 is in plan outlay and 42,313 is nonplan.

Sir, to provide ex-gratia to victims of Bhopal gas leak disaster. Is there any reason to oppose this demand? Sir, may I know from our respected opposition members?

Sir, the RBI share holding in national Bank for agriculture and rural development and national housing bank. Sir, the total share is 1,900 crores. Is it a small thing sir?

Sir, I would like to give a special congratulation to our forward looking Finance Minister for providing 103 crore. On behalf of entire labour community, I congratulate the Finance Minister for providing loan to HMT Ltd. for redemption by Government guaranteed loan and interest Rs.103.98 crore.

Sir, our flagship programme Right to Education Act is one of the most important programme of our Government. Sir in this supplementary demands for grants 4,000 crores is provided for implementing Right to Education Act. Sir also 2,000 crores for the improvement in the pay scale of ministry and college teachers is also provided in this demand grants.

Sir 50 crores is allocated for skill training for youth of left wing extremism areas. Sir, allotment for elector's photo identity cards (EPIC) Rs 150 crores is a welcome step. Sir in our State Kerala some parts of Kannore districts and some other places the bogus identity card is utilizing with the convenience of CPI(M) led State Government. This amount will help to prevent bogus cards.

Sir in the field of rural developments 6,300 crores is allotted. In this 2,000 crores is also for left wing extremism affected districts is also notable one. Sir in this manner we can meet the challenges which our rural India is facing. Sir, with these words I would like to conclude my short speech.

***श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर (परभणी):** अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक मांगों में बोलने का समय दिया, आपका आभारी हूं।

पूरक मांगों पर चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण बातें रखता हूं।

देश की प्रगति के लिए मानव का विकास।

1. मानव का विकास
2. मानव की शिक्षा
3. कृषि विकास
4. ग्रामीण विकास
5. महिला की प्रगति
6. किसानों का इंश्योरेंस
7. रोजी, रोटी, कपड़ा, मकान, प्रथम सुविधा
8. मानव के आरोग्य की सुविधा
9. खेती के लिए जल प्रोजेक्ट होने चाहिए
10. आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा की सुविधा
11. एम.के.वी में फूड की सुविधा
12. जायकावादी बैंक केनाल को पूरा करें।

* Speech was laid on the Table

*SHRI P. KUMAR (TIRUCHIRAPPALLI): On behalf of the AIADMK I putforth my views on the discussion on “Supplementary Demands for Grants for the year 2010-2011.

Union Government has allot huge allocation of funds for centrally sponsored schemes which are to be implemented by the state. I have come to understand that there are two steering committees one headed by the Chief Minister of concerned states and the other at the central level to monitor the implementation programme. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, is one of the flagship programme of the center. Here I would like to bring to the notice of the government that the priority should be given to the local M.Ps in selection of work as per the norms fixed by the government. The implementing authorities are not following the rules prescribed by the Government in giving priority for supervision by the local M.P. or public representatives. The Government should come forward to issue directions to the representatives. The Government should come forward to issue directions to the implementing authorities to follows the rules and provide opportunities for supervision of local M.Ps.

Recently, the Hon’ble Minister of Urban Development orally told that the norms fixed for inclusion of cities under JNNURM will be relaxed. Under the proposed guidelines it was understood that those cities which are having 5 lakhs population will also enjoy the financial allocations under JNNURM. I request the Hon’ble Minister through this House to include Trichi and Salem cities of Tamil Nadu under JNNURM and to allocate funds accordingly in the present budget itself.

Then I am coming to the agricultural sector. The Government should take note of the present situation that the area of cultivable agricultural land are shrinking resulting low production of foodgrains. Due to the low production people are unable to get foodgrains on affordable prices. One side the Government

* Speech was laid on the Table.

is making laws to provide food security to all sections of our population and on the other side the cultivable lands area are coming down. There are two main reasons for this. One is conversion of agricultural land as housing plots and the other is agricultural lands are used for industrial purpose. One side the production of foodgrains are coming down on the other there is no sufficient godown for the storage of the agricultural produces. The Government should come forward to enact a suitable law in this house to ban the conversion of agricultural land for industrial and housing purposes. Then only we can save the cultivable agricultural land which provides foodgrains for the people. In my parliamentary constituency the districts of Trichirapalli and Pudukottai agriculturists are producing more quantity of Bananas, Jasmine and Cashewnuts. But due to marketing problem they are unable to get proper price for their produces. For this I suggest agricultural based industries like establishment of Central Banana Export Centre, Perfume manufacturing industries to extract from jasmine and Cashewnut export unit to enable the agriculturists to have remunerative prices.

Then coming to the road sector I request the Government that the ongoing expansion of NH 67 from Thanjavur to Karur via Trichirapalli may be expedited at the earliest by allocating sufficient funds. There is a long pending demand from the people of Tamil Nadu for conversion of State Highways No.28 from Thanjavur to Sayalkudi. No.25 connecting Trichirapalli and Namakkal into National highways. I request the government to make budgetary provisions for the road project in the ongoing budget itself.

***श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर):** मैं अनुदान की पूरक मांगों (2010-11) पर अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। देश में कृषि तथा उस पर निर्भर किसानों की समस्या पर अनेक सहयोगी सांसद बोल चुके हैं। मैं सुझाव दूंगा देश में हर किसान को अपनी कृषि भूमि का विकास करने की जिम्मेदारी उस किसान से जादा सरकार की मानी जानी चाहिए। सरकार जिस किसान से अपनी कृषि कार्य हेतु सिंचाई हेतु, ट्यूब वेल, बोअरवेल या कुआँ मांगा उसे सरकार पूर्णतः राजसहायता प्रदान कर उस किसान को सिंचाई हेतु जिम्मेवारी ले। देश में अनाज की कमी को यही किसान परिश्रम कर अनाज की कमी पूरी कर सकता है। हमें आयात अनाज पर भारी संख्या में करेन्सी देनी पड़ती है उसे हम बचा सकते हैं।

देश में भारी संख्या में युवा बेरोजगार है। 20 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार रोजगार-नौकरी चाहते हैं। लेकिन सरकार-सरकारी क्षेत्रों व सरकारी नौकरियाँ निकाल नहीं रही है। अनेक पदों को खाली रखा जा रहा है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी से वंचित रखना उचित नहीं। खाली पदों को तुरन्त भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु आदेश दें।

सरकार हर बार कामगार संगठनों कर्मचारी संगठनों के दबाव में वेतन आयोग-पे कमीशन की स्थापना कर उन वेतनभोगियों को बार-बार वेतन बढ़ाने हेतु सहमति देती है। लेकिन बेरोजगारों हेतु बेरोजगार भत्ता देने हेतु आयोग बैठाये तथा बेरोजगारों को भत्ता प्रारंभ करें।

MR. CHAIRMAN : The Deputy-Speaker has already announced that at 6 O' Clock we would be taking up the 'Zero Hour'. Therefore, now I call the hon. Minister to reply.

... (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY (KOKRAJHAR): What about me? I have already given the notice.

MR. CHAIRMAN: We would call you next time. At 6 O' Clock, we are going to take up other business. Before that, we have to pass it.

... (Interruptions)

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : My party is a recognized party. I may be allowed. ... (Interruptions)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

SHRI SANSUMA KHUNGGUR BWISWMUTHIARY : This is not a justice. Why should I not be allowed? ... (Interruptions)

17.37 hrs

At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwisumuthiary came and stood on the floor near the Table

17.37 ¼ hrs

At this stage, Shri Sansuma Khunggur Bwisumuthiary went back to his seat

17.37 ½ hrs

At this stage, Shri Prasanta Kumar Majumdar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

MR. CHAIRMAN: Time is over. It is not like that. Those who have not spoken, they can lay their speeches on the Table of the House.

... (Interruptions)

17.38 hrs

At this stage, Shri Prasanta Kumar Majumdar and some other hon. Members went back to their seats

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Mr. Chairman, Sir, I thank the hon. Members for their observations which they have made. Some of the hon. Members have also stated that they could have said, but because of the paucity of time, they were not provided the opportunity. But those who have also given their speeches in writing, we will take note of it.

I am happy that Shri Yashwant Sinha has participated, who, naturally as a former Finance Minister of a very long standing, could make points relevant and also he has highlighted some of the issues and expressed his concern. And it is quite natural for him to say that some of the expenditure proposals which I have brought in the first Supplementary Demand, keeping in view the nature of their expenditure, could have been anticipated and incorporated in the main Budget. There is no denial to the fact that some of these could have been anticipated. But why I have come out with it. Normally, the Finance Ministers do not come out in the first Supplementary Demand, which is almost five per cent of the total budgetary expenditure and not a substantial part of the GDP in terms of percentage.

This time I wanted to make an experiment. He had this experience and I also had this experience that when we give the money required to the States, one complaint that constantly comes is that much of the working season is lost. That is because we finalise the entire budgetary exercise by middle of May when the Finance Bill is passed. After that, by the time communications and other things are issued, the Monsoon Session starts. As a result of that, if there is a shortfall or an anticipated shortfall, when the additonality is being given to them by the end of Winter Session through the second batch of Supplementary Demands, much of the working season is lost. I wanted to address this.

I would give you one instance as we do not have adequate time. I have given Rs.7,000 crore for the Pradhan Mantri Gramin Sadak Yojana. I entirely agree with Mr. Sinha that this could have been anticipated and incorporated in the Budget. But apart from that I am doing it with the idea that if they can use this now, they will get a larger period of working season. I could have brought it down

on some other items also but that would have created problems in respect of the actual effective implementation. That is because much of the working season would have been lost. I am doing this experiment for the first time. If I find that it has worked, I may repeat it. Otherwise, I will go back to the normal practice, which he followed and which I followed, and will come out with bulk expenditure in the Winter Session. This is one clarification I thought I should give to the hon. Member who initiated the discussion.

There is another point which he perhaps might have missed because I did not elaborate it. I never said that it is only because of the growth that there is this inflationary pressure; that as long as there will be growth, inflationary pressure would be there; and that there is no need of containing the inflation. The short point which I tried to drive at, and I believe as the Finance Minister he should have also done it, is that when we are having a growth regime of nine per cent – that was the scenario from 2005-06, 2006-07, and first part of 2007-08. When I presented my interim budget I mentioned it in February 2009 that in the last quarter of the 2008-09 the GDP growth has come down to 5.8 per cent. In the first quarter it was 7.8 per cent and it came down to 5.8 per cent in the last quarter. My anxiety was - you may disagree with it, anybody may disagree with it - how to decelerate it. That is why I took a tremendous risk. I must say it is a tremendous risk that I allowed the fiscal expansion. Substantial fiscal expansion took place. In absolute terms, Rs.1,86,000 crore were injected either by stepping up the developmental expenditure or by reducing excise duties from 16 per cent to 8 per cent and by taking certain other measures. So, in absolute terms it was Rs.1,86,000 crore and in terms of GDP it was almost three per cent of GDP at the current prices at that time.

Therefore, this fiscal expansion had its impact on the inflationary pressure which was coupled with the shortfall of the monsoon. There was an actual shortfall of about 15 million tonnes of food grains. The adverse impact was

delayed a little because in the first quarter of 2008, in the entire world there was a commodity crisis and energy crisis in terms of rising prices.

Therefore, these things added to inflation. This is the cause and this cause had its effect. That does not mean that the effect will not have to be addressed. Therefore, both these aspects – from demand side and supply side – are there. So far as supply side is concerned, I have elaborated in details. That is what we have done. What is likely to be done and what we should try to do more. There, I sought the cooperation of all the political parties because he has responded. I am happy that he has responded to my request yesterday about the GST. I entirely agree with you without taking the States on board, how can I have the GST? Without Prince of Denmark, I cannot stage Hamlet. They are the Prince of Denmark. They are the main actors. What I appeal to you that the Central leadership should have discussions with them and if we can find a viewpoint of convergence. I have no intention of becoming the Super Finance Minister to interfere with the State GST. They will have their rights as I shall have my right because I am accountable to you. No tax can be levied without your approval; no expenditure can be made without your approval. Similarly, they have accountability to their States. That basic structure cannot be altered. So, what we can do for the practical purpose? I quoted your manifesto not for scoring a brownie point but only to say that I entirely agree with it that it should be desirable if it is around 12 to 14 per cent. It would be desirable if I can completely abolish the Central Sales Tax. But I cannot do it alone. That can be done collectively by all the political parties who are running the State Governments who have representation in both the Houses of Parliament. The short point which I was trying to drive at, if we can do right now because in the remaining three-four weeks, if I can place the Constitution (Amendment) Bill for the consideration of this House, then, it can be sent to the Standing Committee; after scrutiny by the Standing Committee, in the Winter Session we can discuss. And then, it may be possible to have it.

About the rate of taxes, in respect of the convergence of the other areas, that with the Empowered Committee of the State Finance Ministers, I am engaged with them. That is a good institution you have established. I congratulate you and I appreciate it. I am using it. It is not that I have abandoned it. I am waiting for their Report and their comments on the Draft Constitution Amendment, which I have given to them. After that, I will circulate to the political parties for their comments because here I would require their support. But, I am waiting to have their views first.

Yesterday, the Empowered Committee met. Tomorrow, the Chairman of the Empowered Committee would brief me as to what transpired there. Thereafter, I will have meeting with them, sometime later. But before that, if you can exercise your influence as a national leader, it would be beneficial to us.

Mr. Chairman, Sir, as I have stated, mainly if you analyse, the substantial part of this Supplementary Demand, if we can broadly categorise, there are certain items which are relating to the social sector. Social sectors have substantial amount about – Rs.12,500 crore. Of that, Rs.4000 crore is for the Right to Education Bill that has been passed by this Parliament. Now, the States say, we cannot bear the entire expenditure. We calculated for the remaining part of the 11th Plan. The total allocation of the 12th Plan, I cannot forecast. That is the Planning Commission's job. They will be doing it, of course, in consultation with the Finance Minister. But anticipating as to what would be the cost of the remaining period of the 11th Plan and the spill over period of one or two years of the 12th Plan, we calculated that it would be around Rs.2,31,000 crore for the next two or three years.



Of that, Rs.60,000 crore we shall have to give to the SSA and some other amount to Right to Education. We thought that it would be difficult for the States to maintain two parallel streams; therefore, it was suggested that we should have the same sharing formula of 65 per cent from the Centre and 35 per cent from the States. So, for that, I have provided this amount.

I have to give Rs.14,000 crore to the oil marketing companies because there is no way out. Whatever I have done so far, still it is not possible for them to meet their requirements.

I have also mentioned about the PMGSY. On security related expenditures, I agree with the comments – it must have its improvement and its effect in all the districts which are highly affected and highly sensitive. The proposal which the Home Minister is thinking of will come later on, and I have agreed to that. One of the major components is to have 400 police stations with a minimum of 40 police personnel in each because what we have seen from our experience is that in some of the areas, police stations have been occupied by the Maoists; thereafter, when the CRPF and others were sent for the joint operations, their first task was to recover and restore the police stations and place them in the hands of the local police, and thereafter, to work on it. So, the suggestions in respect of the security related matters have come, but so far as this is concerned, mainly it is for meeting the expenditure requirements of the new raisings, including the acquisition of lands in Jammu & Kashmir in the eastern sector, for meeting the additional expenditure of the CRPF, some of the other security expenditures amounting to Rs.980 crore for J.& K. and also the left wing extremist affected districts. Some of the others are for the capital expenditure requirements of the police.

Assistance to the States, as I mentioned, Special Plan Assistance and Special Central Plan Assistance to Jammu & Kashmir, has to be given, amounting to Rs. 3279 crore, which is absolutely necessary. We are giving to Special Category States, an amount of Rs.1,000 crore. ... (*Interruptions*) Please do not

disturb. Time is running out. At 6 o'clock, the House shall have to take up 'Zero Hour'. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : He will answer later on. Let him complete; after that, you can raise the matter. Please take your seats.

... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: For the hon. lady Member from Punjab, I can assure her that I have already taken care of the Special Debt problem of Punjab, after consultation with the Chief Minister of the State and the Finance Minister. But I appeal to others not to bring everything saying that special package will have to be provided to them. Otherwise, I will become bankrupt! ... (*Interruptions*)

So, the total assistance to the States is Rs.7279 crore. ... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats. Let him complete; at the end, you can raise them.

... (*Interruptions*)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: This is no way! It is Supplementary Demand. You will get enough opportunity of discussing this, in a substantive manner and in a substantive way. If you want to raise it in a substantive form, we will be prepared to discuss it, not like 'off the cuff' remark'. Let us discuss substantively about the state of the economy. ... (*Interruptions*) About MPLAD, I will come later on. Why are you so-impatient? Should we always speak for ourselves? I will come to that later on. I have noted this suggestion. I have also noted another suggestion, apart from MPLAD, I am much more concerned, which is the point which Shri Yashwant Sinha stated; it has some relevance.

I cannot just say that I am going to do it from tomorrow. He has particularly referred to a State saying that for umpteen number of years there is not even a local body. If the entire people's representation and activity is confined only to some limited number of MLAs; and MPs have no role in the local developmental work, it then creates really an awkward situation.



The second aspect is, with the growing expansion of the rural developmental activity, if I feel that MPs can be involved and if they are not merely scrutinising a few schemes under the Rural Development Ministry, NREGA or one or two other such schemes but the entire spectrum of the rural development, the MPs can be fully involved. It is not that they would like to have the executive body. But surely their consultations, their views can be taken into account. Many of them are experienced Ministers and administrators, like Shri Yashwant Sinha, and all of them have the credentials. Nobody can come here and sit simply because this is a good hall and they have a desire to come and sit. It is not that. About 1.5 million people are to elect you and then and then only you can come here. Therefore, with due respect to all the Civil Servants who are coming by passing through a competitive examination, let us not have this feeling that they are superior intellectually or otherwise and we are less than them. It is not that.

My point is I am just a Finance Minister. I shall have to take it up with the Cabinet, with the Prime Minister because this is one of the major administrative reforms. I personally feel and I will convey it to the Prime Minister that we must find out a mechanism through which we can effectively resolve it.

So far as MPs demand with regard to MPLAD Fund is concerned, I have asked my colleagues to get some figures. I think Shri Yashwant Sinha has stated that some States are getting just Rs.2 crore or 3 crore per MLA but there are some States where it is only a few lakh.... (*Interruptions*) I know it. In Some States they get only Rs.20 lakh or Rs.25 lakh. I will consider this aspect. I am trying to get some figures from the State Governments.

You have rationed the time of every speaker, as Minister I do not want to take extra advantage. I have covered some of the salient features and the other important issues which the hon. Members have raised, in course of discussions on various issues we will have the opportunity of sharing our common perception.

Thank you, Mr. Chairman, Sir.

MR. CHAIRMAN : I shall now put cut motion Nos. 1 and 2, moved by Shri Prasanta Kumar Majumdar, to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the Supplementary Demands for Grants (General) for 2010-2011 to the vote of the House:

The question is:

“That the respective supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President of India, out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2011, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 4, 6 to 9, 11 to 20, 22, 27, 29 to 33, 35, 41, 46, 49, 51 to 54, 56 to 60, 62, 72 to 74, 81, 84, 87, 88, 90, 92 to 96, 100, 101 and 103 to 105.”

The motion was adopted.



18.00 hrs.

APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 2010*

MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up Item Nos.17 and 18 together.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): I beg to move for leave to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2010-11.

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2010-11.”

The motion was adopted.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I introduce** the Bill.

MR. CHAIRMAN: The Minister may now move that the Bill be taken into consideration.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move**:

“That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2010-11, be taken into consideration.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the Financial year 2010-11, be taken into consideration.”

The motion was adopted.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 2, dated 5.8.2010.

** Introduced and moved with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is:

“That clauses 2 and 3 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the long Title were added to the Bill.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I beg to move:

“That the Bill be passed.”

MR. CHAIRMAN: The question is:

“That the Bill be passed.”

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The time of the House is extended till the ‘Zero Hour’ is over.

I hope the House agrees with it.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

SHRI R. DHIRUVANARAYANA (CHAMRAJANAGAR): Sir, I would like to draw the attention of the House to a long pending issue of identifying the State boundary between Karnataka and Tamil Nadu at Hogenakkal Falls in my Constituency.

The Hogenakkal Falls is a tourist destination and it comes under my Constituency. In this connection, 16 hon. Members of Parliament from Karnataka met the hon. Prime Minister and requested him to solve this boundary dispute.

18.04 hrs

(Shri Inder Singh Namdhari *in the Chair*)

The boundary dispute has to be taken up by the Archaeological Survey of India. In the meanwhile, the Government of Tamil Nadu has taken up Hogenakkal Drinking Water Project in the disputed area. They are violating the Cauvery Tribunal Rules.

So, I urge upon the Union Government to withdraw its permission given for the on-going Hogenakkal Drinking Water Project because it comes under the disputed area. I also urge the Union Government to conduct survey immediately to resolve the problem between Karnataka and Tamil Nadu.

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, रेलवे मंत्रालय द्वारा हमारे क्षेत्र की जो उपेक्षा हो रही है, उसे मैं बहुत ही दुखी मन से बता रही हूँ। मैं केवल उपेक्षा की बात नहीं कहती, थोड़े क्षुब्ध मन से भी कह रही हूँ कि अगर हम कोई मांग करते हैं तो यह जवाब मिलता है कि इस रेल लाइन पर क्षमता नहीं है और कुछ ही दिनों बाद वहाँ दूसरी गाड़ी इंट्रोड्यूस होती है। मैंने मांग की थी कि इंदौर-बंगलौर के मध्य हैदराबाद होते हुए सीधी यात्री सेवा आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ गेज कन्वर्जन के कारण जो काचीगुड़ा ट्रेन चलती थी, वह बंद हो गई थी। मुझे उस समय बताया गया कि इस लाइन पर क्षमता का अभाव है। कुछ ही दिनों में वहाँ अजमेर से रतलाम, उज्जैन, भोपाल होते हुए हैदराबाद के लिए गाड़ी इंट्रोड्यूस की गई। मैंने इसी प्रकार दूसरी मांग रखी थी, क्योंकि गेज कन्वर्जन के कारण हमारे इंदौर-अजमेर के बीच जो लिंक था, वहाँ से सात जोड़ी गाड़ियाँ चलती थीं। वह सातों जोड़ी गाड़ियाँ एक प्रकार से गेज कन्वर्जन के कारण बंद हो गईं। जब मैंने वह मांग की तो मुझे बताया गया कि रतलाम में नागदा होकर अजमेर की ओर अगर हम गाड़ी भेजना चाहें तो वहाँ मेन लाइन का यातायात रोकना पड़ेगा। उसके लिए क्षमता का अभाव और कुछ टेक्नीकल कारण बताए गए। कुछ ही दिनों बाद तुरंत अजमेर से रतलाम, नागदा होते हुए हैदराबाद और

कोलकाता के लिए गाड़ियां चलाई जाती हैं। बार-बार यही होता है। हमें कहा गया कि वहां के लिए इंदौर-मुम्बई दुरंतो एक्सप्रेस दी गई, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं की गई। उस समय कहा गया था कि यह द्रुतगति रहेगी, कम स्टेशनों पर रुकेगी। अब मालूम नहीं द्रुतगति रहेगी या नहीं, मगर अभी तक उसे शुरू करने का कोई नामो-निशान भी नहीं है।

आज इंदौर इंडस्ट्रियल सिटी है। मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण शहर है। मगर उज्जैन से इंदौर 60 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन गत चार सालों से हो रहा है। केवल 500 मीटर के इलेक्ट्रिफिकेशन में कुछ न कुछ कारण बताते हुए एक साल लग रहा है। विकास के काम रेलवे नहीं कर रही है और न ही गाड़ियां मिल रही हैं। मैं अब हसूं या रोऊं, मुझे समझ में नहीं आता। मैंने रेल मंत्री जी को पत्र लिखकर मांग की थी कि इंदौर-बंगलौर गाड़ी चलाइए, इंदौर-पुणे गाड़ी को शोलापुर तक तक चलाइए या उसकी गति बढ़ाइए। मुझे उसका जो उत्तर आया, एक प्रकार से विनोद हो गया, मजाक की बात हो गई यह उत्तर आया कि आपके पत्र मिल गए और आपको प्रसन्नता होगी कि हमने जबलपुर-भोपाल एक्सप्रेस को इंदौर तक बढ़ा दिया। रेलवे मंत्रालय इस प्रकार का मजाक कर रहा है। इंदौर की उपेक्षा सतत रूप से हो रही है। इस कारण इंदौर की जनता आज नहीं तो कल आंदोलन करेगी। वहां लोगों में बहुत उग्रता आ रही है। मेरा आपके द्वारा रेल मंत्रालय से निवेदन है कि कृपया करके इंदौर की मांगों पर तुरंत गति से ध्यान दिया जाए।

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): Sir, the Government of Kerala had submitted a proposal for establishing a Regional Institute of Paramedical Sciences at Kozhikode with a central assistance of Rs. 90 crore in 2007 for inclusion in the 11th Plan.

It is expected that the Institute will cater to about 20 para-medical courses annually. The State Government has also assured sufficient land within the premises of the Medical College at Kozhikode for establishment of the Institute.

The Ministry of Health had also conveyed to the Government of Kerala that the proposal for Kozhikode is under active consideration through its letter dated 17.2.2010. But the formal order for the establishment of the Institute at Kozhikode is still awaited.

As you are aware, Kerala is the foremost State that sends nurses and other para-medical staff to numerous hospitals across the country as well as internationally. Therefore, the establishment of such an institution early, as

suggested, would help the aspiring candidates of Kerala who are otherwise now compelled to attend the courses in other parts of the country.

MR. CHAIRMAN : I would request the hon. Members not to leave the House as soon as they have completed their Zero Hour mentions as it does not look beautiful to do so.

*SHRI P.K.BIJU (ALATHUR) : Chairman Sir, Malayalam is the mother tongue, of all Keralites who are spread cross the world; and it is also the official language of Kerala, Lakshadeep and Mali. But Malayalam too is facing challenges that are retarding its growth.

Malayalam is the mother tongue of 3.5 crores of people'; and it takes the 27th place in the list of world languages spoken by the largest number of people. This means more people speak Malayalam than Greek or the Swiss language.

Kerala became the first Indian state to attain 100% literacy, and this was achieved in Malayalam language.

The *Vashappalli* inscriptions dating back to A.D. 830, shows the antiquity of the Malayalam script.

Linguists like Herman Gundert, says that Malayalam and Tamil both evolved out of the *Adi Dravida* language.

It is also note worthy that Malayalam is the mother tongue of all the people of Kerala, cutting across cast or religious barriers.

Thereby, it fosters the secular traditions of this country.

For centuries Malayalam was the language of administration in Kerala. Even during the days of British Colonialism, the language of administration was Malayalam.

After independence from 1969 onwards, the Government too recognized Malayalam as the language of administration in the state.

* English translation of the Speech originally delivered in Malayalam.

Tamil and Sanskrit language influenced Malayalam the most. Malayalam has not only words from rest of the Indian languages but it has also assimilated words from other world languages.

The sea trade Kerala carried on with the rest of the world, has helped our language to evolve.

Hindi, Arabic, Urdu and European languages and Chinese have enriched the vocabulary of Malayalam. Lakhs of books in different genres like stories, poetry, novel, academic studies are published in Malayalam. The language has produced world renowned literary figures too. Malayalam, is the first regional Indian language in which a translation of Artha Sastra was published.

The original text of Artha Sastra was recreated with the help of this Malayalam translation, that came out in 12th century by the name *Bhasa Kautilyam*.

Vedas and epics, had their translations in Malayalam many centuries ago.

Malayalam publishes the maximum number of translations among all Indian languages. The scientific and technological development and the sentiments of nationalism have influenced the growth of Malayalam language. Herman Gundert the clergyman published the first Malayalam dictionary and a work on Malayalam grammar. This was followed by several other works on linguistics, which were published at the second half of the 19th century.

Malayalam has several newspapers and journals. Next to Hindi a Malayalam newspaper has the maximum numbers of readers. Malayalam Wikipedia ranks 5th in the world in terms of page depth; and it has the top most rank among Indian languages.

But it is regrettable that centre has not given enough encouragement to Malayalam language, which figures among the 22 official languages mentioned in the 8th schedule. Several centrally sponsored schemes have not included Malayalam among the languages that are to be benefited.

The latest instance is the omission of Malayalam from the Central Government language development programme. Though the other three Dravidian languages,

namely Tamil, Telugu and Kannada are being included in the centre's language development programme, Malayalam has been neglected.

Several other programmes and policies that were meant to promote Malayalam language and culture are now inactive, due to the luke warm approach of Government institutions, and other state universities.

Chairman Sir, the Malayalam department, which was part of Modern Indian languages department in the Delhi University; is not functioning for the last few years. I urge the Government to confer classical language status to Malayalam and include Malayalam as part of the Central Government Language Development Programme; and further make Malayalam a part of the Department of Modern Indian Language studies in all central universities.

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश में पायलट की ट्रेनिंग पूरी कर चुके बेरोजगार पायलटों की व्यथा ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो 30 से 40 लाख रुपए पायलट की ट्रेनिंग के लिए खर्च करता है जिसमें उसके माता-पिता का घर, खेत, दुकान आदि गिरवी हो जाते हैं, तब जाकर वह पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। परन्तु उसे देश में ही रोजगार का अवसर नहीं मिल पाता है। आज हमारे देश में लगभग 5000 बेरोजगार पायलट हैं तथा 1000 पायलट हर वर्ष बेरोजगार हो रहे हैं।

इस समस्या के निवारण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? जबकि काफी संख्या में विदेशी पायलट आज हमारे यहां काम कर रहे हैं। यदि उनके अनुबंध समाप्त कर दिए जाएं तो हमारे नौजवान पायलटों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकता है। नौजवान पायलटों को रोजगार प्रदान करने के लिए पायलट की सेवा निवृत्ति की आयु भी 65 से घटा कर 60 वर्ष की जा सकती है।



विमान चालकों की भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा सकती है, ताकि इनकी नियुक्ति पारदर्शिता के साथ हो सके। भारतीय कमर्शियल पायलट लाइसेंस का अथवा बीएससी एविएशन डिग्री का प्रावधान किया जाना चाहिए। जब तक विमान सेवाओं में बूम न आए तब तक जैसा कि सरकार ने वर्ष 1973, 1975 एवम् 1979 में इन पायलटों को लगाया था, उसी प्रकार इन बेरोजगार पायलटों को इंडियन एयरलाइंस एवम् एयर इंडिया में फ्लाइट ऑपरेटर, फ्लाइट डिस्पैचर,

ऑपरेशन मैनेजर के पदों पर लगाया जा सकता है। इन्हें डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जैसे विभागों में भी अधिकारी लगाया जा सकता है। ऐसे भी सुझाव हैं कि इन पायलटों को वायुसेना में यातायात पायलट, तटीय गार्ड में पायलट, सभी निजी एयर लाइंस में फ्लाइट डिसपैचर एवम् ऑपरेशन मैनेजर लगाया जा सकता है।

मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इन बेरोजगार युवा पायलटों को शीघ्र रोजगार प्रदान किया जाए।

MR. CHAIRMAN : I would request the Members not to leave the House immediately after they make their remarks.

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई सांसद बाढ़ के विषय में पहली बार बोला हो। इससे पहले भी बिहार समेत देश के विभिन्न राज्यों के सांसद इस गम्भीर मुद्दे पर बाढ़ से बचाव हेतु कई बार संसद के पटल पर बोल चुके हैं। लेकिन आज तक केन्द्रीय सरकार इस गम्भीर विषय पर कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाई है। जिस कारण आज लाखों लोग बाढ़ की विभीषिका में जीते और मरते हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में 17 जुलाई को भीषण बाढ़ आई थी। ऐसी बाढ़ पहले 1987 में आई थी। नेपाल में लगातर बारिश की वजह से वहां से आने वाली कोसी नदी का कुसा बांध टूटने से अररिया, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तो बर्बाद ही हो गए। आपने पहले भी इस तरह की बात सुनी होगी। अररिया में कुरसाकाटा, नरपतगंज, सिक्टी का इलाका, बकरा नदी, परवान नदी और कनकई नदी, सुरसर नदी में इतना पानी आया कि वहां के इलाके की पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसान धान की फसल रोप चुका था, लेकिन इस बाढ़ से वहां के किसान की कमर टूट गई है और अब वह दोबारा वह फसल रोपने के लायक नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसके लिए कोई ठोस रणनीति बनाए। नदियों के तटबंधों का प्रावधान करे, ताकि बाढ़ से बचाव के लिए इलाके में किसानों की फसल बचे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पुल आदि बने हैं, वे भी डैमेज हो गए हैं। कई सड़कें तो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी थीं। हम लोग पांच साल विकास का काम करते हैं, लेकिन एक दिन जो बाढ़ आती है वह पूरा विकास का काम अपने साथ बहा ले जाती है और वहां तबाही मचा जाती है। इसलिए बकरा नदी से जो कि पहाड़ी नदी है, यह और दूसरी जो कोसी की सहायक नदियां हैं, उनमें इतना पानी आता है कि अचानक घरों में पानी घुस जाता है। इससे किसान

रोता है, खाने के लिए मरता है। मैं केन्द्रीय सरकार से कहूंगा कि एक केन्द्रीय समिति बनाई जाए जो इसकी जांच करे। बाढ़ से बचाव के लिए वहां बाढ़ सुरक्षा बांध बनाए जाएं। इसके अलावा केन्द्र सरकार बिहार सरकार को एक पैकेज दे ताकि बाढ़ और सुखाड़ से वहां की जनता को राहत मिल सके।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदय, मैं नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। 1915-16 से लेकर लगभग 20 वर्ष तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहां खुदाई कराई है। इतने लम्बे काल में इस विभाग ने जो विशद खनन, स्मारकों का संरक्षण और पुरानी वस्तुओं का संग्रह किया, इससे नालन्दा की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई है। यह अलेक्जेंडर कर्निघम ही थे, जिन्होंने संसार के पुरातत्वज्ञों का ध्यान इस स्थान के महत्व की तरफ केंद्रित किया। नालन्दा में पिछले तीन वर्षों में जुआफरडीह, बेगमपुर, दामनखंडा, घोड़ा कटोरा का उत्खनन शाखा टीम, पटना के द्वारा किया गया, जिसमें उत्खनन के पश्चात चौथी शताब्दी का बना हुआ प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय पहले की पुरातत्विक साक्ष्यों की कड़ी जोड़ने का काम जुआफरडीह ने किया है, जिसकी वैज्ञानिक तिथि 1200 से 1300 बीसी के बीच आई है और घोड़ा कटोरा के उत्खनन में ताम्र पाषाणिक संस्कृति से ले कर पाल काल तक के रहने के निरन्तर साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय की अंशतः उत्खनन होने से हमारे इतिहास और संस्कृति की पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिली है।

ऐतिहासिक दस्तावेजों और चीनी यात्रियों फाहियान और ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तान्त से जो साक्ष्य मिले हैं, उनकी पुष्टि आधे अधूरे उत्खनन कार्य को पूरा करके ही मिलेगी।

मैं इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार से यह मांग करता हूं कि नालन्दा विश्वविद्यालय एवं इसके साथ-साथ 10 उत्खनन स्थलों, जिसमें बेसमक और तेलहाड़ा शामिल है, वे भी नालन्दा विश्वविद्यालय के इतिहास को ही दोहराएंगे। इसका जो उत्खनन शेष है, उसे यथाशीघ्र कराया जाए।

SHRI RAJIAH SIRICILLA (WARANGAL): Mr. Chairman Sir thank you very much for giving me the opportunity.

Today, I rise to inform this august House regarding the injustice done in the appointment of higher judiciary. In higher judiciary appointments, collegium system is being followed in which there is Chief Justice of India with two other Judges. They only sponsor the candidates of their own choices thereby the Government has a very little role. As per Article 124(2), consultation is to be taken and not the consent. But contrary to this, the Supreme Court has given some judgment. According to that, the Committee is taking care of that and no SCs, STs

and OBCs are being appointed as senior judiciary officers throughout the country and that is the case in Andhra Pradesh also, particularly in the Telengana region.

... (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Judicial amendment is in the pipeline.

SHRI RAJAIAH SIRICILLA: I know that. I know that some Commission is being constituted. So, my request is that in the National Commission, which is going to come up, please keep some provision to nominate members from the SC, ST and OBC communities so that their interests can be safeguarded.

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : Sir, please allow me to associate with him.

MR. CHAIRMAN: Yes.

Shri G.V. Harsha Kumar – not present.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदय, मैं एक विशेष बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और सभी राष्ट्रीय टीवी चैनल्स में इसे दिखाया गया है और सीवीसी इसकी इन्क्वायरी कर रही है तथा सीबीआई से इस बात की इन्क्वायरी करने के लिए दिल्ली की सड़कों पर जुलूस निकल चुका है। लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्र मंडल खेल होने जा रहे हैं और इसमें पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है।

देश के कुछ मुट्ठी भर लोग गिरोह बनाकर लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। देश के राष्ट्रीय समाचार पत्रों और टीवी में इस बात को दिखाया जा रहा है इसलिए मैं मांग करता हूँ कि सदन में इस बात पर चर्चा हो। सीबीआई इन्क्वायरी करे, सदन की समिति इन्क्वायरी करे, संयुक्त समिति इन्क्वायरी करे क्योंकि देश के नाम पर दुनिया में कलंक का टीका लगाया जा रहा है। दुनिया के अच्छे खिलाड़ी इन खेलों में आने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं लगता कि स्टेडियम सुरक्षित रहेगा। जिस दिन उद्घाटन हुआ उसी दिन ऊपर से पानी टपकने लगा। पैसा लुट रहा है, बह रहा है और देश के नाम पर कलंक का टीका लग रहा है। इस बात की इन्क्वायरी हो, संयुक्त संसदीय समिति इन्क्वायरी करे, मामला सामने आए ताकि लूटने वालों को गिरफ्तार किया जाए, जेल में बंद किया जाए जिससे देश की इज्जत बच सके।

श्री यशवंत लागुरी : महोदय, मैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित विषय कार्यवाही में शामिल करने की मांग करता हूँ। आदिवासी क्षेत्र में जब कोई उद्योग लगता है या खनन के लिए अनुमति की जरूरत होती है, इसके लिए व्यवस्था बनी हुई है कि स्थानीय लोगों की राय शामिल की जाती है। इसमें व्यवस्था है कि जहां

उद्योग लगेंगे, उनमें जो भी गांव आएंगे, वहां के लोगों की ग्राम सभा के माध्यम से राय ली जाएगी। लेकिन यह इस ढंग से कराया जाता है जिससे प्रतीत होता है कि इसकी कोई इम्पॉर्टेंस नहीं है। यह सच है कि उद्योगपति, खनन करने वाले मालिक निश्चय ही आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं। आदिवासी लोगों से पूछा जाता है कि इनको उद्योग लगाने दिया जाए या नहीं। इसमें एक डेट फिक्स की जाती है और गांव के लोगों को बुलाया जाता है और सामने पूछकर मत व्यक्त करने की व्यवस्था की जाती है। इसमें जो उद्योगपतियों का विरोध करता है वह प्रक्रिया खत्म होने के बाद उनके रोषका शिकार बनता है।

सभापति महोदय : लागुरी जी, अगर आदिवासी एरिया में इंडस्ट्रलाइजेशन नहीं होगा तो उनको पिछड़ापन दूर कैसे होगा? अगर लोग कहेंगे कि हम नहीं बनाने देंगे तो आउटकम क्या होगा?

श्री यशवंत लागुरी: मैं उद्योग के विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं। ग्राम सभा की व्यवस्था में उद्योगपति कुछ वादे करते हैं और प्रक्रिया खत्म होने के बाद उद्योग लग जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई चैकिंग व्यवस्था नहीं है कि जो वादे किए थे उसे कार्यरूप में रूपांतरित किया गया है या नहीं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

सभापति महोदय: मैं सतपाल जी का उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर वे आगे आ जाएं, मैं इसकी अनुमति देता हूं ताकि उन्हें निकलने का मौका न मिले।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : महोदय, बिहार के दो दर्जन से अधिक जिले भयंकर जिले सूखे की लपेट में हैं। पटना, नालंदा, नवादा, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, सासाराम, भगुआ, बक्सर, आरा, सीतामढ़ी और शिवहर आदि जिलों सहित 28 जिलों में वर्षा के अभाव में धान का रोपण नगण्य है। धान की पौध खेतों में सूख रही है। भू जल स्तर काफी नीचे चला गया है।

पशुओं के लिए चारे की समस्या गहराती जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस जिले को सूखाग्रस्त कोष से विशेष धनराशि मुहैया कराई जाए। धन्यवाद।

सभापति महोदय : बिहार में कई जिले सूखाग्रस्त घोषित हुए हैं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): सभापति महोदय, मैं एक अति गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बाल श्रम हमारे सामने एक बहुत गंभीर चुनौती है। सदन में अनेकों बार इस विषय पर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन फिर भी हालात जहां के तहां हैं। हम दिल्ली की बात करें तो पिछले आठ-दस दिनों के भीतर हमने समाचार पत्रों में पढ़ा और देखा कि पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर में एक ढाबे में

काम करने वाले 14 वर्षीय बालक को बहुत प्रताड़ित किया जाता था। वहां की एक युवती ने साहस का परिचय देकर पुलिस चाइल्ड हैल्प लाइन को सूचना देकर उस बालक को मुक्त कराया।

इसी तरह से सीलमपुर में पांच कारखानों में छापा मारा गया और उन कारखानों से 21 बाल श्रमिक मुक्त कराये गये। उन मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की उम्र 13 वर्ष से कम थी। उन बच्चों से कास्मैटिक के कारखानों और कपड़ों पर जैली करने वाले कारखानों में काम कराया जाता था। कास्मैटिक कारखानों में काम करने पर उनके हाथों और पैरों में स्किन डिजीज भी हो जाती थी और काम करने से मना करने पर उन्हें बुरी तरह से पीटा भी जाता था। यह देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है।

अभी कॉमनवैल्थ गेम्स की तैयारियां चल रही हैं और उन गेम्स की तैयारियों के दौरान हमने देखा कि रोड्स के किनारे कई स्थानों पर बागवानी का काम करते हुए, गिट्टी उठाते हुए, मिट्टी डालते हुए बाल श्रमिक नजर आ जाते हैं। यह देश की राजधानी में हम सबकी आंखों के सामने हो रहा है। हम कहीं भी नजर डालें, हम संसद के एक-दो किलोमीटर के अराउंड कहीं भी जाएं तो हमें बाल श्रमिक काम करते हुए नजर आ जाते हैं।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की राजधानी में ये हालात हैं। हमने बाल श्रम अधिनियम बनाया है। लेकिन उस अधिनियम का पालन हम ठीक ढंग से राजधानी में नहीं करा पा रहे हैं तो देश के बाकी राज्यों में क्या हालात होंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार बाल श्रम को खत्म करने के लिए गंभीरता से पहल करे और बाल श्रमिकों की पहचान करके उन्हें मुक्त कराये जाने के साथ-साथ उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए तथा संबंधित क्षेत्रों में जहां बाल श्रमिक पाये जाते हैं, वहां श्रम विभाग के जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, उन्हें दंडित करने के लिए भी कदम उठाये जाएं। ताकि बाल मजदूरी प्रथा देश से पूरी तरह से खत्म हो सके। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Rahman Saheb, if you have some emergent work, then I can permit you to go, but you are enhancing the glory of this House.

SHRI N. KRISTAPPA (HINDUPUR): Mr. Chairman, Sir, I would like to bring a very important matter to the notice of the Government and the matter pertains to my parliamentary constituency in Kadiri Municipality of Anantpur District of Andhra Pradesh. One Shaik Ataullah went to Saudi Arabia for employment. He expired in Saudi Arabia on 11.5.2010. Mrs. Shaik Nawaji, his wife, requested the Indian Embassy in the Kingdom of Saudi Arabia for the release of his dead body to India. On 20.6.2010, I requested the Government of India to release the dead


body. On 22.6.2010, I received a letter from the Indian Embassy at Riyadh. The Government of Andhra Pradesh has also written a letter to the Indian Embassy at Riyadh on 7.7.2010 in this regard. In spite of completing all the formalities and after so many reminders to authorities, no action has been taken so far to release the dead body of the poor man and his family is shocked that even after completion of all formalities and lapse of about three months period, the body has not yet been released. It is unfortunate that there is too much delay on the part of the Government of India and the Indian Embassy at Riyadh that a poor family has to wait for such a long time to receive the dead body.

So I strongly demand a probe into the whole issue so that the erring officials are taken to task and request for the release of the dead body at the earliest.

18.35 hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS –Contd.

(ii)Re: Need to review the decision to accord environmental clearance to nuclear power plants to be set up in Chandrapur and Nagpur regions of Maharashtra

 श्री हंसराज ग. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

महाराष्ट्र में चन्द्रपुर मेरा निर्वाचन क्षेत्र है जो एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है। यहां की एक बहुत बड़ी समस्या विगत लोकसभा में भी उठा चुका हूँ जिसका कुछ असर भी हुआ था। यहां पर प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ है कि उसका कुछ अनुमान बताना चाहता हूँ। केन्द्रीय पर्यावरण और प्रदूषण बोर्ड ने भी उसकी एक रिपोर्ट बनायी है। उसने ऐसे दस शहरों को चुना है, उसमें मेरा चन्द्रपुर क्षेत्र भी है। चन्द्रपुर का क्रम देश के दस शहरों में से चौथे स्थान पर है। अभी प्रधानमंत्री जी यहां नहीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूंगा कि इस प्रदूषण से मेरे शहर चन्द्रपुर के नागरिकों का जीना हराम हो गया है और अनेक बीमारियों से पीड़ित हैं। अगर आज भी वहां कोई बच्चा पैदा होता है तो बीमार सा होता है... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Mr. Narayanasamy, please take a note of it. The point is very important. Please take it up with the Minister of Environment.

श्री हंसराज गं. अहीर: सभापति जी, इसके पहले भी चन्द्रपुर के बारे में अमरीका के नासा संस्थान की एक रिपोर्ट छपी थी। उसमें इसका उल्लेख हुआ है। उन्होंने ओजोन मॉनिटरिंग सिस्टम से यह रिपोर्ट बनायी थी कि यहां पर यानी चन्द्रपुर परिसर में एसिड के बादल होने की आशंका जतायी थी। इसके साथ जर्मनी की सैटेलाइट ने भी यह रिपोर्ट सरकार को भेज दी है कि यहां प्रदूषण के इतने प्रमाण होने के बावजूद यहां एक बड़ी घटना हो रही है। राज्य सरकार बार बार यहां पॉवर प्लांट लगाये जाने की अनुमति देती जा रही है। आज की स्थिति में देश का सब से बड़ा पॉवर प्लांट चन्द्रपुर में है जो 2400 मेगावाट बिजली पैदा करता है। इसके अलावा और भी छोटे पॉवर प्लांट्स यहां पर हैं। वहां सीमेंट के प्लांट हैं...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह मुम्बई से कितनी दूर है?

श्री हंसराज गं. अहीर: यह आन्ध्र प्रदेश के बॉर्डर पर नागपुर से आगे है। वहां कोयले की 27 बड़ी खानें हैं। बड़ी पार्टी की सीमेंट की इंडस्ट्रीज हैं, वहां कोल वाशरीज भी हैं। पेपर मिल भी है क्योंकि बांस का ज्यादा उत्पादन होता है। इसके अलावा स्टील प्लांट्स भी हैं। हम इतनी सारी इंडस्ट्रीज का विरोध नहीं करेंगे। जितनी इंडस्ट्रीज वहां हैं, वे सब कोल बेस्ड हैं। वहां करीब 60 हजार मीट्रिक टन कोयला हर रोज उस ऐरिया में जलता है और इन सारी बातों को सुनकर हमने श्री जयराम रमेश, पर्यावरण मंत्री जी से विनती की थी। उन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी में विज़िट की थी। इसके बाद वहां के जितने एनजीओज हैं, उन से मीटिंग की और फिर यह निर्णय लिया था कि इसके बाद यहां एक भी उद्योग नहीं लगाया जायेगा। माननीय मंत्री जी ने हमें वहां आश्वस्त किया था कि नया पावर प्लांट जो कोल बेस्ड होगा, नहीं लगाया जायेगा और अनुमति देने से पहले जितने प्रस्ताव होंगे, उन पर पहले विचार किया जाएगा और जितने प्रस्ताव आये हैं, उन्हें ठंडे बस्ते में रख दिया जायेगा।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के कहने के बाद भी कई निजी पावर प्लांट लगाये जाने की अनुमति मिली है। वहां ऐसे चार निजी पावर प्लांट का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने ऐसे 26 और पावर प्लांट लगाये जाने के प्रस्ताव भेजे हैं। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। वहां के नागरिकों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे वहां इसके गम्भीर परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इससे वहां वाटर पोल्यूशन होगा, अगर एक ही नदी पर 25-25 पावर प्लांट बनायेंगे तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। इसलिये मैं

आपके माध्यम से सरकार से विनती करूंगा कि वहां पर कोई नया पॉवर प्लांट न आये। मेरे जिले में किसी और जगह पर पॉवर प्लांट लगाया जा सकता है, जिसे राज्य सरकार भेजे। मेरे क्षेत्र में 70 किलोमीटर की दूरी पर नदी है...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अहीर जी, हमारे क्षेत्र में एक पॉवर प्लांट रुका है, उसके लिये आन्दोलन हो रहा है। हमारे वहां भी कोयला ज्यादा है।

श्री हंसराज गं. अहीर :महोदय, मैं सरकार से और पर्यावरण मंत्री जी से विनती कर रहा हूं कि इसके बाद वहां किसी भी पावर प्लांट को एनओसी, मान्यता न दें। मैं आपके माध्यम से यह विनती करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS
(SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman, Sir, you are kind enough to observe that. It is because, he has mentioned that the power plants are coming there and, therefore, environmental problem is being faced, I will convey the sentiment of the hon. Member, as far as Chandrapur is concerned, to the Environment and Forests Minister to look into the matter and try to ensure that the environmental pollution is not there in that area.

श्री गणेश सिंह (सतना): महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। कई दिनों के बाद शून्यकाल शुरू हुआ है। मैं अध्यक्ष महोदया, का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों का निवेदन स्वीकार किया।

सभापति महोदय : गणेश जी, मैंने प्रयास किया है कि शून्यकाल में सब कुछ शून्य न हो जाये, इसीलिए मैं किसी को भी जाने नहीं दे रहा हूं।

श्री गणेश सिंह: महोदय, मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। लगातार यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से देश के विभिन्न क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया जाता रहा है, लेकिन जो वास्तविक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग की है, उसी के तहत अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में विशेष पैकेज की जो मांग की गयी है, वह पूर्णतया:

उचित है। प्रधानमंत्री जी को इस पर गहराई से विचार करना क्योंकि विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र देश के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है, जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके साथ-साथ वहां कई महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल मौजूद हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण इन दोनों क्षेत्रों का ठीक से विकास नहीं हुआ है। इन क्षेत्रों में लगातार गरीबी बढ़ रही है। इसके साथ-साथ वहां बुनियादी सुविधाएं भी न के बराबर हैं। राज्य सरकार अकेले अपने संसाधनों से इन क्षेत्रों का विकास करने में सक्षम नहीं हो सकती है, लिहाजा मैं भारत सरकार से इन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज देने की मांग करता हूं। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट कराना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 87 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां करोड़ों की आबादी है, जहां के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, वहां के बारे में हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं पुनः विशेष रूप से उन क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष पैकेज की मांग करता हूं।

सभापति महोदय: आप हंसराज जी से थोड़ा समझौता कर लें तो दोनों की तकलीफ दूर हो जायेगी।

श्री गणेश सिंह : मैंने हंसराज जी से निवेदन किया है कि आप वहां से इंडस्ट्री हटा रहे हो और हम लोग मांग रहे हैं।

श्री के.डी. देशमुख (बालाघाट): महोदय, मैं गणेश सिंह जी के भाषण से अपने को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अच्छा, ठीक है।

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, मेरा अलग मुद्दा भी है। मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट और सिवनी जिले से लोकसभा सदस्य चुनकर आया हूं। उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर 4 लेन जबलपुर से नागपुर एन.एच. मार्ग स्वीकृत है। यह मार्ग लखनादौन से सिवनी तक बन चुका है। करोड़ों रूपया खर्च होकर 4 लेन मार्ग बन चुका है। मगर सिवनी से खवासा, जो नागपुर मार्ग पर पड़ता है, यह बीस-बाइस किलोमीटर का जो पोर्शन है, इसे ठेकेदार ने छोड़ दिया है। उसने काम बंद कर दिया है। उस पर रोक लग गयी है। छिंदवाड़ा के एनजीओ ने उच्चतम न्यायालय में स्टे लगा दिया है कि इस काम को प्रारम्भ न किया जाये। जहां करोड़ों रूपये खर्च हो चुके हैं, यह प्रमुख मार्ग है।

महोदय, यह कहते हैं कह यह शेरशाह सूरी के जमाने का मार्ग है। जब शेरशाह सूरी का शासन था, उस समय मध्य प्रदेश में एक ही मार्ग था। सिवनी जिला वैसे भी पिछड़ा हुआ जिला है। जबलपुर से सिवनी

और शिवनी से नागपुर जाना होता है। वन्य प्राणियों का आवागमन अवरूद्ध होता है, टाइगर को नुकसान होता है, इसलिए एनजीओ के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी है।

इस मार्ग का काम एक साल से बंद है। शिवनी की जनता आंदोलन कर रही है, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस मार्ग को प्रारम्भ किया जाए। इस मार्ग को यदि शुरू नहीं करना था तो बनाना ही नहीं चाहिए था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एनजीओज़ तो इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जाते रहेंगे और राजमार्ग का काम रुका रहेगा। शिवनी जिले के लोगों को चिकित्सा के लिए जबलपुर या नागपुर जाना होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में जाए और उस मार्ग को प्रारम्भ करने में मदद करे। यदि सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी तो यह मामला वर्षों तक लंबित पड़ा रहेगा।

सभापति महोदय : धरना प्रदर्शन होने और उसकी पब्लिसिटी होने से कोर्ट पर भी उसका असर पड़ता है।

श्री के.डी. देशमुख : महोदय, एक बार शिवनी जिला बंद हुआ था। लेकिन हम लोग मारकाट नहीं कर सकते हैं क्योंकि शिवनी बहुत शांतिपूर्ण जिला है और पिछड़ा हुआ है।

DR. KIRIT PREMJI BHAI SOLANKI (AHMEDABAD WEST): Respected Chairman, Sir, I would like to thank you for providing an opportunity to speak on a very vital issue.

We observe that there is injustice to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes so frequently. I would like to draw the attention of the House, through you, Sir, that there is a speculation that through the Central Government, the injustice is being done to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes. I would like to draw the attention of this House to a move of our HRD Ministry.

The Ministry of Human Resource Development is known to make many innovative experiments, and this Ministry has achieved many good results also. But probably, because of some over enthusiasm or pro-activeness, this Ministry is making a University Innovation Bill. The HRD Ministry has prepared a draft Bill on this and it has been circulated among the experts. I am getting pained to say that in this draft Bill, the HRD Ministry has not mentioned about the reservation

for SCs, STs and OBCs. It has talked about the merits only. These innovative Universities will be set up either by public or by private or by PPP mode.

This draft Bill has not mentioned about a clear-cut reservation but it has insisted that it will be strictly on the basis of merit. It says:

“This University shall be open to all the persons irrespective of nationality, gender, caste, creed, disabilities, ethnicity, social or economic ground.”

This draft Bill has been circulated among the experts. I would request the Government of India, through you, Sir, to make necessary changes in this draft Bill for keeping a provision for reservation of SCs, STs and OBCs in this Bill as per the rules of the Government.

As I am coming from Ahmedabad, Gujarat, I would also request the Government of India that if this University Innovation Bill is passed, then one such University should be installed in Ahmedabad, Gujarat. Thank you.

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Sir, I associate myself with him on this issue.

SHRI T.K.S. ELANGO VAN (CHENNAI NORTH): Sir, I also associate myself on this issue.

MR. CHAIRMAN: All right, your names would be associated.

SHRI M.B. RAJESH (PALAKKAD): Mr. Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government in regard to the miseries of Non-Resident Keralites due to lack of adequate travel facilities in this season of Onam and Ramzan.

Thousands of families of Non-Resident Keralites are worried that their kith and kin would not be able to join them in the festival celebrations due to the utter neglect of the Indian Railways and the Air India.

Sir, I can cite a number of examples of the discrimination done by the Railways towards Kerala. In this festive season, the Railways have not introduced a single special train between Chennai and Trivendrum. Further, compared to last year, 10 special trains from Chennai to other parts of Kerala have been cancelled.


From Mumbai, where lakhs of Keralites are working to earn their livelihood, no special train has been announced till date. In the past though there were some special trains from Delhi yet all those trains were stopped in the recent years. Similarly, Bangalore is another city from where additional trains are desperately needed.

Sir, Southern and Western Railway Authorities have not yet announced any special trains in this festive season.

Moreover, there has not been a slightest of improvement in the services of the Air India between Gulf countries and Kerala. The condition is pathetic. Abrupt cancellations, indefinite delays, callousness and negligence have become the normal feature of the Air India's services between Gulf countries and Kerala.

Although there has always been a demand for additional flights during the festive season, yet the Air India never responded to it. Instead, they always charged exorbitant fares from passengers. The Air India Authorities see the festive season as an opportunity to exploit passengers. They are not even ready to operate A-321 aircraft on this route, which could carry more passengers.

Therefore, in these circumstances, I would request the Government to intervene and ensure that adequate additional trains and flights are provided to Kerala in this festive season.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, मैं आपसे खास कर अनुरोध करता हूँ, हमारे अंडमान और निकोबार के दो अम्बेसेडर यहां बैठे हैं - श्री पवन कुमार बंसल जी और श्री नारायणसामी जी। मैं अंडमान और निकोबार का एमपी हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट का एम.पी. नहीं हूँ। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह ऐसा फोरेस्ट है, जो भारत के लिए ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के लिए एसेट है। उस फोरेस्ट में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो  फोरेस्ट सर्विस में एससीएफ हैं, वे लोग करीब-करीब 26 साल से काम कर रहे हैं। कोई-कोई एससीएफ करीब पांच साल से डीएफओ पद में वन विभाग में काम कर रहा है। उनके साथ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पे-कमीशन में इनजस्टिस किया गया।

सरकार कहती है कि जो एससीएफ है, वह डिपार्टमेंट पुलिस के डीएसपी के रैंक के बराबर है। ऑल इंडिया फोरेस्ट सर्विसेस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका टाइम स्केल के मुताबिक हर चार साल

बाद प्रमोशन होता है और उन्हें फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे-कमीशन का बेनिफिट भी मिला है। इस परिणामस्वरूप अंडमान फोरेस्ट सर्विसेस में जो लोग काम करते हैं, एससीएफ, स्टेट फोरेस्ट सर्विस में बीस साल काम करने के बाद भी उनका प्रमोशन नहीं होता और न ही उन्हें कोई बेनिफिट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पे-कमीशन में मिला है। इसलिए उनके दिल और मन में बड़ी चुभन शुरू हो गई है। इसी मुताबिक अपने प्रशासन अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में स्टेट फोरेस्ट सर्विस एसोसिएशन एनोमली कमेटी में गया था, अंडमान-निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी तकलीफ को देखते हुए, उनके अधिकार को ठीक समझते हुए एनोमली कमेटी ने रिकोमेंडेशन भारत सरकार को भेजी। उन रिकोमेंडेशंस को मान कर उसे मिनिस्ट्री ऑफ फोरेस्ट में भेजा ताकि उन्हें उनके बराबर पे-स्केल 1 जनवरी, 2006 से मिले। सिक्स्थ पे-कमीशन में जो डिस्पेरिटी है, उसे दूर किया जाए।

सभापति महोदय, मेरी आखिरी एक और मांग है कि जो आईएफएस भारत के विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अंडमान में जो स्टेट फोरेस्ट सर्विसेस के अधिकारी हैं, उन्हें इंडियन फोरेस्ट सर्विसेस के अधिकारी के समान पैरिटी मिले। मैं फिर से अनुरोध करूंगा, हमारे दो-दो अम्बेसेडर यहां बैठे हैं, बंसल जी और नारायणसामी जी, कृपा करके इस बात को सरकार के पास पहुंचाएं। इस बारे में मैंने संबंधित मंत्री जी से मुलाकात भी कर ली है और उनसे बात भी की है और उन्हें पत्र भी दिया है। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप मेरी बात को उन तक पहुंचा दें।

सभापति महोदय : आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया।

श्री विष्णु पद राय : नारायणसामी जी, आपने कुछ बोला नहीं।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): मैंने आपकी पूरी बात सुनी है।

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Mr. Chairman, Sir, thank you for giving me an opportunity.

I would like to invite the attention of this august House to the miseries and problems faced by the passengers of our national air carrier due to unjustifiable delay, cancellation and withdrawal of flights in the Middle East-Kerala sector. Within the short span of last one month, several incidents of flight cancellation and indefinite delay repeated with the Air India flights. These were creating harsh protest among the passengers who were held up in various airports, after booking tickets to reach their hometowns and work places.

On last July 30, 159 passengers bound for Doha and Bahrain were stranded at the Thiruvananthapuram International Airport at night after an Air India Express flight was grounded. The flight was grounded owing to shortage of cabin crew, enforcement of certain regulations of the Director-General of Civil Aviation and delay in arrival of the incoming flight.

IC 457 Kochi-Thiruvananthapuram-Bahrain-Doha flight, scheduled to depart from Kochi at 7.05 p.m. on Friday with 61 passengers, could commence the service only at 11.30 p.m. from the Cochin International Airport at Nedumbaserry. Ninety-nine more passengers boarded that aircraft in Thiruvananthapuram when the flight landed here at 12.15 a.m. But unfortunately, thereafter, the flight departed from Thiruvananthapuram Airport after 48 hours. There is no need to describe the mental harassment suffered by the passengers and bad consequences they were forced to face after the two days delay in the prior scheduled programmes.

Allegations are levelled that the entire lapse is taking place deliberately to help the private airlines operating in the same sector.

Also, it was unfair decision of the Air India to cancel three Air India Express flights from Thiruvananthapuram International Airport to Gulf countries and to cause undue delay and cancellation of flights to Gulf countries from Kerala and *vice-versa*. Now, the Air India management has decided to stop the service of Air India Express flights to Dubai, Sharjah and Abu Dhabi from next month. If they are cancelled, it should be adversely affecting a large number of NRIs employed in those countries. Also, this decision will help the private airlines operating from the Gulf sector to Kerala to hike their airfare to Kerala extremely and it has come as a big blow to the hundreds of NRIs. In fact, the Air India Express service was a great relief to the NRIs because of the lowest air fares and convenient timings.

Many of the passengers, who have booked tickets, due to these delays or cancelled flights, might even lose their jobs if they fail to get at their workplace in time.

Acute shortage of cabin crews is the cause for the cancellation and delay of flights, and the Civil Aviation Ministry should take necessary action to reinstate the cancelled services urgently as it is a serious issue, which will be affecting a large number of NRIs from Southern States of India. Also, the Government should give necessary direction for sufficient staff recruitment to inevitable posts for smooth operations of aircraft from Gulf-Kerala sector. Thank you, Sir.

श्री बद्रीराम जाखड़ (पाली): सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सदन में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया है। मैं जिस एरिया से आता हूँ वह राजस्थान का पाली क्षेत्र है। पाली की जनता पूरे भारत में रहती है। मैंने इस संबंध में रेल मंत्री जी से मिला था और मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि पाली से दिल्ली के लिए इंटरसिटी की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जाए और दिल्ली से पाली के लिए एक इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाई जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे क्षेत्र की जनता मजदूरी के लिए विशेष रूप से चेन्नै, पूना, हैदराबाद और मुम्बई रहती है, उसे पाली आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। वहां के लिए केवल हफ्ते में केवल एक ट्रेन चलती है। मैं करता हूँ कि उसे पूरे हफ्ते रोजाना चलाया जाए। चेन्नै से चलने वाली गाड़ी नं. 2526, हैदराबाद से चलने वाली गाड़ी नं. 3738, पूना से चलने वाली गाड़ी 1089 और 1090 हैं, उन्हें पूरे सप्ताह, यानी रोजाना चलाया जाए।

महोदय, मैंने एक नई रेल लाइन बर-बिलाडा के लिए भी मांग की है और मंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सर्वे करा रही हूँ और जल्दी से जल्दी सर्वे को पूरा किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि इसके सर्वे के लिए 30 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इसके लिए एक भी पैसा स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि इस लाइन का शीघ्र सर्वे कराया जाए और उसे रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। इससे जनता को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक नई रेलवे लाइन पीपाड़ सिटी से वाया भोपालगढ़ होती हुई, आसोप होती हुई, मुंडवा और नागोर के लिए बनाने की मांग की है।

19.00 hrs.

इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से कहना चाहूंगा, नारायण स्वामी जी सुन रहे हैं, ये हमारी बात का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि हमारे बहुत से लोग बाहर रहते हैं, लम्बे टाइम से वह मजदूरी के लिए जा

रहे हैं, इसलिए लोगों को आने-जाने की बड़ी तकलीफ है। रेलवे की कैपेसिटी 650 है और वेटिंग लिस्ट 900 आ रही है, यह स्थिति है। स्वामी जी, आपको हमारा पूरा ध्यान रखना है और हमारे एरिया की मांग आपको रेल मंत्री से पूरी करानी है। जयहिन्द-जयभारत।

डॉ. राजन सुशान्त (कांगड़ा): सम्मानित सभापति जी, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल अवशेष संशोधन एवं विधिमाम्यकरण अधिनियम, 2010 लागू होने से 100 मीटर तक निर्माण कार्य पर पूरा प्रतिबन्ध और उससे आगे 200 मीटर तक नवनिर्माण, पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्य सक्षम अधिकारी की अनुमिति से आवश्यक हो गये हैं, अन्यथा निर्माण अवैध होगा तथा दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आ जायेगा।

इस प्रकार का संरक्षण दिल्ली में लाल किला तथा आगरा में ताजमहल जैसी अति-विशिष्ट एवं सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों पर लागू करना तो शायद उचित होगा, परन्तु हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में यह सर्वथा उचित नहीं है। हमारे क्षेत्र में नूरपुर, चम्बा, कांगड़ा, बैजनाथ, भरमौर, किन्नौर, शिमला, सिरमौर सब जगह हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ये छोटे-छोटे कस्बे हैं, 1-1 किलोमीटर के शहर हैं। इससे लोग पूरी तरह से स्तब्ध हो चुके हैं। यह मौलिक अधिकारों का यह हनन है तथा संविधान का गला घोंटा गया है। यह कल्याणकारी राज्य की परिभाषा का अपमान है। एक व्यक्ति, जो पूरे जीवन की पूंजी तथा खून-पसीने की कमाई से एक मकान बनाता है, उसे अवैध करार दिया जा रहा है। सभी सरकारी विभाग भी इससे विस्थापित हो जाएंगे, चाहे कार्यपालिका के हों, चाहे न्यायपालिका के हों, क्योंकि निर्माण व मरम्मत के नाम पर एक भी ईंट नहीं लगाई जा सकती है।

मैं इस तुगलकी फरमान की घोर निन्दा करता हूँ तथा सरकार से पुरजोर अपील करता हूँ कि इसे जनकल्याण के हित में जल्दी से जल्दी वापस ले लिया जाये।

श्री सतपाल महाराज (गढ़वाल): सभापति जी, मैं इनके साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ।

सभापति महोदय : आप अपनी-अपनी स्लिप टेबिल पर भेज दीजिए, आपका नाम उसमें एसोसिएट हो जायेगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल साहब, एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो मुद्दा आपने उठाया है, वह मुद्दा अभी हुक्मदेव नारायण जी ने अभी उठाया है, जो कॉमनवैल्थ गेम्स हैं, उसी के बारे में आपका है न, अगर आप चाहें तो अपने आपको इसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं।

श्री बदरुद्दीन अजमल : आप एसोसिएट कर दें, लेकिन एक-दो लफ्ज़ तो बोलने दें। सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरी एक तो आप सबसे यही गुजारिश है

कि हाउस में कम से कम इस किस्म के इम्पोर्टेड मैटर, जो पूरे हिन्दुस्तान के नुमाइन्दे लेकर आते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ टाइम मिलना चाहिए, इसमें बड़ी कमी हो रही है।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप देखते हैं कि मैंने किसी के टाइम में कटौती नहीं की।

श्री बदरुद्दीन अजमल : आज पहली मर्तबा मैं समझता हूं, मुझे मौका मिल रहा है। नम्बर दो-क्वश्चन आंसर के टाइम पर हाउस में जो हंगामा होता है, उसके लिए सारे साथियों से मेरी रिक्वैस्ट है कि कम से कम इस एक घंटे को माफ करें, उसके बाद चाहे जो करें। कम से कम पूरे हिन्दुस्तान के लोगों की जरूरत होती है, पता नहीं, लोग कैसी-कैसी डिमांड लेकर आते हैं, कैसे-कैसे क्वश्चंस होते हैं, लेकिन उसको ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अजमल साहब, यह बात आप सुबह 11 बजे कहिएगा तो ज्यादा असर पड़ेगा।

श्री बदरुद्दीन अजमल : सुबह कहने का मौका ही तो नहीं मिलता। इतने दिनों से यही तो हो रहा है कि बैठे हुए हैं, लेकिन मौका नहीं मिलता।

मैं अपनी बात पर आ रहा हूं कि यह जो खेल का मसला है, हमारे हिन्दुस्तान में देखिये, इंसान की सेहत अगर तन्दरुस्त नहीं होगी, मुल्क का नौजवान अगर तन्दरुस्त नहीं होगा तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। कॉमनवैल्थ गेम एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, पूरे मुल्क को इसका इन्तजार था कि यह बहुत अच्छे तरीके से होंगे, कामयाब होंगे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। वे बाहर से जाकर मैडल नहीं ला पाते हैं, यहां बड़े-बड़े मैडल लाएंगे तो पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम होगा, लेकिन अफसोस की बात है, अर्जेंट मैटर में मैंने इसे इसलिए दिया कि आज ही पेपर में पढ़ा कि सिर्फ दो महीने बाकी हैं और 36 डिपार्टमेंट्स में अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा न हो कि खेल-खेल में, चूंकि यह खेल का मामला है, खेल-खेल में सारे हराम हलाल हो जायें। मैं आपकी तवज्जह चाहूंगा कि खेल-खेल में ये सारे हराम हलाल हो जायें, इसलिए इसके ऊपर मेरी दरखास्त है कि ध्यान दिया जाये। प्राइम मिनिस्टर साहब के खुद के अपने आफिस से, मैडम के यहां से बाकायदा निगरानी हो और जो लोग इस घपले में लिप्त पाये जायें, उनको माफ न किया जाये। पूरी दुनिया में इसकी बदनामी हो रही है। यह हमारे घर का गेम नहीं है, कॉमनवैल्थ गेम है। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, ऐसा न हो कि किसी को छोड़ दिया जाये।

आखिर में, जो लोग घपलेबाजी कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि देखो ए दीवानों, तुम ये काम न करो, खेल का नाम बदनाम न करो। अपने देश की इज्जत रखो, देश का ख्याल रखो। जय हिन्द, जय भारत।



MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again at 11 a.m. on Friday, 6th August, 2010.

19.06 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Friday, August 6, 2010/Sravana 14, 1932 (Saka).*

